{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
शनिवार 25 जुलाई 2026
आषाढ़ शुक्ल 11 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 301
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

सेंसेक्स	-	76,059.77
निफ्टी	-	23,767.45
सोना	-	1,52,621
चांदी	-	2,35,000
डॉलर	-	96.37

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

खास खबर

प्रीमियम पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट नहीं होगी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले प्रीमियम पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण नहीं किया जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सदन में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सरकार के अनुसार, इंडियन ऑयल का एक्सपी100, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर100 और भारत पेट्रोलियम का स्पीड100 जैसे प्रीमियम पेट्रोल पूरी तरह इथेनॉल-मुक्त रहेंगे। इन प्रीमियम ईंधनों की देश में कुल पेट्रोल बिक्री में हिस्सेदारी लगभग 0.5 प्रतिशत है। मंत्री ने यह भी बताया कि सामान्य पेट्रोल में ई10 (10% इथेनॉल मिश्रण) और ई20 (20% इथेनॉल मिश्रण) की आपूर्ति को लेकर सरकार की नीति पहले की तरह जारी है। हालांकि, ई20 से अधिक इथेनॉल मिश्रण लागू करने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मणिपुर में पेट्रोल पंप विस्फोट मामले में उग्रवादी गिरफ्तार

इंफाल। 24 जुलाई मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में मोइरांग स्थित पेट्रोल पंप पर हुए बम विस्फोट के सिलसिले में प्रतिबंधित संगठन कांगलेई यावोल कन्ना लुप (केवाईकेएल) के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 39 वर्षीय मयांगलंबम तोंबा सिंह को बिष्णुपुर की तेरा उरक जांच चौकी से पकड़ा गया। वह चुराचांदपुर जिले के बिजांग खुनौ का निवासी है और वर्तमान में फुबाला राहत शिविर में रह रहा था। उसके पास से मैगजीन सहित नौ मिलीमीटर की पिस्तौल और अलग-अलग बोर के 11 कारतूस बरामद हुए हैं। सिंह पर इस साल की शुरुआत में मोइरांग के पेट्रोल पंप पर हुए विस्फोट में शामिल होने का आरोप है, जिसमें सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ था। सुरक्षा बलों ने एक अलग अभियान में प्रतिबंधित यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी (यूकेएनए) के संदिग्ध वित्त प्रमुख एस. पलाल कुकी को भी गिरफ्तार किया है। कुकी को चुराचांदपुर जिले के मोलनोम से गिरफ्तार किया गया।

झेलम का जलस्तर घटने से जम्मू-कश्मीर को राहत

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात के बीच शुक्रवार को राहत की खबर सामने आई। झेलम नदी के प्रमुख गेज स्टेशनों पर जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे फिलहाल श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने 28 जुलाई से एक बार फिर भारी बारिश और संभावित बाढ़ की चेतावनी जारी की है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार राम मुंशी बाग में झेलम का जलस्तर 19.07 फीट दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 21 फीट से नीचे है।

कुछ ना कहना

एनटीए में बड़ी कार्रवाई : 47 अधिकारी किए गए बर्खास्त, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की तैयारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी - एनटीए ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई परीक्षा संचालन में जवाबदेही तय करने और एजेंसी की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के व्यापक सुधार अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि यह प्रक्रिया अभी यहीं नहीं रुकेगी और आगे भी एजेंसी में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि हाल के महीनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों, अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद केंद्र सरकार लगातार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रही है। इसी क्रम में एजेंसी के भीतर जवाबदेही तय करते हुए यह सख्त फैसला लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों का विश्वास फिर से कायम हो सके। इससे पहले भी केंद्र सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में प्रशासनिक फेरबदल कर चुकी है। नए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने और परीक्षा संचालन की निगरानी बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के इस अभियान के बीच सरकार का जोर ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करने पर है, जिसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता हों। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के ढांचे और संचालन में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया जारी है।

नीट पेपर लीक मामले में हटाए गए उच्च शिक्षा सचिव

नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को उच्च शिक्षा सचिव के पद से हटा दिया है। उन्हें पंचायती राज मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर नरेश कुमार गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है, जबकि टी.के. अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विनीत जोशी 30 जून को संजय कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च शिक्षा सचिव के साथ-साथ स्कूली शिक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। उनके तबादले के बाद शिक्षा मंत्रालय की दोनों प्रमुख जिम्मेदारियां अलग-अलग अधिकारियों को सौंप दी गई हैं। विनीत जोशी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के पहले महानिदेशक (डीजी) रहे हैं। वर्ष 2017 में इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए एनटीए की स्थापना की गई थी और 2018 में उन्हें इसका पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने वर्ष 2021 तक इस पद पर कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान जेईई, नीट, सीयूईटी और यूजीसी जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं का संचालन एनटीए के माध्यम से हुआ। हालांकि बाद के वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों के कारण एजेंसी लगातार सवालों के घेरे में रही।

विनीत जोशी इससे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्ष 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद उन्हें राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें फिर केंद्र में शिक्षा मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी दी गई। सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल को नीट पेपर लीक विवाद और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मंत्रिपरिषद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से किया मंजूर

मोदी कैबिनेट से रवनीत बिट्टू का इस्तीफा

- राष्ट्रपति ने मंजूर किया इस्तीफा, मंत्री पद छोड़ा।
- अब पंजाब की राजनीति में निभा सकते हैं बड़ी भूमिका।
- मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज।

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा स्वीकार किया। हालांकि, इस्तीफे के पीछे की विस्तृत वजह आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं। वह पहले कांग्रेस में रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार में उन्हें रेल मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हाल के दिनों में पंजाब की राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका भी चर्चा में रही थी। रवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद में उनके स्थान पर किसे जिम्मेदारी सौंपते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक बदलावों से भी जुड़ा हो सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई अतिरिक्त आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली में पहली फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले और अन्य परीक्षा घोटालों को लेकर देश भर में जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच न्याय व्यवस्था ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं की त्वरित सुनवाई के लिए पहली विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इस विशेष अदालत की कमान अनुभवी न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बलीगा को सौंपी गई है, जो बतौर विशेष न्यायाधीश इन मामलों का फैसला करेंगी।

अनु ग्रोवर बलीगा दिल्ली न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) की वरिष्ठ अधिकारी हैं। वह राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थापित इस फास्ट-ट्रैक कोर्ट में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगी। यह नियुक्ति हाल ही में लागू हुए पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी और पेपर लीक जैसे आपराधिक मामलों में तेज न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। जज अनु ग्रोवर बलीगा को दिल्ली की जिला अदालतों में काम करने का 10 से अधिक वर्षों का लंबा अनुभव है। वह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडिशनल सेशंस जज) और साउथ-ईस्ट दिल्ली जिला कोर्ट में जिला न्यायाधीश (कमर्शियल) के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में जज-इन-चार्ज के तौर पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है।

सीजेपी-सरकार वार्ता : प्रधान के इस्तीफे पर गतिरोध बरकरार

मुआवजा और केस वापसी पर बनी सहमति

नई दिल्ली। नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई। दो घंटे चली वार्ता में जहां केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने और प्रभावित छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने पर सहमति जाहिर की है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सीजेपी की प्रमुख मांग पर गतिरोध बना हुआ है। मोदी सरकार ने इस संवेदनशील मुद्दे पर आंतरिक चर्चा के लिए शनिवार तक का समय मांगा है। संविधान क्लब में हुई बैठक में एनडीए सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए, जबकि सीजेपी की ओर से मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने प्रतिनिधित्व किया। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने साफ किया कि वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इस उन्होंने अपनी तीन मुख्य मांगों में से पहली और सबसे जरूरी बताया। सीजेपी ने नीट पेपर लीक के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा और आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज कानूनी मामले वापस लेने की मांग की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सीजेपी ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पांच सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा, हम लोगों ने इन पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है। नड्डा ने पुष्टि की कि शुक्रवार की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर आंतरिक चर्चा के बाद मोदी सरकार शनिवार दोपहर को सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक करेगी। यह बैठक तब समय हुई है जब नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन चल रहा है। दोनों पक्षों के बीच लंबे गतिरोध के बाद शुरू हुई बातचीत की इस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अनशन खत्म, लेकिन वांगचुक ने छोड़े कई सवाल

आंदोलन अब संसद और जवाबदेही की राह पर

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवाल अब भी कायम हैं। सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने आंदोलन को विराम दिया है। वांगचुक के इस फैसले को एक ऐसे मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, जहां सड़क पर चल रहा विरोध अब संसद में बहस और नीतिगत बदलाव की मांग तक पहुंच गया है।

वांगचुक ने अनशन खत्म करने के बाद कहा कि उनका उद्देश्य केवल विरोध दर्ज कराना नहीं था, बल्कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना था जिसमें छात्रों को बार-बार परीक्षा संबंधी अनिश्चितताओं और गलतियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मिले आश्वासन में छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं करने, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने की बात शामिल है। इस आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा छात्रों पर पड़ने वाला असर रहा है। पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत, समय और भविष्य प्रभावित होता है। वांगचुक ने इसी चिंता को केंद्र में रखते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की थी। उनका कहना है कि केवल दोषियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे दोबारा इस तरह की स्थिति पैदा न हो।

वांगचुक ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पूरी नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने इसे आंदोलन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं बताया। उनके मुताबिक, सबसे जरूरी यह है कि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए और परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल हो। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के पद छोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदारी तय करना है।

सुप्रीम कोर्ट- बिना इजाजत नहीं कर सकते कोर्ट वीडियो का इस्तेमाल या मोनेटाइज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड और ऑनलाइन सुनवाई की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के अनाधिकृत उपयोग पर कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने नए अंतरिम निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि संबंधित अदालत की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी किसी भी रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, अपलोड, प्रसारित, रीपोस्ट, संशोधित या मोनेटाइज नहीं किया जा सकेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने अदालत की कार्यवाही के वीडियो के अनाधिकृत इस्तेमाल और मोनेटाइजेशन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल या संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की पूर्व अनुमति के बिना लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश वैध समाचार रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने अपने सेक्रेटरी जनरल और सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश को संबंधित अदालतों की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब मांगा है, और केंद्र सरकार से याचिका में उठाई गई मांगों की जांच करने को कहा है। पीठ ने सभी हाईकोर्ट से भी लाइव स्ट्रीमिंग को विनियमित करने वाले नियमों और निरंतर लाइव स्ट्रीमिंग व्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी है।

पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की हरी झंडी, 27 जुलाई को होगा संसद में पेश

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण विधेयक पर मुहर लगी। माना जा रहा है कि बिल को 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। यह फैसला तब आया है जब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से जुड़े वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं है और यह लाखों छात्रों तथा उनके अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है।

पीएम ने दिया संदेश बोले- पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई होगी

नई दिल्ली। पेपर लीक के मुद्दे पर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात देश के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, बल्कि इससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और दोषियों के खिलाफ अब तक की कार्रवाई से आगे बढ़ते हुए और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानूनी व्यवस्था तैयार करने के प्रस्ताव पर अगले दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई महीनों में सामने आई पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने कई स्तरों पर कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और मामले की जांच लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। इसी उद्देश्य से कम समय में लगभग 22 लाख विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षाएं आयोजित कराई गईं। उन्होंने बताया कि 19 तारीख को परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं और देशभर से सफल विद्यार्थियों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को पेपर लीक से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए थे। विभागों ने देर रात इस संबंध में मसौदा तैयार कर सरकार को सौंप दिया है। प्रस्तावित व्यवस्था में फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ-साथ दोषियों के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान रखा गया है, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

ईडी का एक्शन, दिल्ली-यूपी और पंजाब में आठ ठिकानों पर छापेमारी

-यह कार्रवाई 450 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में की

नई दिल्ली। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एम/एस संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ शुक्रवार को कई स्थानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई करीब 450 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में की गई।

ईडी सूत्रों के मुताबिक यह जांच सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के आधार पर की जा रही है। आरोप है कि संतोष ओवरसीज लिमिटेड ने बैंकों के एक कंसोर्टियम से करीब 450 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। जांच में सामने आया है कि इस लोन की राशि को फर्जी कंपनियों, एंट्री ऑपरेटरों और संबंधित संस्थाओं के नेटवर्क के जरिए इधर-उधर किया गया। इसके लिए, फर्जी बिल और सर्कुलर वित्तीय लेनदेन का सहारा लिया गया ताकि पैसों की असली आवाजाही को छिपाया जा सके।

ईडी ने इस मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में स्थित आठ ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इन स्थानों में कंपनी के प्रमोटरों, उनसे जुड़ी कंपनियों और कथित सहयोगियों के परिसरों को शामिल किया है। तलाशी की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और मामले की आगे की जांच जारी है। बता दें इससे पहले 20 जुलाई को भी ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने एक बड़े फर्जी डिग्री और जाली शैक्षणिक दस्तावेज मामले में कार्रवाई की थी। उस दौरान एजेंसी ने 25.44 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था।

अटैच की गई संपत्तियों में एक फार्महाउस, कई फ्लैट और वाहन शामिल थे। यह जांच यूपी एसटीएफ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ था कि हापुड़ स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी के नाम पर एक बड़ा गिरोह फर्जी डिग्री और शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि यह गिरोह फर्जी मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज तैयार करने, बेचने और उनकी फर्जी पुष्टि कराने का अवैध कारोबार चला रहा था।

महज सरकारी कागजों मे हो रहा वाटर हार्वेस्टिंग नियम का पालन, धरातल पर नियमो की उड़ाई जा रही धज्जियां

शासकीय कार्यक्रम और भाषणों तक सिमट कर रह गया जल संरक्षण अभियान, नगरी क्षेत्र में 1300 मकानों में से महज 300 मकानों में लगा है सिस्टम, करीब 1000 मकानों के प्रकरण लंबित

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। शासन प्रशासन द्वारा जल संरक्षण को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके भी लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता नहीं आई है और लोग जल संरक्षण कि ओर अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हैं।जिसके चलते जल संरक्षण का यह अभियान महज कागजों में सिमटता नजर आ रहा है। प्रतिवर्ष बरसात व गर्मी के दिनों में शासन प्रशासन, नेतागण व समाजसेवियों सहित जागरूक नागरिकों द्वारा जल संरक्षण को लेकर तरह-तरह के कसीदे गढ़े जाते हैं जल को व्यर्थ बहने से रोकने की बातें की जाती है, वही जल को बचाने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं लेकिन जल के संरक्षण के लिए बने नियम का पूर्णताः पालन नहीं किया जाता।जी हां बात कर रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की, जिसकी अनिवार्यता को लोग हल्के में ले रहे हैं और जहां-तहां इस नियम को ताक में रख धड़ल्ले से नए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।जहां लोगो द्वारा नए भवनों का निर्माण तो कराया जा रहा है लेकिन उन भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया जा रहा है जिसके चलते अनिवार्य वाटर हार्वेस्टिंग का यह नियम सरकारी फाइलों की शोभा बना हुआ है।हालांकि नगरपालिका ने नए बन रहे मकानों के लिए गाइड लाइन तय कर रखी है, पर इसका कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा। केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई शासकीय कार्यालयों में भी अनिवार्य वाटर हार्वेस्टिंग के इस नियम कि धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और नगर में महज गिने-चुने शासकीय कार्यालयों और आम लोगों के घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ नजर आता है।

क्या कहता है नियम

बात अगर नियम की करे तो नगर पालिका की गाइड लाइन के अनुसार जब भी नगर पालिका से भवन निर्माण की अनुमति जारी की जाती है तो भवन निर्माण कराने वाले व्यक्ति को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की जानकारी दी जाती है और 2500 रु से लेकर 7हजार ,व 12 हजार रु(साइज के अनुसार) डिपाजिट जमा कर उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाने को कहा जाता है यदि भवन निर्माण करा रहा वह व्यक्ति अपने भवन में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा लेता है तो जमा कराई यहा राशि उसे वापस कर दी जाती है। यदि एक समय सीमा के भीतर भवन निर्माण कराने वाला व्यक्ति अपने मकान में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाता तो नगर पालिका द्वारा उस व्यक्ति की जमा की गई उक्त राशि से उसके भवन में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का नियम बनाया गया है लेकिन नियमों को ताक में रख बालाघाट नगर में भवनों का निर्माण कराया जा रहा है और यह नियम भी अन्य नियमों की तरह सरकारी फाइलों की शोभा बढ़ाता नजर आ रहा है।

सरकारी फाइलों में दम तोड़ रही योजना

शहरी सीमा क्षेत्र में हर साल सैकड़ों मकान बन रहे हैं पर उन मकानों में वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण नहीं हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बगैर तैयार हो रहे मकानों को देखने की फुर्सत भी नपा के पास नहीं है।यदि लोग गंभीरता से यह सिस्टम अपने घरों में लगाते हैं तो करोड़ों लीटर पानी व्यर्थ बहने से रोका जा सकता है। वही करोड़ों लीटर पानी धरती के गर्भ संरक्षित होता। लेकिन पानी बचाने को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं और शासकीय योजनाएं भी फाइलों में ही दम तोड़ रही हैं। योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होने से इसका बेहतर लाभ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नगरपालिका क्षेत्र में भवन बनाने वालों के लिए नियम के तहत मकान निर्माण के साथ वाटर हार्वेस्टिंग बनवाना अनिवार्य है। अधिकांश लोग नगर पालिका से भवन बनाने का नक्शा तो पास करा लेते हैं पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाते। जबकि नियम में मकान बनाने वाले को मकान में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी बताया गया है। अभी भी शहर में सैकड़ों मकानों का निर्माण हो रहा है। कॉलोनियां बसाई जा रही है पर वहां भी इसकी कोई मानिटरिंग नहीं हो रही। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी निर्माण एजेंसियां भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने को लेकर गंभीर नहीं है।

1 साल पूर्व जारी किए गए थे नोटिस पर नहीं हुआ कोई असर

जल के संरक्षण के लिए नगर पालिका द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व सभी शासकीय कार्यालयों में नोटिस जारी कर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए थे इन निर्देशों के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और आज भी ऐसे कई शासकीय कार्यालय हैं जहां वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा है सवाल यह है कि जब सरकारी महकमा ही वाटर हार्वेस्टिंग के इस नियम का पालन नहीं कर रहा है तो फिर आम लोग भला इस नियम का पालन कैसे करेंगे।वही इस नियम को लेकर लोगों में जन जागरूकता कैसे आएगी ?

बढ़ता है जलस्तर

रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में छत का पानी पाइप के सहारे सीधे जमीन में पहुंचता है। इससे वाटर लेवल बढ़ता है। इसमें रेत, गिट्टी, बजरी गिट्टी तथा ईंट का उपयोग किया जाता है। जानकार बताते हैं कि इस तरह से वर्षा जल संरक्षित करने से काफी हद तक जल सुरक्षित हो जाता है। भूगर्भ का जल स्तर बढ़ने से पानी की किल्लत का सामना भी नहीं करना पड़ता

बिल्डिंग में अनिवार्य है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

बताया गया की वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य है बिल्डिंग की परमिशन के साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की भी समझाइश दी जाती है।नपा जब बिल्डिंग की परमिशन देती हैं तो बिल्डिंग की परमिशन लेने वाले से राशि जमा कराई जाती है ताकि बरसात का पानी धरती में चला जाए और जल स्तर ऊंचा हो। सड़क नालियां कांक्रीट की होने के चलते बरसात का पानी जमीन के भीतर नहीं जा पाता जिससे पानी व्यर्थ बह जाता है जिसे रोका जाना अति आवश्यक है समय-समय पर लोगों को जागरूक करने अभियान भी चलाया जाता है ताकि पानी को सहज कर रखा जा सके।लेकिन इसका भी लोगो पर कोई असर नही पड़ रहा है।

अब राशि जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी- ज्योति मेश्राम

मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका इंजीनियर श्रीमती ज्योति मेंश्राम ने बताया कि वाटर हार्वेस्टिंग का नियम अनिवार्य है हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा होना चाहिए, ताकि बरसात के पानी को भूमि के भीतर संरक्षित करके रखा जा सके। परमिशन लेते वक्त भी इस नियम की जानकारी लोगों को दी जाती है और वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के लिए निर्माण एरिया के आधार पर 2500 से लेकर 5, हजार, 7000 और 10000 हजार ऐसे रुपए जमा कराए जाते हैं,सम्बंधित व्यक्ति अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर, सूचना नगर पालिका में देता है तो उसकी जमा की गई यहां रकम वापस कर दी जाती है। लेकिन इसमें लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं करीब 1300 मकान की परमिशन जारी की गई है जिसमें से महज 300 लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है जबकि करीब हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह सिस्टम नहीं लगवाया। गर्मी के समय सभी को दूरभाष पर जानकारी देकर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने कहा गया था और उनकी रकम वापस ले जाने कहा गया था,लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अब पुनः नोटिस जारी करके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने कहा जाएगा, यदि वे ऐसा नहीं करते तो नगर पालिका द्वारा उनकी जमा की गई राशि को जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। हमारी सभी से अपील है कि घर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर लगाए ताकि भविष्य में पानी को लेकर किसी प्रकार की परेशानी ना हो।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत महिला थाना बालाघाट की टीम ने विद्यार्थियों को दिलाई नशामुक्ति की शपथ

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत 24 जुलाई को महिला थाना बालाघाट की टीम ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया तथा उन्हें नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया।अभियान के अंतर्गत महिला थाना पुलिस की टीम ने शासकीय सांदीपनि विद्यालय लेंडेझरी (लालबर्रा) एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेकाडी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटंगझरी तथा शासकीय हाई स्कूल नेतरा में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया।इस दौरान विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा और समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों से नशे से दूर रहने, अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र-छात्राओं को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई और स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प कराया गया। महिला थाना प्रभारी किरण वरकडे ने बताया कि अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

वनग्रामों के विस्थापन की कार्रवाई के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न

परिवार की ईकाई निर्धारण के लिए 24 जुलाई 2026 कट ऑफ डेट निर्धारित, 04 अगस्त को ग्राम पंचायतों में सूचना का होगा प्रकाशन

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। दक्षिण सामान्य वनमंडल, बालाघाट के अंतर्गत तहसील बालाघाट एवं परसवाड़ा क्षेत्र में स्थित वनग्राम कुर्थीटोला, खापा, तल्लाबोड़ी, पोलबत्तुर एवं कोकमा के विस्थापन की कार्रवाई के संबंध में 24 जुलाई 2026 को कलेक्टर श्री मृणाल मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वनग्रामों के विस्थापन की प्रक्रिया, सूचना के प्रकाशन तथा दावे-आपत्तियों के निराकरण के संबंध में चर्चा कर आवश्यक तिथियां निर्धारित की गईं। बैठक में समिति के सचिव एवं दक्षिण सामान्य वनमंडल के वनमंडलाधिकारी श्री नित्यानंदम एल., जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, समिति के सदस्य तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में तय किया गया कि विस्थापित होने वाले परिवार की ईकाई निर्धारण के लिए 24 जुलाई 2026 को कट ऑफ डेट माना जाएगा। जिन युवक-युवतियों ने 24 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली होगी, उन्हें पृथक इकाई माना जाएगा।

वनग्रामों के विस्थापन के संबंध में अनुभाग स्तरीय समिति ग्रामों का सर्वे कर 04 अगस्त 2026 को संबंधित ग्राम पंचायतों में विस्थापित होने वाले परिवारों की सूची का प्रकाशन करेगी। सूचना प्रकाशित होने के साथ ही दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिनका निराकरण 11 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। विस्थापित होने वाले वनग्राम कुर्थीटोला, खापा, पोलबत्तुर एवं कोकमा बालाघाट तहसील के अंतर्गत आते हैं, जबकि तल्लाबोड़ी परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत स्थित है। वनग्रामों के विस्थापन के लिए प्रत्येक पात्र इकाई को 15 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। परिवार में पति-पत्नी एवं उनके बचों को एक इकाई माना जाएगा। वहीं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवक-युवती, दिव्यांग व्यक्ति तथा विधवा महिला को पृथक इकाई के रूप में पात्रता प्रदान की जाएगी।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान

रूपझर पुलिस ने रैली जनजागरण और शपथ कार्यक्रमों से फैलाया नशामुक्ति का संदेश

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले में चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत रूपझर पुलिस ने 24 जुलाई को व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर विद्यार्थियों, ग्रामीणों, यात्रियों एवं आम नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। विभिन्न गांवों और सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प दिलाया गया।अभियान की शुरुआत ग्राम रूपझर में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं की जागरूकता रैली से हुई। रैली के दौरान बच्चों ने नशे से दूरी है जरूरी जैसे प्रेरक नारे लगाते हुए पूरे गांव में जनजागरूकता फैलाई और ग्रामीणों से नशे का त्याग करने की अपील की।इसके बाद रूपझर थाना के सामने से गुजरने वाली बसों को रोककर पुलिस ने यात्रियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी तथा उनसे स्वयं नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का आग्रह किया।अभियान के तहत उकवा रेंज कार्यालय पहुंचे विभिन्न लोगों को भी नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को बताया कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है तथा इससे दूर रहकर ही स्वस्थ और सुरक्षित जीवन संभव है।रूपझर पुलिस की टीम ने समनापुर, पोंडी, पोला, पटपरी, जामटोला और किनारदा सहित विभिन्न गांवों के स्कूलों में पहुंचकर छात्र-छात्राओं को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को स्वयं नशे से दूर रहने के साथ-साथ अपने परिवार और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने की सीख दी गई। इस दौरान छात्रों एवं ग्रामीणों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई।उकवा बाजार में पुलिस ने आम नागरिकों को एकत्रित कर पंपलेट वितरित किए तथा बैनर के माध्यम से अभियान की जानकारी दी। वहीं जगन्नाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को भी नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के उद्देश्य से अवगत कराते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया गया।रूपझर थाना प्रभारी कामेश धूमकेती ने बताया कि अभियान का उद्देश्य युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी बढ़ाना है। पुलिस द्वारा यह अभियान क्षेत्र में लगातार चलाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुंच सके।

शासकीय महाविद्यालय हट्टा मे आयोजित किया गया नशा मुक्ति अभियान

पद्मेश न्यूज। हट्टा । उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार शासकीय महाविद्यालय, हट्टा में दिनांक 15-जुलाई 2026 से 30 जुलाई 2026 तक 15 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। यह कार्यक्रम महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री अंशुल मेश्राम की उपस्थिति में संपन्न कराया गया।इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा स्वस्थ एवं नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करना था।अभियान के प्रथम दिवस, 15 जुलाई 2026 को महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों की संहभागिता से इसके अंतर्गत अवेयरनेस रन व रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने नशा उन्मूलन से संबंधित संदेश एवं नारों द्वारा आमजन को जागरूक किया।16 जुलाई 2026 को विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय में नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रील एवं लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसमें नशे के दुष्प्रभावों तथा उससे बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। 17 जुलाई 2026 को नशे के दुष्परिणाम एवं सामाजिक दुष्प्रभाव पर तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू-सिगरेट की कोई दुकान संचालित न हो, इस पर सहायक प्राध्यापक राकेश रंगारे द्वारा विशेष व्याख्यान दिया गया एवं पुलिस थाना, हट्टा के सहायक उप-निरीक्षक विजय पटले, राजेश पटले, श्री आर विष्णु प्रताप.एवं आर लक्ष्मी टेकाम द्वारा परिसर में महाविद्यालय के विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई।21 जुलाई 2026 को मंहाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए चित्रकला, निबंध, पेंटिंग, स्लोगन एवं रंगोली-पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।समस्त कार्यक्रमों के आयोजन में महाविद्यालय के समस्त शिक्षकगण, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की और अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।इस प्रकार यह 15 दिवंसीय कार्यक्रम विद्यार्धियों के लिए प्रेरणादायक एवं मार्गदर्शक अनुभव रहा।

आवश्यकता है
श्री फाइनेंस में
कर्मचारियों की
कम्प्यूटर ज्ञान आवश्यक है,
वेतनमान योग्यतानुसार,
वारासिवनी के आसपास
वाले ही संपर्क करें
-संपर्क सूत्र-
श्री फाइनेंस वारासिवनी
मो.नं. 9329595770

आवश्यकता है
ऐश्वर्य कम्पयुटर में
कम्प्युटर टीचर्स - 03 पद
टैली टीचर्स - 02 पद
स्टेनो टीचर्स - 02 पद
ऑफिस कार्य - 02 पद
इच्छुक युवक-युवती सम्पूर्ण
बॉयोडाटा इंस्टीट्यूट में जमा कर सकते हैं।
वेतन-योग्यतानुसार
पता-ऐश्वर्य कम्प्युटर
पानी टंकी के पास, पुराना रोजगार
कार्यालय के सामने, बूढ़ी, बालाघाट (म.प्र.)
7691909255, 9424663575

बारबेड वायर (कांटेदार तार)
एवं चेन लिंक जाली
उचित दाम पर उपलब्ध
लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध
निर्माता
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोनः- 07632-243531
मोः- 8989976858, 9425139998

न्यूज गैलरी

एमएलबी स्कूल में करियर मार्गदर्शन एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम संपन्न

पद्मेश न्यूज़। बालाघाट। गुरु पूर्णिमा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में करियर मार्गदर्शन एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को 10वीं और 12वीं के बाद सही दिशा

चुनने में मदद करना था ।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती धनश्री जैन एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती मोनिका पटेल विशेष रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार जैन ने की। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती धनश्री जैन ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर सही करियर का चुनाव ।उन्होंने कहा कि ꠰जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, उसी क्षेत्र में करियर बनाएं ।भीड़ देखकर निर्णय न लें ।लक्ष्य निर्धारित करें, मेहनत करें और माता-पिता एवं शिक्षकों का सहयोग लें ।असफलता से घबराएं नहीं, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती मोनिका पटेल ने अपने जीवन की विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए छात्राओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई तरह की बाधाएं आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को पार करके ही सफलता मिलती है। हार मानने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं विस्तृत जानकारी दी ।वही प्राचार्य डॉ. मनोज कुमार जैन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते हैं ।कार्यक्रम का संयोजन मुख्य रूप से वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती तनुजा ठाकुर, मीना परासर, प्रिया बक्शी, नीता मिश्रा, प्रतिमा दुबे ने किया ।कार्यक्रम में समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बडी संख्या में छात्राएं उपस्थित रही।

तीन बच्चों की मौत के बाद जागा प्रशासन, अडोरी के गांवों में स्वास्थ्य अलर्ट

कुंडेकसा और बोंदारी में वायरल बीमारी के बीच स्वास्थ्य शिविर शुरू, अंधविश्वास के कारण समय पर इलाज नहीं मिलने की आशंका

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

बिरसा तहसील की ग्राम पंचायत अडोरी के अंतर्गत आने वाले कुंडेकसा और बोंदारी गांव इन दिनों बच्चों में फैल रही अज्ञात बीमारी को लेकर दहशत में हैं। बीते 15 से 20 दिनों के भीतर तीन मासूम बच्चों की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। सबसे चिंताजनक बात यह सामने आई है कि बीमारी फैलने के बावजूद कई परिवार आज भी अस्पताल का रुख करने के बजाय झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र का सहारा ले रहे हैं। लगातार मौतों के बाद मामला प्रशासन तक पहुंचा, जिसके बाद कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और प्रभावित गांवों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर घर-घर स्वास्थ्य परीक्षण शुरू कराया गया।

ग्राम पंचायत अडोरी के सरपंच परशुराम धुर्वे ने बताया कि पिछले कई दिनों से पंचायत के कुंडेकसा, बोंदारी सहित आसपास के गांवों में छोटे बच्चों के शरीर पर लाल दाने निकलने, तेज बुखार, कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कई बच्चों की तबीयत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने और अंधविश्वास के कारण स्थिति गंभीर होती चली गई। उन्होंने बताया कि अब तक तीन मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में भय और चिंता का माहौल है। जानकारी के अनुसार बोंदारी गांव निवासी सोमारू धुर्वे की तीन वर्षीय पुत्री लमिया धुर्वे और एक वर्षीय पुत्र संतोष धुर्वे की बीमारी के चलते मौत हो गई। इसी प्रकार कुंडेकसा गांव निवासी नेहरू मरकाम की तीन वर्षीय पुत्री प्रती मरकाम ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लगातार तीन बच्चों की मौत के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि अभी भी गांव में कई बच्चे बीमार हैं। अधिकांश बच्चों के शरीर पर दाने निकल रहे हैं और उन्हें तेज बुखार आ रहा है। कई परिवारों ने बच्चों का इलाज कराया है, लेकिन कुछ लोग अब भी पारंपरिक झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के भरोसे बैठे हैं। यही कारण है कि बीमारी को लेकर ग्रामीणों में डर और असमंजस दोनों बना हुआ है ।सरपंच परशुराम धुर्वे ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण कई लोग समय रहते अस्पताल नहीं पहुंचते। उन्होंने कहा कि यदि शुरुआत में ही सभी मरीजों का चिकित्सकीय उपचार कराया जाता तो शायद इतनी गंभीर स्थिति पैदा नहीं होती। उन्होंने प्रशासन से गांवों में लगातार स्वास्थ्य निगरानी रखने और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। तीन बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही कलेक्टर मृणाल मीणा ने स्वास्थ्य विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद चिकित्सा विभाग की टीमों ने अडोरी पंचायत के प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाए। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने घर-घर जाकर बच्चों की जांच शुरू की, दवाइयों का वितरण किया और गंभीर मरीजों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। स्वास्थ्य अमला लगातार गांवों में निगरानी बनाए हुए है ताकि बीमारी का फैलाव रोका जा सके। लगातार तीन मासूमों की मौत ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और अंधविश्वास के बीच चल रही लड़ाई को उजागर कर दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि स्वास्थ्य विभाग बीमारी पर कितनी जल्दी नियंत्रण पा पाता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

प्रभावित गांवों में मेडिकल टीम तैनात है - परेश उपलव

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलव ने बताया कि विभाग को तीन बच्चों की मौत और कई बच्चों के बीमार होने की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में क्षेत्र में वायरल फीवर के मामले सामने आए हैं, हालांकि बीमारी के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच भी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है और प्रभावित गांवों में लगातार मेडिकल टीम तैनात है। सीएमएचओ ने ग्रामीणों से स्पष्ट अपील की कि बच्चे को बुखार, शरीर पर दाने, कमजोरी या किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास का सहारा न लें। ऐसे मामलों में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचें, क्योंकि समय पर उपचार ही बच्चों की जान बचा सकता है।

सीएम हेल्पलाइन और शिकायतों का डर दिखाकर सरपंचों से वसूली, 90 हजार रुपये लेते दो कथित पत्रकार रंगे हाथ गिरफ्तार

एसपी बोले- महीनों से पंचायतों को बना रखा था निशाना, शिकायत बंद कराने के नाम पर मांगे थे 2.10 लाख रुपये, सरपंचों की रणनीति और पुलिस की ट्रैप कार्रवाई से हुआ खुलासा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले में सीएम हेल्पलाइन और शासकीय शिकायतों का भय दिखाकर ग्राम पंचायतों से कथित रूप से रंगदारी वसूलने वाले दो तथाकथित पत्रकारों को पुलिस ने सुनियोजित ट्रैप कार्रवाई में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों कई महीनों से विभिन्न पंचायतों के सरपंचों को शिकायतें दर्ज कराने, सीएम हेल्पलाइन में प्रकरण लगवाने और फिर उन्हें बंद कराने के नाम पर मोटी रकम की मांग कर रहे थे। 24 जुलाई को स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेसवार्ता में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों को शिकायतकर्ताओं से 90 हजार रुपये लेते समय गिरफ्तार किया गया है। मामले में दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि ग्राम पंचायत मौदा के सरपंच मनमोहन वैद्य ने 23 जुलाई को थाना अजाक में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी संजय अजीत और उसका साथी अंकुश चौहान विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों से शिकायतें एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरण बंद कराने के नाम पर कुल 2 लाख 10 हजार रुपये की अवैध मांग कर रहे थे। आरोपियों को पहली किश्त के रूप में पहले ही 60 हजार रुपये दिए जा चुके थे, जबकि शेष 90 हजार रुपये 23 जुलाई की शाम दीनदयालपुरम कॉम्प्लेक्स में दिए जाने थे। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी अजाक निरीक्षक ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखते हुए ट्रैप की योजना बनाई। तय समय पर जब शिकायतकर्ता दीनदयालपुरम पहुंचे और आरोपियों ने 90 हजार रुपये की राशि प्राप्त की, तभी पहले से मौजूद पुलिस टीम ने दोनों को रंगे हाथ दबोच लिया। मौके से पूरी नकद राशि और मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय अजीत (38 वर्ष), निवासी कोसमी तथा अंकुश चौहान (29 वर्ष), निवासी बूढ़ी, बालाघाट के रूप में हुई है। दोनों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 351(2) एवं एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) और 3(2)(1ड़) के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रेसवार्ता के दौरान मौजूद सरपंचों ने भी पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपी स्वयं को पत्रकार बताकर पंचायतों में हुए निर्माण कार्यों, तालाब, सड़क और अन्य विकास कार्यों को लेकर लगातार शिकायतें करते थे। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन और अन्य विभागों में प्रकरण दर्ज कर पंचायत प्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जाता था। जब सरपंच परेशान हो जाते, तब शिकायत वापस लेने और प्रकरण बंद कराने के एवज में हजारों रुपये की मांग की जाती थी। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रकाश बाहे ने बताया कि संजय अजीत लंबे समय से पंचायत को निशाना बना रहा था। पहले भी उसके खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने से कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद सरपंचों ने रणनीति बनाकर आरोपी की पैसे मांगने संबंधी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की। उन्होंने बताया कि आरोपी पहले छिपकर पैसे लिया करता था, इसलिए इस बार बटन कैमरा और अन्य माध्यमों से पूरे घटनाक्रम के सबूत जुटाए गए। बाद में सभी साक्ष्य पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए, जिसके आधार पर ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई। सरपंचों ने यह भी दावा किया कि आरोपी शिकायत वापस लेने के बाद एक लिखित सहमति पत्र भी तैयार कराता था, जिसमें भविष्य में दोबारा शिकायत नहीं करने की बात लिखी जाती थी। इतना ही नहीं, हाल ही में आरोपियों से एक माफीनामा भी लिखवाया गया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि उनके द्वारा की गई कुछ शिकायतें गलत थीं। इसके बावजूद वे लगातार पंचायतों से धन उगाही का प्रयास करते रहे। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को शिकायत करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यदि कोई शिकायतों का दुरुपयोग कर अवैध धन वसूली, ब्लैकमेलिंग या रंगदारी का माध्यम बनाता है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में इस प्रकार की गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है और भविष्य में भी ऐसी शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व मामलों के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में करें निराकरण-कलेक्टर मृणाल मीना

कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की ली बैठक

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कलेक्टर मृणाल मीना ने शुक्रवार 24 जुलाई को जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की बैठक लेकर राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि साइबर तहसील, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा तरमीम और सीएम हेल्पलाइन से जुड़े मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, श्री डी.पी. बर्मन, संयुक्त कलेक्टर राहुल नायक, श्री एम.आर. कोल, एसडीएम गोपाल सोनी तथा अधीक्षक भू-अभिलेख कृष्णा नायक उपस्थित रहे। जिले के सभी एसडीएम एवं तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

साइबर तहसील के लंबित मामलों पर जताई नाराजगी

कलेक्टर ने सबसे पहले साइबर तहसील के प्रकरणों की समीक्षा की। किरनापुर, लांजी, परसवाड़ा और लालबर्रा तहसीलों में नामांतरण के अधिक मामले लंबित मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भूमि की रजिस्ट्री होने के बाद निर्धारित समय-सीमा में नामांतरण होना अनिवार्य है। यदि समय पर नामांतरण नहीं हुआ तो संबंधित पटवारी और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

10 दिन से अधिक विलंब पर पटवारी का वेतन रोकने के निर्देश

बैठक में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी मामलों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकरण के निराकरण में 10 दिन से अधिक का विलंब होता है तो संबंधित पटवारी का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाए।

एमपीआईडीसी को 30 एकड़ भूमि आवंटन में तेजी लाने के निर्देश

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री मीना ने खैरलांजी तहसील के ग्राम सावरी में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) को 30 एकड़ शासकीय भूमि के शीघ्र आवंटन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने वारासिवनी एसडीएम को इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जा सके।

वसूली बढ़ाने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश

बिरसा, कटंगी और तिरोड़ी तहसीलों में विभिन्न राजस्व मदों की वसूली की प्रगति कम पाए जाने पर कलेक्टर श्री मीना ने इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामांतरण और बंटवारा के साथ-साथ नक्शा तरमीम का कार्य भी तत्काल पूरा किया जाए। कलेक्टर ने शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल की सहायता लेकर अतिक्रमण हटाया जाए।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण पर जोर

बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री मीना ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि शिकायतों का गंभीरता से निराकरण करें और कोई भी शिकायत 50 दिनों से अधिक लंबित न रहे। उन्होंने कहा कि नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा से संबंधित शिकायतों पर पटवारी, राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, ताकि शिकायतों का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित हो सके।

डाइट बालाघाट में जनशिक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न, 128 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) बालाघाट में जनशिक्षकों का पांच दिवसीय अकादमिक एवं क्षमतावर्धन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य जनशिक्षकों की शैक्षणिक दक्षता, निरीक्षण क्षमता तथा विद्यालयों में अकादमिक गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाना था। कलेक्टर मृणाल मीना एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ के निर्देशन में आयोजित इस प्रशिक्षण में जिले के 128 जनशिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मैदानी स्तर पर विभागीय कार्यों के प्रभावी संचालन तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स श्री के.डी. तितिरमारे, श्री एस.एन. पंडित, श्री महाजन बिसेन, योगेश कुमार ताम्रकार, शेख हबीब खान एवं राकेश कुमार पटले ने जनशिक्षकों को मॉनिटरिंग, निरीक्षण, विद्यालय प्रबंधन, अकादमिक नेतृत्व, क्षमतावर्धन तथा विभागीय कार्यप्रणाली से जुड़े विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया।

साथ ही विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनशिक्षकों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर डाइट के प्राचार्य नरेश प्रसाद मलगाम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के समग्र विकास तथा शिक्षकों में नवाचार और विभागीय निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन में जनशिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनशिक्षक शिक्षा व्यवस्था और विद्यालयों के बीच एक सशक्त अकादमिक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। प्रशिक्षण प्रभारी श्री के.डी. तितिरमारे ने बताया कि जनशिक्षकों द्वारा विद्यालयों की सतत मॉनिटरिंग एवं मार्गदर्शन से शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण जनशिक्षकों को अकादमिक एवं प्रशासनिक विषयों की अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा, जिससे वे विद्यालयों के शिक्षकों का बेहतर मार्गदर्शन कर सकेंगे और शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बना सकेंगे। समापन समारोह में सभी प्रतिभागी जनशिक्षकों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर शुभकामनाएं दी गईं तथा अपेक्षा व्यक्त की गई कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव का उपयोग वे विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में करेंगे।

पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से नहर के ऊपर बने पुल में जमा हो रहा पानी

पानी जमा होने से बड़ी दुर्घटना होने की बनी संभावना, आवागमन में हो रही परेशानी, जिम्मेदार मौन, पानी निकासी की व्यवस्था बनाने की उठी मांग

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा।

लालबर्रा से समनापुर मार्ग पर स्थित ढूटी वीयर वैनगंगा बड़ी नहर के पुल पर पानी की सही निकासी न होने के कारण बारिश के दिनों में भारी जलभराव हो रहा है। यानि की तेज बारिश होने पर पुल में पानी का जमाव हो जाता है। जिससे राहगीरों, वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जलभराव से यहां कभी भी गंभीर दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है किन्तु पानी निकासी की व्यवस्था नही की जा रही है जबकि प्रतिवर्ष बारिश के दिनों में पुल के ऊपर पानी जमा होने की स्थिति निर्मित होती है और बरसात शुरू होने के पूर्व पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की जाती है। लेकिन संबंधित जिम्मेदार विभाग और प्रशासन पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। जिससे आने-जाने वाले ग्रामीणजन एवं राहगीरों में शासन-प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है।

पानी का जमाव पुल को कर सकता है क्षतिग्रस्त

आपकों बता दें कि लालबर्रा से समनापुर पहुंच मार्ग का निर्माण विगत वर्ष पूर्व लाखों रूपयों की लागत से किया गया है परंतु इस मार्ग के निर्माण कार्य में संबंधित ठेकेदार के द्वारा भारी लापरवाही बरती गई है और इस मार्ग के संबंध में आये दिन नई नई समस्याएं देखने को मिलती है। गत दिनों दिनों से हो रही बारिश के कारण लालबर्रा से समनापुर पहुंच मार्ग अमोली से बम्हनी के बीच से गुजरी ढूटीवीयर वैनगंगा बड़ी नहर में सड़क निर्माण के दौरान ही बनाये गये नवीन पुल में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पुल पर पानी का जमाव हो रहा है। जिससे जहां एक ओर राहगीरों व स्कूलीं ब'चों को आवागमन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वहीं दूसरी ओर पुल पर कई दिनों तक पानी का जमाव होने से यह पुल को क्षतिग्रस्त भी कर सकता है जिससे शासन को काफी नुकसान होगा। साथ ही पुल के ऊपर बारिश का पानी जमा होने पर अगर आने-जाने वालों के वाहन तेज गति में रहता है एवं अनियंत्रित होता है तो पुल से वाहन टकराकर वे सीधे नहर के नीचे गिर सकते है। जबकि वर्तमान में नहर में 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता है। इस समस्या से सड़क विभाग को अवगत करवा दिया गया है परन्तु शासन-प्रशासन के द्वारा इस समस्या को नजरअंदाज करके भारी लापरवाही बरती जा रही है और पुल का उचित रख रखाव नहीं होने के कारण जल्द क्षतिग्रस्त होने की संभावना भी बन रही है। जबकि संबंधित ठेकेदार को पुल निर्माण के दौरान पानी निकासी के लिए पुल के दोनों ओर किनारे में होल बनाये जाने चाहिये थे। जिससे आसानी से पानी की निकासी हो सके परंतु ठेकेदार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिससे पुल पर पानी का जमाव हो रहा है। जिसके कारण आने-जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क विभाग से पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग राहगीर एवं ग्रामीणजनों ने की है।

दर्जनों ग्राम के ग्रामीणजन करते है आवागमन

यह मार्ग लालबर्रा से समनापुर होते हुए बालाघाट-मंडला मुख्य मार्ग को आपस में जोडता है और इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में दर्जनों ग्राम के ग्रामीणजन आवागमन करते है और यह मार्ग बम्हनी, ददिया, खामघाट, आमाटोला, समनापुर सहित अन्य दर्जनों ग्रामों को शहर से जोड़ता है। जिससे बड़ी संख्या में लोग रोजाना मार्केट, शासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज सहित अन्य जगह पर आवश्यक काम के चलते आवागमन करते है। परंतु बारिश होने पर पुल पर पानी का जमाव होने के कारण पुल के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणजन एवं राहगीरों ने शासन प्रशासन से पुल में जमा हो रहे पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है।

इनका कहना है-

लालबर्रा से समनापुर पहुंच मार्ग अमोली से बम्हनी के बीच से गुजरे ढूटीवीयर वैनगंगा बड़ी नहर के ऊपर बने पुल में जमा हो रहे पानी निकासी की व्यवस्था नही होने के कारण पानी जमा होने की समस्या के संबंध में आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। जल्द ही स्थल निरीक्षण कर जमा पानी की निकासी की व्यवस्था की जायेगी।

मुकेश बेले
एजेएम
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग
बालाघाट।

अतरी से आमाटोला (गाडर) पहुंच मार्ग खस्ताहाल

आवागमन में हो रही परेशानी, मरम्मत करवाने की उठी मांग

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय से महज 4 किमी दूर स्थित ग्राम पंचायत अतरी से आमाटोला (गाडर) को जोड़ने वाला पहुंच मार्ग इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रहा है। सड़क पर जगह-जगह बने गड्डों और उधड़ती गिट्टियों के कारण राहगीरों एवं ग्रामीणों को आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बदहाल सड़क के चलते इस मार्ग पर हर समय किसी बड़ी दुर्घटना के होने का अंदेशा बना रहता है। लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा इस सड़क की समस्या की ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है जिससे ग्रामीणजनों एवं राहगीरों में प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

गुणवत्ताहीन निर्माण की खुली पोल

आपकों बता दे कि ग्राम अतरी के समीप से गुजरी वैनगंगा बड़ी नहर किनारे से विगत वर्ष पूर्व सीसी सड़क का निर्माण करवाया गया है। लेकिन यह निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नही होने के कारण निर्माण के कुछ साल बाद ही सीमेन्टीकरण सड़क के बीच में दरारे आ चुकी है एवं जगह-जगह से गिट्टियां उखड़ जाने और सड़क खराब हो जाने से आवागमन करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से निर्माण के कुछ साल बाद ही लाखों रूपयों की लागत से बनी सीसी सड़क निर्माण कार्य के गुणवत्ताहीन की पोल खुल चुकी है। निर्माण एजेंसी व सड़क विभाग के द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता बरतते हुए शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अतरी से गाडर आमाटोला पहुंच मार्ग का सीमेंटीकरण कुछ वर्ष पूर्व ही करवाया गया था। लेकिन निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान न रखे जाने के कारण सड़क खराब हो चुकी है। वर्तमान में सड़क पर जगह-जगह गहरी दरारें आ चुकी हैं और कंक्रीट उधड़कर पूरी सड़क जर्जर हो चुकी है। यह साफ तौर पर निर्माण एजेंसी की लापरवाही और गुणवत्ताहीन कार्य को दर्शाता है। सड़क की इस जर्जर स्थिति से क्षेत्रीयजन लंबे से परेशान है लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा इस समस्या की ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। आगे कहा कि सड़क की बदहाली और इससे होने वाली समस्याओं को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय प्रशासन को अवगत करवा चुके है। इसके बावजूद अब तक न तो सड़क के जीर्णोध्दार पर ध्यान दिया गया और न ही कोई मरम्मत कार्य शुरू करवाया गया है, जिसके कारण सड़क और बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। जबकि इस मार्ग से रोजाना ग्रामीणों और स्कूली ब'चों का आना-जाना होता है। बारिश के दिनों में और भी 'यादा खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों एवं राहगीरों ने स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि सड़क की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द अतरी से आमाटोला गाडर पहुंच मार्ग का मरम्मत कार्य करवाये ताकि आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।

जाम के हायर सेकेण्डरी स्कूल में नशा मुक्ति अभियान 2.0 आयोजित

थाना प्रभारी राजमल दायमा ने विद्यार्थियों को दिलाई नशे से दूर रहने की शपथ

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक विशेष नशा मुक्ति अभियान 2.0 'नशे से दूरी है जरूरी' चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति निरंतर जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में 24 जुलाई को थाना लालबर्रा के थाना प्रभारी राजमल दायमा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाम पहुंचे। जहां उन्होंने 'नशे से दूरी है जरूरी' विषय पर छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं के बीच एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी राजमल दायमा ने विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि किशोरावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है। किसी भी प्रकार के प्रलोभन या बहकावे में आकर नशे की गर्त में न जाये। साथ ही थाना प्रभारी ने उपस्थित शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपने आसपास के वातावरण को नशा-मुक्त बनाने तथा समाज में इसके प्रति अलख जगाने का आव्हान भी किया है। वहीं कार्यक्रम के अंत में थाना प्रभारी ने उपस्थित समस्त छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को जीवन में कभी भी नशा न करने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं, विद्यार्थी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।

सामान्य वन परिक्षेत्र अधिकारी सीता भलावी का रीवा तबादला

सहायक वन संरक्षक के पद पर गोविन्दगढ़ वन विद्यालय में देंगी सेवाएं

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा हाल ही में अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत दक्षिण सामान्य वन मंडल लालबर्रा में पदस्थ वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती सीता भलावी का स्थानांतरण रीवा कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा गत 22 जुलाई को जारी स्थानांतरण आदेश के तहत श्रीमती सीता भलावी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अब रीवा स्थित गोविन्दगढ़ वन विद्यालय में सहायक वन संरक्षक सह अनुदेशक के महत्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। श्रीमती भलावी का दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र में कार्यकाल बेहद सराहनीय रहा है।

वन एवं वन्यजीव संरक्षण, क्षेत्र में अवैध कटाई पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा स्थानीय समुदाय के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में उनकी भूमिका की काफी सराहना की गई है। अब गोविन्दगढ़ वन विद्यालय में उनकी नियुक्ति से वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भावी वनकर्मियों को उनके प्रशासनिक अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। आदेश जारी होने के बाद विभाग द्वारा उन्हें नये पदस्थापना स्थल पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये है।

हट्टा पुलिस ने सालेटेका बस स्टैंड पर ऑटो चालकों को दिलाई गई नशामुक्ति की शपथ

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले में चलाए जा रहे नशे से दूरी 2.0 अभियान के तहत 24 जुलाई को थाना हट्टा पुलिस द्वारा सालेटेका बस स्टैंड में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ऑटो चालकों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। यह कार्यक्रम सहायक उप निरीक्षक विजय पटले के नेतृत्व में थाना हट्टा पुलिस टीम द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। सड़क पर वाहन चलाने वाले चालकों की जिम्मेदारी और भी अधिक होती है इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहकर सुरक्षित एवं जिम्मेदार ढंग से वाहन संचालन करना चाहिए। पुलिस टीम ने ऑटो चालकों से अपील की कि वे स्वयं नशे से दूर रहें तथा अपने साथियों और परिचितों को भी नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ऑटो चालकों ने नशे का सेवन नहीं करने तथा समाज में नशामुक्ति का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। थाना हट्टा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक विजय पटले ने बताया कि नशे से दूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत क्षेत्र में लगातार जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ताकि युवाओं सहित आमजन को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराकर समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा सकें।

वारासिवनी में फोर्टिफाइड चावल की हेराफेरी पर एसआईटी का कसता शिकंजा

२२ ट्रक जब्त २ आरोपी पुलिस रिमांड पर ५ आरोपी गये जेल

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। गरीबों के हक का फोर्टिफाइड चावल एथेनॉल प्लांटों, बीयर कंपनियों और खुले बाजार में खपाने वाले अंतरराज्यीय सिंडिकेट के खिलाफ पुलिस और विशेष जांच दल की कार्यवाही लगातार तेज होती जा रही है। वारासिवनी क्षेत्र से उजागर हुए इस बड़े चावल घोटाले में अब तक कुल २२ ट्रकों को जब्त किया जा चुका है। थाना वारासिवनी में दर्ज अपराध क्रमांक २७२/२६ भारतीय न्याय संहिता की धारा ३१६,३,३३६,३, ३४०,२,३३८ एवं ३/५ के तहत दो नए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

यह आरोपियों को अदालत में किया पेश

पुलिस एवं एसआईटी की संयुक्त टीम ने मामले में हाल ही में गिरफ्तार किए गए दो नए आरोपियों में राजेश पिता लूनकरण संचेती निवासी वारासिवनी संचालक संचेती राइस मिल ,विनोद शर्मा निवासी बालाघाट संचालक हर्ष राइस मिल को पूर्व में गिरफ्तार ५ आरोपियों के साथ न्यायालय वारासिवनी के समक्ष पेश किया। जहाँ से राजेश संचेती और विनोद शर्मा को गहन पूछताछ हेतु २९ जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। वहीं पूर्व में गिरफ्तार ५ आरोपी कुंजबिहारी पटले ३८ वर्ष निवासी नैतरा संचालक बिहारी राइस मिल, सुरेन्द्र राणा ६५ वर्ष निवासी नेवरगांव संचालक शांति राइस मिल, अतुल बिसेन २३ वर्ष निवासी नैतरा राइस मिल मैनेजर, गौरव माहेश्वरी ४५ वर्ष निवासी बालाघाट संचालक विराज राइस मिल, किशनलाल खंडेलवाल ७१ वर्ष निवासी गोंदिया महाराष्ट्र संचालक खंडेलवाल राइस मिल को अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

यह हैं घोटाले का तरीका जांच जारी

प्राप्त जानकारी अनुसार जांच में सामने आया है कि एफसीआई और नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से गरीबों के लिए आवंटित फोर्टिफाइड राशन को ट्रकों में भरकर एथेनॉल प्लांटों व बीयर कंपनियों को भेजा जाता था। वहां से यह चावल महंगे दामों में खुले बाजार के राइस मिलर्स को बेचा जाता था। राइस मिलर्स इसी चावल को दोबारा सरकारी कस्टम मिलिंग के नाम पर एफसीआई और नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों में जमा कराकर दोहरा मुनाफा कमाते थे। अब तक २२ ट्रकों की जब्ती इस बात का प्रमाण है कि घोटाले का दायरा अत्यंत व्यापक है। पुलिस रिमांड अवधि के दौरान मुख्य सरगनाओं बेनामी संपत्तियों और अन्य संलिप्त मिलर्स के बारे में कड़ी पूछताछ कर रही है। इस सिंडिकेट में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जिले के कई प्रमुख राइस मिलर्स भी एसआईटी की रडार पर हैं। आने वाले दिनों में और भी वाहनों की जब्ती तथा कई बड़े चेहरों के बेनकाब होने की संभावना है। एसआईटी ने भारतीय खाद्य निगम और मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन के आधिकारिक रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू कर दिए हैं। दस्तावेजों की क्रॉस.चेकिंग की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस मिलर ने कितना सरकारी चावल खपाया और इसका लेन देन कहां कहां तक फैला हुआ है।

आवश्यकता के आधार पर आरोपियों की रिमांड लेकर पुछताछ की जा रही है-एस पी

पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि एसआईटी जांच कर रही थी उनके द्वारा काफी वित्तीय लेखा फोन रिकॉर्ड की जांच की गई जिसके आधार पर दो गिरफ्तारियां की गई है। इसमें संचेती राइस मिल में संचालक के रूप में काम कर रहे वहां पर २ जून २०२६ को एफसीआई से आने वाले चावल को उन्होंने उतरा था राजेश संचेती उन्हें गिरफ्तार किया हैं। उनके साथ ही हर्ष राइस मिल के संचालक से पूछताछ में जो भी चीज सामने आई है उस आधार पर प्रोपराइटर विनोद शर्मा को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया है। इनमें पूर्व में भी गिरफ्तार आरोपी है आवश्यकता के आधार पर रिमांड ली जायेगी।

बुदबुदा रेलवे क्रॉसिंग पर लाई ओवर निर्माण हेतु हो रहा सर्वे कार्य -विक्रम देशमुख

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली को १९/७/२०२६ को शिकायत की गई थी कि वारासिवनी से कटंगी रेलवे स्टेशन के बीच ग्राम धानीटोला बुदबुदा में बी के ३८ नामक रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से आरयूबी अंडरग्राउंड का निर्माण प्रस्तावित किया गया है जिसका कार्य लंबित है। जबकि बीके.३८ लेवल क्रॉसिंग जिला मुख्य मार्ग पर स्थित है और वारासिवनी को कटंगी होते हुए महाराष्ट्र राज्य से जोड़ता है। विक्रम देशमुख के द्वारा अपनी शिकायत में प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा गया था कि इस लेवल क्रॉसिंग से मात्र १४० मीटर की दूरी पर चंदन नदी रोड लेवल से गहराई पर बहती है। जिससे रेलवे के द्वारा प्रस्तावित आरयूबी में जलभराव की स्थिति का अंदेशा रहेगा। साथ ही चूंकि यह जिला मुख्य मार्ग है जिस पर पंद्रह से बीस फ ीट ऊंचाई वाले मालवाहक कंटेनरों का भी आवागमन बाधित होने की आशंका है। उपरोक्त कारणों से विक्रम देशमुख के द्वारा अपनी शिकायत में प्रधानमंत्री कार्यालय भारत शासन को बी के ३८ पर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से एलएचएस के स्थान पर आरयूबी फलाई ओवर निर्माण की मांग की गई थी। जैसा कि इसी रेल मार्ग पर ग्राम वारा और अगासी में आरयूबी फलाई ओवर का निर्माण हो चुका है। विक्रम देशमुख की शिकायत को प्रधानमंत्री कार्यालय ने कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबंधक गति शक्ति दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर अग्रेषित किया गया था। जिसके परिपालन में उप मुख्य अभियंता गति शक्ति दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर ने २१ जुलाई २०२६ को जवाब दिया है कि पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि मांग को देखते हुए नवीनतम रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत सर्वेक्षण चल रहा है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य विक्रम देशमुख के द्वारा जिला मुख्य मार्ग पर स्थित इस रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग विभिन्न शासकीय माध्यमों पर समय समय पर उठाई जा रही है।

नव नियुक्त प्रधानपाठक दामेन्द्र मन्दरेले के द्वारा किया जा रहा नवाचार

एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत १३७ पौधों का किया रोपण

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व सम्मान को समर्पित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला किन्ही में एक सराहनीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत २४ जुलाई को १३७ पौधों का रोपण कर विद्यालय परिसर और आसपास हरियाली बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। विद्यालय में यह सकारात्मक बदलाव उस समय से देखने को मिल रहा है जब प्रधान पाठक दामेन्द्र कुमार मन्दरेले ने १ जुलाई को शाला का प्रभार संभाला। प्रभार लेते ही उन्होंने विद्यालय में कई नवाचारों की शुरुआत की जिससे शिक्षण व्यवस्था और विद्यार्थियों की दिनचर्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार प्रधान पाठक के द्वारा एमडीएम का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है और बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही विद्यालय में प्रार्थना सभा को भी व्यवस्थित किया गया है, जिसमें लाउडस्पीकर के माध्यम से गायन प्रेरणादायक संदेश और बाल सभा का आयोजन किया जा रहा है। इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का विकास हो रहा है। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। बच्चों ने स्वयं पौधे लगाए और उनकी देखरेख का संकल्प भी लिया। इस पहल का उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधान पाठक दामेन्द्र कुमार मन्दरेले ,रश्मि तुरकर, माया आमाडारे, निशा अर्जे, प्रेमलता बागड़े, प्रेमलता तुरकर, संतोष लिल्हारे, नीरज बनोटे, रामचंद कातरे एवं समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ग्रामीणों पालकों और छात्र.छात्राओं में इस सकारात्मक बदलाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी का कहना है कि प्रधान पाठक द्वारा प्रभार संभालते ही विद्यालय में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, जिससे शाला का माहौल बेहतर हुआ है और बच्चों के सर्वांगीण विकास को नई दिशा मिली है। विद्यालय परिवार की यह पहल ना केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और सुधार का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी बनकर सामने आई है।

महाराजपुर में जंगली सुअरों का आतंक,खरीफ सीजन में किसान हलाकान

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत महाराजपुर में इन दिनों किसान जंगली सुअरों के बढ़ते आतंक से बेहद परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुअरों का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को अपने ही खेतों में आवागमन करने में भारी डर और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खेतों और आसपास के इलाकों में झुंड के झुंड घूमते जंगली सूअर देखना अब आम बात हो गई है। जिससे पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण निर्मित हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में खरीफ का सीजन अपने चरम पर है और किसान खेती किसानी के कार्यों में दिन रात जुटे हुए हैं। खेतों में धान की रोपाई का कार्य युद्ध स्तर पर चालू है लेकिन जंगली सुअरों की बिन बुलाई मौजूदगी से यह पूरा काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। किसानों के द्वारा बड़ी मेहनत से लगाए गए नए रोपे धान के पौधों को ये सूअर अपने पैरों से रोंदते हुए भाग रहे हैं जिससे किसानों की हफ्तों की मेहनत और पूंजी पल भर में बर्बाद हो रही है। केवल मुख्य खेत ही नहीं बल्कि जंगली सुअरों का यह दल ग्रामीणों के घर के आसपास बनी बाडियों में भी बेधड़क घुस रहा है। बाड़ियों में उगाई गई सूरन, घुइयां एवं अन्य कंद वाली फसलों को सूअर मिट्टी खोदकर पूरी तरह खा रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही खेतों के धूरे को तोड़कर ये फसलों की सिंचाई और सीमांकन व्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। सुअरों का आतंक केवल फसलों की तबाही तक सीमित नहीं है बल्कि यह किसानों की जान पर भी बन आया है। खेतों में काम करने के दौरान कई बार जंगली सुअरों ने किसानों पर सीधे हमले की कोशिश भी की है। हालांकि किसानों की सजगता और एकजुटता के कारण वे किसी तरह सुअरों को खदेड़ने और खुद को बचाने में सफल हो रहे हैं जिससे अब तक कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई है। लेकिन हर वक्त मंडराते इस खतरे के कारण भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका से ग्रामीण थर.थर कांप रहे हैं। लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान और जान माल के खतरे को देखते हुए महाराजपुर के पीड़ित किसानों ने शासन प्रशासन एवं संबंधित वन विभाग से गुहार लगाई है,कि खेतों और गांव के सीमावर्ती इलाकों में जंगली सुअरों की रोकथाम के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जायें।

जंगली सूअर के आंतक से ग्रामीणजन बहुत परेशान है- रामेश्वर गजभिये

किसान रामेश्वर गजभिये ने बताया की खेतों में जंगली सूअर का मुद्दा काफ ी संवेदनशील है। आज सुबह की ही बात है मैं अपने खेत गया हुआ था जहां ६ जंगली सूअर झुंड में खेतों से जंगल की तरफ जा रहे थे। मेरे साथ मेरा परिवार था वह दौड़ते हुए जंगल की तरफ गई कभी हमारे तरफआती तो एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। ऐसे दो.तीन दिन में झुंड दिखता रहता है उनकी बहुत ज्यादा तादाद हो गई है हर समय डर लगा रहता है। काफी सजगता के साथ खेतों में आना जाना करना पड़ता है कई बार तो झाड़ियां में छिपी होती है। खेतों में बहुत ज्यादा नुकसान भी यह कर रही है इस विषय पर जिम्मेदार अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए ताकि किसान सुरक्षित अपना खेती कर सके। इनका कोई समय निर्धारित नहीं है कभी भी यह किधर भी देखने के लिए मिल जाती है।

जंगली सूअर को प्रशासन ने जंगल की ओर छोड़ना चाहिये-मनोज साहू

किसान मनोज साहू ने बताया कि खेतों में अभी रोपाई का कार्य चल रहा है कई जगह हो गया है। यह जंगली सूअर झुंड में खेतों के बीच से दौड़ती है जो रोपाई को रौंद रही है वहीं कई बार किसानों पर भी हमला कर देती है ,परंतु किसान बच जाते हैं। यह ऐसा पशु है जिसे किसान हाथ भी नहीं लगा सकता है अन्यथा विभाग उन्हें जेल में डाल देगा परंतु यह किसान का नुकसान करता है। एक तो उसकी फसलों को नुकसान पहुंचाएगा या उस पर विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार शिकायत की गई है और यह एक जगह की बात नहीं है हर जगह आपको यह जंगली सूअर का आतंक देखने मिलेगा। हमारे यहां तो ४ किसान मिलकर खेतों की तरफ जाते हैं या उन्हें पता रहता है कि खेत में लोग है तब वह वहां जाते हैं इनका बंदोबस्त किया जाना चाहिए।

आबादी भूमि की रजिस्ट्री पर नहीं लगेगा कर -गौरव सिंह पारधी

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम १९८१ में हुए संशोधन से पहुंचेगा सीधे ग्रामीणों को लाभ

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। मध्यप्रदेश विधानसभा में मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम १९८१ में संशोधन पर चर्चा के दौरान कटंगी खैरलांजी विधायक गौरव सिंह पारधी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का आभार व्यक्त किया और कहा की राज्य सरकार ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी की जमीन का कानूनी मालिकाना हक दिलाने का काम कर रही है। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम १९८१ में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी की जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाला सेस उपकर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब गांवों के लाखों परिवार बिना इस अतिरिक्त शुल्क के अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और अपनी भूमि का कानूनी मालिकाना हक प्राप्त करने का रास्ता भी आसान होगा। विधायक गौरवसिंह पारधी ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लोगों को उनकी आबादी की जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है। पहले इस रजिस्ट्री पर सेस उपकर देना पड़ता था लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है। इससे ग्रामीण परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और वे बिना अतिरिक्त बोझ के अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास वर्षों से जमीन थी लेकिन उसके वैध दस्तावेज नहीं थे उन्हें अब कानूनी स्वामित्व मिलेगा। इससे भविष्य में जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे और ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार मिलेगा। उन्होंने सभी ग्रामीण नागरिकों को इस महत्वपूर्ण फैसले पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार गांव के लोगों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

क्रिएटिव इंटरनेशनल एकेडमी किन्ही में आज होगा छात्र संसद का लोकतांत्रिक चुनाव

भविष्य के जागरूक मतदाताओं को तैयार कर रहा है सीआईए

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। क्रिएटिव इंटरनेशनल एकेडमी किन्ही में २५ जुलाई २०२६ दिन शनिवार को छात्र परिषद के मुख्य पदों हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए पूरी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। यह चुनावी प्रक्रिया केवल स्कूल के लीडर्स चुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को देश के जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। संस्था के प्राचार्य तुलमोहन भोयर ने बताया कि इस अनूठी पहल के जरिए सीआईए किन्ही अपने विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यो, मतदान के महत्व और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया का व्यावहारिक ज्ञान दे रहा है। विद्यालय का मानना है कि आज के ये नन्हे छात्र ही आने वाले समय में देश के भविष्य के मतदाता हैं, जिन्हें सही और पारदर्शी नेतृत्व चुनने के लिए अभी से तैयार किया जा रहा है। इस चुनाव को पूरी तरह से वास्तविक आम चुनावों की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बकायदा उम्मीदवारों का नामांकन, चुनाव प्रचार और गुप्त मतदान शामिल है। छात्र छात्राएं खुद अपने मत का प्रयोग कर अपने सबसे योग्य प्रतिनिधियों को चुनेंगे। संस्थान के प्रबंधन और शिक्षकों के मार्गदर्शन में होने वाले इस आयोजन को लेकर स्कूल के छात्र छात्राओं में भारी उत्साह और उत्सुकता का माहौल है। आज होने वाली इस वोटिंग के बाद जल्द ही परिणाम घोषित किए जाएंगे और विजेता छात्र नेताओं को शपथ दिलाई जाएगी।

छात्रों के भविष्य पर सियासत का संग्राम

देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद का उद्देश्य सरकार से जवाब मांगना, कानून बनाना और जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करना है। वहीं लोकतंत्र में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब संसद का बहुमूल्य समय लगातार हंगामे की भेंट चढ़ने लगे और सड़क पर चल रहे आंदोलनों का स्वर समाधान से अधिक राजनीतिक टकराव का प्रतीक बन जाए, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है। इसका सीधा उत्तर है—देश के छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों का। नीट पेपर लीक का मामला अत्यंत गंभीर है। करोड़ों परिवारों की उम्मीदें प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी होती हैं। यदि परीक्षा की गोपनीयता भंग होती है तो केवल प्रश्नपत्र नहीं लीक होता, बल्कि लाखों विद्यार्थियों का विश्वास भी टूटता है। इसलिए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है। केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। सरकार ने संसद में यह भी कहा कि वह इस विषय पर किसी भी दिन और किसी भी अवधि की चर्चा के लिए तैयार है। इसके बावजूद संसद के मानसून सत्र में गतिरोध बना रहा। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को चर्चा की पूर्व शर्त बना दिया। संसद के बाहर इंडिया गठबंधन और एनडीए के सांसद आमने-सामने आ गए। नारेबाजी हुई, आरोप-प्रत्यारोप हुए और दोनों सदनों की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन यदि संसद ही चर्चा का मंच न बन सके तो फिर जवाबदेही किस प्रकार तय होगी। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। यह उनका राजनीतिक अधिकार है। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि जांच चल रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है और चर्चा के लिए वह तैयार है। ऐसे में लोकतांत्रिक परंपरा यही अपेक्षा करती है कि पहले संसद में खुली बहस हो, तथ्यों पर चर्चा हो और उसके बाद राजनीतिक निष्कर्ष निकाले जाएं। यदि हर विषय पर पहले इस्तीफे की शर्त रखी जाएगी तो संसदीय विमर्श की परंपरा कमजोर होगी। वर्तमान घटनाक्रम का दूसरा पक्ष जंतर-मंतर पर चल रहा आंदोलन है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरी तरह वैध है, लेकिन जब किसी आंदोलन के दौरान हिंसा, पुलिस से टकराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या आम नागरिकों के जीवन को बाधित करने जैसे आरोप सामने आते हैं, तब आंदोलन की नैतिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। यदि किसी प्रदर्शन में कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस का कर्तव्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। वहीं पुलिस की कार्रवाई भी कानून के दायरे में और निष्पक्ष होनी चाहिए। दोनों पक्षों की जवाबदेही लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भी देख रहा है। छात्र और युवा हर चुनाव में महत्वपूर्ण मतदाता होते हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल स्वयं को युवाओं का सबसे बड़ा हितैषी दिखाना चाहता है। यही कारण है कि नीट का मुद्दा केवल परीक्षा व्यवस्था तक सीमित न रहकर राजनीतिक संघर्ष का प्रमुख विषय बन गया है। लेकिन इस पूरी कवायद में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या छात्रों की वास्तविक समस्याएं केंद्र में हैं या राजनीतिक लाभ? इतिहास भी बताता है कि परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाएं केवल किसी एक सरकार या एक राजनीतिक दल के कार्यकाल तक सीमित नहीं रही हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के समय भी विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पेपर लीक तथा धांधली के मामले सामने आए थे। इससे स्पष्ट है कि यह समस्या राजनीतिक दलों से अधिक परीक्षा व्यवस्था की संस्थागत कमजोरियों से जुड़ी है।

लोकतंत्र में धरना-प्रदर्शन-जनहित का संवैधानिक अधिकार या दलगत टकराव का अखाड़ा?

वैश्विक स्तरपर भारत का लोकतंत्र अपनी सबसे बड़ी शक्ति जनता की भागीदारी, असहमति के सम्मान और शांतिपूर्ण विरोध की परंपरा से प्राप्त करता है।किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना,प्रदर्शन, सत्याग्रह और जनआंदोलन केवल विरोध के साधन नहीं होते,बल्कि वे शासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करने के संवैधानिक माध्यम भी माने जाते हैं। भारत की सभ्यता में भी अहिंसक प्रतिरोध की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है,जिसे आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन के रूप में विश्व के सामने स्थापित किया।स्वतंत्रता संग्राम से लेकर किसानों,मजदूरों,छात्रों, महिलाओं और सामाजिक संगठनों तक,शांतिपूर्ण आंदोलनों ने समय-समय पर सरकारों को जनभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।यही लोकतंत्र की आत्मा है कि सरकार और विपक्ष दोनों जनता के प्रति जवाबदेह रहें तथा मतभेदों का समाधान संविधान और संवाद के माध्यम से खोजें। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि समय के साथ-साथ आंदोलन की प्रकृति में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देने लगा है। आज अनेक अवसरों पर यह धारणा बनती जा रही है कि कई आंदोलन जनहित और नीति-सुधार से अधिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और दलगत हितों के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गए हैं। जनता के एक वर्ग में यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या धरना-प्रदर्शन अब लोकतांत्रिक विमर्श का माध्यम रह गए हैं,अथवा वे राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का उपकरण बनते जा रहे हैं? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच के समानांतर सड़क पर संघर्ष की राजनीति बढ़ती दिखाई दे रही है।इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2026 का मानसून संसद सत्र विशेष चर्चा का विषय बन गया है। 20 जुलाई से प्रारंभ हुए संसद सत्र के साथ ही विभिन्न विपक्षी दलों ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई ।यू.जीसी-नेट,शिक्षा व्यवस्था,छात्रों के मुद्दे,कथित पुलिस कार्रवाई तथा शिक्षामंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर आक्रामक रुख अपनाया, दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी आंदोलन को व्यापक राजनीतिक समर्थन मिलने लगा,जिसमें विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं की भागीदारी ने इसे केवल एक छात्र या सामाजिक आंदोलन न रहने देकर राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना दिया।अब धरना स्थल पर भगदड़, पीएम के आवास पर धरना, फिर 22 जुलाई 2026 को सत्ताधारी पार्टी द्वारा भी आंदोलन धरना व तेलंगाना में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की झड़प यह सब मीडिया में आ रहा है जिसे जनता, मतदाता व पूरा विश्व देख रहे हैं।

साथियों इसी क्रम में पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आंदोलन को भी विपक्ष ने समर्थन दिया। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की गई और न्यायालय के सुझाव के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे आंदोलन को मानवीय और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से व्यापक चर्चा मिली। लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है,किंतु जब ऐसे आंदोलनों के साथ राजनीतिक दल खुलकर जुड़ते हैं तो आंदोलन का स्वरूप स्वत: व्यापक राजनीतिक बहस का विषय बन जाता है। सरकार इसे राजनीतिकरण कहती है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक समर्थन बताता है। दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं, किंतु अंतिम निर्णय जनता की लोकतांत्रिक समझ पर ही सटीकता से निर्भर करता है।

साथियों, इन घटनाओं के समानांतर संसद के भीतर भी लगातार हंगामा, नारेबाजी, स्थगन और बहिर्गमन जैसी स्थितियां देखने को मिलीं।संसद का प्रत्येक मिनट राष्ट्रीय संसाधनों,करदाताओं के धन और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व से जुड़ा होता है। जब 25 दिन के निर्धारित संसदीय सत्र का बड़ा हिस्सा व्यवधानों में व्यतीत होता है,तबस्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या जनहित से जुड़े विधेयक, आर्थिक सुधार, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर्याप्त चर्चा प्राप्त कर पाएंगे ?लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार से कठोर प्रश्न पूछना है, वहीं सरकार का दायित्व उत्तर देना और संसद चलाना है। यदि दोनों पक्ष संवाद के स्थान पर केवल टकराव का मार्ग अपनाते हैं तो अंतत: नुकसान सटीकता से जनता का होता है।

साथियों, स्थिति तब और अधिक गंभीर दिखाई दी जब संसद के बाहर पीएम के आधिकारिक आवास के निकट प्रमुख विपक्षी पार्टी द्वारा धरना-प्रदर्शन किया गया।प्रदर्शन का मुख्य आधार नीट पेपर लीक,छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई तथा शिक्षा संबंधी मुद्दे बताए गए।विपक्ष का कहना था कि वह छात्रों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहता है, जबकि सत्तापक्ष ने इसे सुरक्षा व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं के विरुद्ध राजनीतिक प्रदर्शन बताया। पीएम आवास जैसे अति- संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन ने स्वाभाविक रूप से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई और राजनीतिक वातावरण और अधिक गर्म हो गया।इसके तुरंत बाद प्रमुख सत्ताधारी पार्टी ने भी प्रमुख विपक्षी पार्टी के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन प्रारंभ कर दिए।अनेक राज्यों में प्रमुख सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और विपक्ष के आरोपों का प्रतिवाद किया।यह घटनाक्रम लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का स्वाभाविक हिस्सा माना जा सकता है, किंतु जब जवाबी प्रदर्शन भी समान तीव्रता से शुरू होते हैं तो राजनीतिक तनाव कई गुना बढ़ जाता है। तेलंगाना सहित कुछ स्थानों पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों की मीडिया में आई खबरों ने चिंता और बढ़ा दी। लोकतंत्र में विचारों का संघर्ष स्वीकार्य है,परंतु यदि वह शारीरिक टकराव का रूप लेने लगे तो लोकतांत्रिक संस्कृति कमजोर पड़ने लगती है।

साथियों,आज सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के युग में भारत की प्रत्येक राजनीतिक गतिविधि केवल देश की जनता ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व भी देखता है। भारत स्वयं को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसे में संसद के भीतर लगातार व्यवधान, सड़क पर राजनीतिक संघर्ष, आरोप-प्रत्यारोप और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतांत्रिक परिपक्वता के संदर्भ में चर्चा का विषय बनते हैं। लोकतंत्र की शक्ति केवल चुनावों में नहीं, बल्कि असहमति को गरिमा के साथ संभालने की क्षमता में भी निहित होती है।

साथियों,राजनीतिकविश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि जनता अब केवल भाषणों और नारों के आधार पर निर्णय नहीं करती। मतदाता शिक्षा, रोजगार, महंगाई, कृषि स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कानून-व्यवस्था और आर्थिक अवसरों जैसे ठोस मुद्दों पर सरकार और विपक्ष दोनों का मूल्यांकन करता है। यदि संसद का समय बार-बार हंगामे में व्यतीत होता है और जनहित के प्रश्न पीछे छूट जाते हैं, तो मतदाता दोनों पक्षों के आचरण का आकलन अपने अनुभव और अपेक्षाओं के आधार पर करता है।इसलिए कई विश्लेषक यह संभावना व्यक्त करते हैं कि अंतत: जनता अपने मताधिकार के माध्यम से राजनीतिक दलों के व्यवहार पर प्रतिक्रिया देती है। यह प्रतिक्रिया किसके पक्ष में जाएगी, इसका निर्णय केवल चुनाव परिणाम ही करते हैं; इसलिए किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना उचित नहीं होगा।

साथियों,लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक सशक्त विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाता है, नीतियों की समीक्षा करता है और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह आलोचना को लोकतांत्रिक भावना से सुने, संवाद के अवसर बनाए और आवश्यक होने पर सुधारात्मक कदम उठाए। यदि दोनों पक्ष संवाद छोड़कर केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण को प्राथमिकता देंगे, तो लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होगी।जनता पर इन घटनाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव भी कम नहीं पड़ता। संसद का कामकाज बाधित होने से अनेक विधेयकों, नीतिगत चर्चाओं और जनहित से जुड़े निर्णयों में विलंब हो सकता है। दूसरी ओर,संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धरना- प्रदर्शन होने से आम नागरिकों को यातायात, सुरक्षा जांच और दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करनापड़ता है। तीसरा प्रभाव लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास पर पड़ता है। यदि नागरिकों को यह महसूस होने लगे कि समस्याओं का समाधान संसद के बजाय केवल सड़क पर संघर्ष से ही संभव है, तो संस्थागत लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार दिया है। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई है कि इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप हो। इसी प्रकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा रहती है कि वे संसद और विधानसभाओं को संवाद, बहस और नीति- निर्माण का सर्वोच्च मंच बनाए रखें। यदि सड़क और संसद दोनों स्थानों पर केवल टकराव ही दिखाई देगा,तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रभावशीलता पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेंगे।

साथियों, विश्व के अनेक परिपक्व लोकतंत्रों में भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, किंतु अंतत: अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय संसदीय समितियों, विधायी बहसों, न्यायिक समीक्षा और संस्थागत संवाद के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए भी यही मार्ग अधिक टिकाऊ और लोकतांत्रिक माना जाता है। आंदोलन लोकतंत्र की शक्ति हैं, परंतु आंदोलन का उद्देश्य समाधान होना चाहिए, स्थायी टकराव नहीं।आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार विपक्ष की चिंताओं को गंभीरता से सुने, विपक्ष संसद की कार्यवाही को प्रभावी ढंग से चलने दे और दोनों पक्ष राष्ट्रीय हित को दलगत हितों से ऊपर रखें। जनता ने जनप्रतिनिधियों को संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि समस्याओं का समाधान खोजने के लिए चुना है। संसद में बहस जितनी मजबूत होगी, लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा।

अत: अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विशेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत का लोकतंत्र आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहाँ संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और जनअपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। धरना-प्रदर्शन लोकतंत्र की आत्मा हैं, किंतु उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करना होना चाहिए, न कि संस्थाओं को कमजोर करना। संसद का प्रत्येक दिन देश के भविष्य से जुड़ा है; इसलिए उसका अधिकतम उपयोग होना चाहिए। अंतत: लोकतंत्र का अंतिम निर्णायक न सरकार होती है,न विपक्ष बल्कि भारत का जागरूक मतदाता होता है,जो समय आने पर अपने मताधिकार के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के आचरण, जवाबदेही और प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करता है। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।

-किशन सनमुखदास भावनानी

प्रधान का इस्तीफा और सौ सियासी डर- जेन ज़ी के चक्रव्यूह में घिरी मोदी सरकार

-दिलीप कुमार पाठक

भारत का लोकतंत्र इस समय एक अभूतपूर्व चौराहे पर खड़ा है। देश के कोने-कोने में छात्रों का एक ऐसा स्वत:स्फूर्त और विशाल आंदोलन खड़ा हो गया है, जिसने सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया है। नीट और अन्य बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं ने देश के नौजवानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। यह केवल किसी एक परीक्षा की विफलता का मामला नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भरोसे, उनकी दिन-रात की कड़ी मेहनत और सुनहरे भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई बन चुका है। इसी गुस्से के बीच देश की संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, जो पूरी तरह से इस छात्र आंदोलन की आंच में झुलस रहा है और देश की सर्वोच्च पंचायत पूरी तरह ठप हो चुकी

है। मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष ने छात्रों के समर्थन में संसद के दोनों सदनों में सरकार को पूरी तरह घेरने का कड़ा रुख अपनाया है। सत्र के पहले दिन से ही नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है और उसका यह कड़ा रुख विधायी कार्यों पर पूरी तरह भारी पड़ रहा है। अगर अब तक की संसदीय कार्यवाही पर नजर डालें, तो दोनों सदनों में नाममात्र का काम हुआ है। कार्यवाही हर रोज हंगामे की भेंट चढ़ रही है। राज्यसभा और लोकसभा को लगातार स्थगित करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई बार सदन शुरू होने के दस मिनट के भीतर ही बंद करना पड़ता है। विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, वेल में आकर विरोध जता रहे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सरकार भले ही सिर्फ चर्चा कराने का दावा कर रही हो, लेकिन विपक्ष की साफ मांग है कि चर्चा से पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिसके कारण यह गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।इस पूरे मामले में विपक्ष और आंदोलनकारी छात्रों का रुख बिल्कुल स्पष्ट और कड़ा है। उनका कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। विपक्ष का मानना है कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री की बनती है। विपक्षी दलों का साफ कहना है कि जब तक मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक वे सदन के भीतर किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होंगे। इस बीच संकट को टालने और छात्रों को शांत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं को निष्पक्ष जांच और न्याय का भरोसा दिलाया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि देश के आक्रोशित छात्र अब सरकार के इस डिजिटल आश्वासन और कोरे विश्वास को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आधी रात को बने इस वीडियो का बेअसर होना सीधे तौर पर मोदी सरकार की साख और उसकी मजबूत छवि पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। एक तरफ जहां छात्र सड़कों पर डटे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कभी न झुकने वाली मोदी सरकार अपनी इस मजबूत और सख्त छवि को हर हाल में बनाए रखना चाहती है। सरकार की यह पुरानी कार्यशैली रही है कि वह किसी भी बाहरी आंदोलन या विपक्ष के दबाव में आकर अपने मंत्रियों के इस्तीफे नहीं लेती, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से उसकी राजनीतिक कमजोरी उजागर होगी। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ छवि की नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक डर भी काम कर रहा है। प्रधानमंत्री यह बखूबी जानते हैं कि आंदोलनकारी छात्रों का यह गुस्सा सिर्फ एक मंत्रालय तक सीमित नहीं रहेगा। यदि सरकार ने दबाव में आकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, तो आंदोलनकारियों के हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद यह आंदोलन थमेगा नहीं, बल्कि विपक्ष और छात्र अन्य मंत्रालयों की नाकामियों को लेकर खुद प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ जाएंगे।

सरकार को डर है कि एक बार इस्तीफे का सिलसिला शुरू हुआ, तो देश भर के युवा इस सत्ता के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोल देंगे, जिसे संभालना सरकार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। डोमिनो इफेक्ट का यही डर सरकार को कदम पीछे खींचने से रोक रहा है। इस आंदोलन की सबसे अनोखी और बड़ी बात यह है कि पूरे देश में यह विरोध प्रदर्शन बेहद तेज और आधुनिक हो चुका है। अब यह लड़ाई सिर्फ दिल्ली की सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर राज्य और हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैल चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार सत्ताधारी दल भाजपा की पूरी आईटी सेल और उनका विशाल सोशल मीडिया तंत्र इस युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ी के आगे पूरी तरह बेअसर और नाकाम साबित हो रहा है। तकनीक और मीम्स के दौर में जीने वाली यह नई पीढ़ी डिजिटल स्पेस में सत्ता के हर नैरेटिव को ध्वस्त कर रही है। भाजपा की आईटी सेल युवाओं के इस गुस्से को भटकाने की जितनी कोशिश कर रही है, जेन ज़ी उतने ही कड़े और तार्किक सवालों के साथ सोशल मीडिया पर भारी पड़ रही है। सड़क से लेकर स्क्रीन तक युवा पूरी तरह हावी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह उठता है कि आखिर यह आंदोलन कहां जाकर रुकेगा? एक तरफ देश का भविष्य यानी छात्र सड़कों पर लाठियां और आंसू गैस झेलते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता का अहंकार और राजनीतिक शह-मात का खेल चल रहा है। संसद ठप पड़ी है, जनता के पैसे और समय की बर्बादी हो रही है, लेकिन समाधान की कोई राह नजर नहीं आ रही। जब तक सरकार अपनी अड़ियल छवि से बाहर निकलकर छात्रों के प्रति वास्तविक संवेदनशीलता और जवाबदेही नहीं दिखाएगी, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह गतिरोध तब तक बना रहेगा जब तक कि सत्ता छात्रों के भविष्य को अपनी राजनीतिक साख से ऊपर रखना नहीं सीख लेती।

आतंकवाद का बदलता चेहरा और भारत की जीरो टॉलरेंस नीति

सोशल मीडिया से ब्रेनवॉश और क्रिप्टो फंडिंग तक आतंक का नया जाल, लेकिन सतर्क सुरक्षा एजेंसियां हर साजिश को कर रही हैं नाकाम

आतंकवाद का स्वरूप समय के साथ लगातार बदलता रहा है। कभी सीमा पार से घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और प्रत्यक्ष प्रशिक्षण इसके प्रमुख साधन हुआ करते थे, लेकिन तकनीक के विस्तार ने आतंकवादी संगठनों को नए रास्ते उपलब्ध करा दिए हैं। अब आतंक का नेटवर्क बंदूक और बारूद से कहीं अधिक मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्रिप्टोकरेंसी के सहारे संचालित हो रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हालिया कार्रवाई और विभिन्न मामलों में दायर आरोपपत्रों ने इस बदलते स्वरूप की स्पष्ट तस्वीर सामने रखी है। जांच से यह संकेत मिला है कि आतंकवादी संगठन अब एक सुनियोजित थ्री-एप मॉडल के माध्यम से युवाओं को अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले सोशल मीडिया के जरिए संपर्क स्थापित किया जाता है, फिर एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर वैचारिक कट्टरता फैलाकर ब्रेनवॉश किया जाता है और अंत में क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह नया मॉडल केवल तकनीकी बदलाव नहीं है बल्कि आतंकवाद की रणनीति में आया बड़ा परिवर्तन भी है। पहले आतंकवादी संगठनों को भर्ती और संपर्क के लिए भौतिक नेटवर्क की आवश्यकता होती थी, जबकि अब इंटरनेट ने दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति तक उनकी पहुंच आसान बना दी है। सोशल मीडिया पर सामान्य धार्मिक या वैचारिक सामग्री के माध्यम से युवाओं का विश्वास जीतने का प्रयास किया जाता है। धीरे-धीरे उन्हें बंद समूहों में जोड़ा जाता है जहां उग्र और हिंसक विचारधारा से परिचित कराया जाता है। इसके बाद हथियारों, विस्फोटकों और आतंकी गतिविधियों से संबंधित सामग्री साझा कर उन्हें हिंसा के रास्ते पर धकेलने की कोशिश की जाती है। एनआईए की जांच में सामने आए विभिन्न मॉड्यूल इस नए खतरे की गंभीरता को दर्शाते हैं। तमिलनाडु में ऐसे समूहों का पता चला जिनमें सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड एप के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया। विजयवाड़ा से जुड़े मामले में विदेशी हैंडलरों के संपर्क, भारत में कट्टरपंथ फैलाने और प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने जैसी योजनाओं का खुलासा हुआ। मंगलुरु मॉड्यूल में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विस्फोटक बनाने की जानकारी और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात सामने आई। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि आतंकवादी संगठन अब पारंपरिक नेटवर्क से अधिक डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होते जा रहे हैं। इन मॉड्यूल का सबसे चिंताजनक पक्ष यह है कि इनके निशाने पर 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के पढ़े-लिखे युवा हैं। यह वर्ग इंटरनेट और सोशल मीडिया का सबसे अधिक उपयोग करता है। आतंकवादी संगठन इसी मनोविज्ञान का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। वे पहले धार्मिक, सामाजिक या भावनात्मक विषयों पर चर्चा के बहाने संपर्क स्थापित करते हैं और धीरे-धीरे युवाओं को कट्टर विचारधारा की ओर मोड़ते हैं। कई बार यह पूरी प्रक्रिया इतनी सुनियोजित होती है कि व्यक्ति को स्वयं यह एहसास भी नहीं होता कि वह किस प्रकार एक खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा बनता जा रहा है। तकनीक के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग भी आतंकवाद के लिए नई चुनौती बनकर उभर रहा है। फर्जी वीडियो, परिवर्तित आवाज, नकली पहचान और स्वचालित संदेशों के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। एन्क्रिप्टेड संचार के कारण जांच एजेंसियों के लिए इन नेटवर्क तक पहुंचना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो जाता है। वहीं क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होने वाला लेन-देन पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से अलग होने के कारण इसकी निगरानी भी चुनौतीपूर्ण रहती है। यही कारण है कि आधुनिक आतंकवाद केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा और तकनीकी क्षमता का भी विषय बन चुका है। हालांकि इन चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा और जांच एजेंसियों की सतर्कता लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, विभिन्न राज्यों की आतंकवाद निरोधी इकाइयां, खुफिया एजेंसियां और साइबर विशेषज्ञ समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। देशभर में लगातार छापेमारी, संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों की निगरानी, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान और समय रहते कार्रवाई के कारण अनेक साजिशों को विफल किया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि आतंकवादी संगठन चाहे जितनी नई तकनीक अपनाएं, भारतीय सुरक्षा तंत्र भी उसी गति से अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता के साथ लागू किया है। इस नीति का मूल उद्देश्य यह है कि आतंकवाद के प्रति किसी भी स्तर पर नरमी न बरती जाए। चाहे सीमा पार से संचालित नेटवर्क हों, देश के भीतर सक्रिय मॉड्यूल हों या आर्थिक सहायता पहुंचाने वाले तंत्र, सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। यही कारण है कि अनेक आतंकी संगठन आज पहले की तुलना में काफी कमजोर पड़े हैं। उनके पारंपरिक नेटवर्क लगातार ध्वस्त हुए हैं और उन्हें नए-नए तरीके अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह भी सच है कि आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए लगातार नए रास्ते खोज रहे हैं। कभी सोशल मीडिया, कभी एन्क्रिप्टेड एप, कभी क्रिप्टोकरेंसी और कभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर वे अपनी मौजूदगी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरी ओर भारत की खुफिया और जांच एजेंसियां भी समान रूप से सजग हैं। वर्षों के अनुभव, आधुनिक तकनीक और मजबूत समन्वय के कारण वे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में पहले से कहीं अधिक सक्षम हुई हैं। अनुभवी अधिकारी व्यवहार, डिजिटल गतिविधियों और संदिग्ध संपर्कों का विश्लेषण कर समय रहते खतरे का आकलन कर लेते हैं। यही सतर्कता अनेक संभावित घटनाओं को घटित होने से पहले ही रोक देती है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष केवल सुरक्षा एजेंसियों का दायित्व नहीं है बल्कि समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संगठन और सामाजिक संस्थाएं युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। डिजिटल साक्षरता, तथ्य आधारित सोच और अफवाहों से बचने की आदत विकसित करना आज की आवश्यकता है। यदि समाज जागरूक रहेगा तो आतंकवादी संगठनों के लिए युवाओं को भ्रमित करना कठिन हो जाएगा। भारत ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वह आतंकवाद के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करेगा। सीमा पर कठोर सुरक्षा व्यवस्था, देश के भीतर मजबूत जांच तंत्र, आधुनिक तकनीक का उपयोग और जीरो टॉलरेंस की नीति ने आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को लगातार सीमित किया है। यदि कोई आतंकी नेटवर्क भूमिगत होकर छिपने का प्रयास भी करता है तो सुरक्षा एजेंसियां उसे खोज निकालने और कानून के दायरे में लाने के लिए निरंतर सक्रिय रहती हैं। यही दृढ़ इच्छाशक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद का स्वरूप चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, उसका उद्देश्य समाज में भय, अस्थिरता और विभाजन पैदा करना ही होता है। इसके मुकाबले के लिए केवल हथियार नहीं बल्कि तकनीकी दक्षता, मजबूत खुफिया तंत्र, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। भारत ने इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यही कारण है कि आतंकवाद का नया डिजिटल मॉडल भी भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के सामने लंबे समय तक सफल नहीं हो पाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति, सतर्क सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता और जागरूक नागरिकों के सहयोग से आतंकवाद के हर नए रूप का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है। यही राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है।

-कांतिलाल मांडोत

इंदौर बाजार भाव

इंदौर। एजेंसी। श्रावणी माँग के चलते शुक्रवार को किराना जिंसों में नारियल बाजार बड़त पर रहे। शक्कर में मजबूती रही। खाद्य तेलों में सुधार कायम रहा। तिलहनों में सोयाबीन व सरसो बाजार बड़त पर रहे। दलहनों में चना सुस्ती पर रहा। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार नारियलों में आवकें सामान्य है। नारियलों में आवक 5 गाड़ी की रही। श्रावणी माँग के चलते भावों में तेजी देखी गयी। शक्कर में बाजार सुधार के रहे। खाद्य तेलों में व्यापार सामान्य ही रहा। तिलहनों में सोयाबीन व सरसो में बाजार बढ़त पर देखे गये। दलहनों में चना गुरूवार के मुकाबले सुस्ती पर रहा। भाव इस प्रकार रहे-

किराना- शक्कर 4720-4830, खोपरा गोला 375-420, खोपरा बूरा 3200-6800 (15 कि.ग्रा.), जीरा राजस्थान 280-285, ऊंझा हल्का 290-295, बेस्ट 315-325, हल्दी निजामाबाद 210-230, सांगली 275-280, साबूदाना हल्का 5200-5350, मीडियम 5450-5600, बेस्ट 6000-6100, सच्चा मोती 5700, मोरधन 7200-8200, सौंफ मोटी 275-350, बेस्ट 350-400, सौंफ बारिक 180-300, एक्स्ट्रा बोल्ड 350-400, राई दाल 90-95, सरसो दाल 85-95, कालीमिर्च एटम 750-755, मीनी मटरदाना 770-800, मटरदाना 825-850, खसखस अनक्लीन 1150-1250, क्लीन 1300-1350, दालचीनी 250-260, जायफल 725-750, वाद्यान फूल 405-600, शाहजीरा 350-400, तेजपान 90-100, पत्थर फूल 235-425, जावत्री 1675-1750, केसर 200-250, नाग केसर 925-975, सौंठ 325-500, धोली मूसली 1400-1600, लौंग 700-720, बेस्ट 760-790, हींग (वनदेवी 751) 3450, पाउच 10 ग्राम 3550, सिंघाडा छोटा 100-120, बड़ा 120-130, सिंदूर (25 कि.ग्रा. पैकिंग) 7300, देशी कपूर 850-860, बेस्ट 875-900, पूजा बादाम 115-125, बेस्ट 220-230, पूजा सुपारी 425-450, अरीठा 180-200, हरी इलायची एवरेज 2700-2800, मीडियम 2900-3050, बेस्ट 3150-3250, एक्ट्रा बेस्ट 3300-3500, पानबार 2450, बड़ी इलायची 1800-2100, तरबूज मगज 525-550, काजू (240) 880-925, काजू (210) 950-1000, काजू डब्ल्यू (340) 840-870, काजू एस.डब्ल्यू (300) 800-825, काजू जे.एच. 840-870, टुकड़ी 780-820, बादाम मगज 840-870, सिंगापुरी 850-860, बादाम टांच 700-725, अखरोट 590-850, अखरोट गिरी 1250-1550, जर्दालु 375-500, बेस्ट 550-650, किशमिश कंधारी 450-600, इंडियन 400-450, चारौली 1450-1750, मुनक्का 350-550, अंजीर 850-950, मखाना 850-1200, बेस्ट 1350-1400, खारक एवरेज 75-80, मीडियम 90-130, बेस्ट 140-260, पिस्ता पिशोरी 2900-3100, कंधारी 2500-2700, नमकीन पिस्ता 1000-1150, बेस्ट 1200-1250, गेहूँ आटा 1820, मैदा कट्टा 1850, रवा कट्टा 1880, बेसन 4675 (50 कि.ग्रा.), नारियल (120) 2700-2750, (160) 3100-3150, (200) 3400-3450, (250) 3800-3850,

तेल- सींगदाना 1750-1770, मुम्बई 1740, राजकोट तेलिया 2700, सोया साल्वेंट 1410-1415, सोया रिफाइंड 1475-1480, कपास्या 1590, धूलिया 1600, कड़ी 1600,

रात की धारणा- गुजरात लुज 1675, मुम्बई पाम 1500, मुम्बई सोया 1515,

खली- कपस्या खली (60 कि.ग्रा.) इन्दौर 2660, देवास-उज्जैन 2660, खंडवा 2630, बुरहानपुर 2575, अकोला 3950 (प्रति क्विंटल)

तिलहन- सरसो 8100-8500, रायडा 7000-7200, सोयाबीन 7100, टोली (महुआ बीज) 5300-5400, करंज 4400-4500, अलसी 8500-9000, अरंडी 4500-4700, तिल्ली पुरानी 6500-7000, तिल्ली नई 7200-7500,

दलहन- चना कांटेवाला बेस्ट 6450-6550, एवरेज 6200-6300, विशाल 6300-6350, महाराष्ट्र विशाल 5900-5950, काबूली चना डॉलर 7000-8300, काबूली चना रशियन 5600-5800, बिटकी 5200-5300, मसूर बेस्ट 6000-6050, एवरेज 5800-5900, मूंग गर्मी बेस्ट नया 7100-7250, मूंग पुराना बोल्ड 7600-7900, मीडियम 7400-7700, मोगर 5500-6500, तुअर निमाड़ी बेस्ट 7200-7400, एवरेज 6500-6600, हल्की 6400-6500, महाराष्ट्र सफेद 7400-7500, महाराष्ट्र लाल 7700-7900, उड़द बेस्ट 9500-9700, उड़द गर्मी 8800-9500, ग्रेविटी क्लीन 10100-10200, हल्की 5000-7000,

दाल- चना दाल एवरेज 7400-7500, मीडियम 7600-7700, बोल्ड 7900-8100, तुअर दाल सवा नं. 8200-8400, तुअर दाल 7300-7600, तुअर दाल मीडियम 8500-8800, बेस्ट 9900-10200, मसूर दाल 6800-7100, मूंग दाल 8700-8900, मूंग मोगर 10100-10600, उड़द दाल 9900-10300, मोगर 10800-11000,

अनाज- गेहूं मिल क्वालिटी 2500-2550, लोकवन एवरेज 2550-2650, बेस्ट 2750-2800, मालवराज 2600-2650, गेहूँ पूर्णा एवरेज 2400-2550, बेस्ट 2650-2750, मक्का पीली 1975-2000,

चावल- चावल हंसा सफेद 2900-3100, सेला 3500-3700, परमल 3400-3500, दुबराज 4500-5500, राजभोग 7500, काली मुंछ डिनर किंग 9000, बासमती दुबार 9500-10000, मीनी दुबार 8000-8500, मोगरा 5000-7000, तिबार 10500-11500, बासमती (921) 12000-13000, बासमती सेला 7500-9500, पोहा 4500-5100,

मावा- इन्दौर 340, उज्जैन 280, रतलाम 275 रू. प्रति किलो।

इंदौर सर्राफा बाज़ार

इन्दौर। एजेंसी। शुक्रवार को स्थानीय सराफा बाजार में व्यापार सामान्य ही रहा। दोनों ही मूल्यवान धातुओं में बाजार नरमी के रहे। भाव इस प्रकार रहे-

चाँदी (9999) 222000, चाँदी (99) 221900, टंच 221200, सिक्का 2600, सोना 10 ग्राम 141900,

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई। एजेंसी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को 25 पैसे की बढ़त के साथ ही 96.47 पर बंद हुआ। रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 22 पैसे मजबूत होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.51 पर पहुंच गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने के बाद रुपये में और गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संभावित हस्तक्षेप से घरेलू मुद्रा को थोड़ा समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर के कमजोर होने से रुपये को कुछ समर्थन मिला, जबकि विदेशी पूंजी की निकासी और घरेलू शेयर बाजारों में लगातार गिरावट से स्थानीय मुद्रा पर दबाव बना रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया कमजोर रुख के साथ 96.81 प्रति डॉलर पर खुला।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 331, निफ्टी 102 अंक गिरा

मुम्बई। एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को भी गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। कच्चे तेल की कीमतों में आये उछाल और अमेरिका के भारत से खरीदे जाने वाले सामान पर 10 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा से भी बाजार पर दबाव पड़ा है। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अंत में 331.62 अंक नीचे आकर 76,059.77 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 102.15 अंक गिरकर 23,767.45 अंक पर बंद हुआ। इस प्रकार देखा जाये तो पूरे सप्ताह ही बाजार में गिरावट रही। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा,

भारती एयरटेल, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील और सन फार्मा के शेयर भी नीचे आये। वहीं दूसरी ओर, एचसीएल टेक, आईटीसी, एक्सिस बैंक, ट्रेंट, मारुति, रिलायंस, टीसीएस और कोटक बैंक के शेयरों में बढ़त आई।

आज निफ्टी मेंबजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। वहीं ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप के शेयरों में भी गिरावट रही। सेक्टरवाइज देखें तो निफ्टी ऑटो में 1 फीसदी की गिरावट आई और यह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सेक्टर रहा। निफ्टी रियल्टी और निफ्टी फार्मा का प्रदर्शन भी कमजोर रहा जबकि निफ्टी मीडिया और निफ्टी आईटी ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार गिरावट के साथ खुला। । सुबह शुरुआत में निफ्टी 207 अंक टूटकर 23,662.70 पर आ गया, जबकि सेंसेक्स 718.41 अंक की बड़ी गिरावट के साथ ही 75,672.98 के स्तर पर पहुंच गया।

आरबीआई की रियायती विंडो से पहले बैंकों की डॉलर बॉन्ड जारी करने की तैयारी

नई दिल्ली। एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रदान की गई रियायती स्वैप विंडो के दिसंबर में समाप्त होने से पहले कई प्रमुख भारतीय बैंक डॉलर बॉन्ड जारी करने की तैयारी में हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कम हेजिंग लागत का लाभ उठाना है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) सहित कई बड़े ऋणदाता विदेशी बाजारों से पूंजी जुटाने की योजना बना रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी इस मामले पर विचार कर रहा है। आरबीआई की यह सुविधा पात्र विदेशी मुद्रा बॉन्ड (ओएफसीबी) और बाहरी कमर्शियल बॉरोइंग (ईसीबी) पर हेजिंग लागत का 1.5 प्रतिशत तक का हिस्सा कवर करती है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक ने पहले ही 3.3 अरब डॉलर की फंडिंग में मदद की है। फेडरल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) भी इस दौड़ में शामिल हैं। हालांकि, पहले एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे बड़े बैंकों द्वारा डॉलर बॉन्ड जारी करने से बाजार में एक सुस्ती देखी गई थी। निवेशकों को भारी आपूर्ति की आशंका थी, जिससे क्रेडिट स्प्रेड में वृद्धि हुई और फंडिंग की लागत कम आकर्षक हो गई। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और बॉन्ड स्प्रेड जैसे कारकों को रियायती सुविधा में शामिल न होने के कारण, रुपये में फंडिंग की प्रभावी लागत घरेलू उधार के समान ही थी। बाजार के जानकारों के अनुसार, जून तिमाही के नतीजों से पहले कई बैंकों का साइलेंट पीरियड में होना भी एक कारण था। अब अधिकांश निजी बैंक अपने नतीजे घोषित कर चुके हैं और विदेशी बॉन्ड बाजार में उतरने के लिए तैयार हैं। वे बॉन्ड जारी करने के समय और लागत पर सावधानीपूर्वक विचार कर रहे हैं, ताकि विदेशी पूंजी घरेलू उधार से अधिक लाभदायक हो।

अमेरिका ने 60 देशों पर लगाया मजदूरी शुल्क-भारत समेत 17 पर 10 फीसदी बोझ

नई दिल्ली। एजेंसी। अमेरिका ने जबरन मजदूरी से तैयार किए गए सामान के उत्पादन पर रोक लगाने के प्रयासों के तहत भारत सहित 60 देशों पर नए आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। शुक्रवार मध्यरात्रि से प्रभावी हुए इन शुल्कों के तहत, भारत समेत 17 देशों पर 10 फीसदी और शेष 43 देशों पर 12.5 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। भारत को अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन कर जबरन मजदूरी वाले सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने के कारण कम शुल्क वर्ग में रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत यह अंतिम कार्रवाई की है। 60 देशों में से 17 अर्थव्यवस्थाएं, जिनमें भारत, कनाडा, ब्रिटेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं, उन पर 10 फीसदी शुल्क लागू होगा। अमेरिकी प्रशासन ने स्वीकार किया है कि इन देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। विशेष रूप से, भारत ने अपनी नीति में बदलाव कर ऐसे सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया, जिससे उसे प्रस्तावित 12.5 फीसदी के बजाय 10 फीसदी शुल्क के दायरे में रखा गया। वहीं चीन और जापान जैसे 43 देश उन पर 12.5 फीसदी शुल्क का सामना करेंगे, क्योंकि वे जबरन मजदूरी से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहे हैं। हालांकि, कुछ उत्पादों को इन शुल्कों से छूट दी गई है, जिनमें वे कच्चे माल शामिल हैं जिनसे अमेरिका में घरेलू आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, या वे उत्पाद जो अर्थव्यवस्था में बाधा डाल सकते हैं, या जिन्हें अमेरिका में पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं किया जाता। इन कदमों का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित देशों को जबरन मजदूरी संबंधी प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

मेष- आज कुछ नया सोचने और उसे करने का जुनून रहेगा। काम का बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत आपको पीछे नहीं हटने देगी। नौकरी बदलने वालों के लिए किस्मत मुस्कुरा रही है और प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले भी आपके पक्ष में जा सकते हैं। किसी सहकर्मी की बात दिल को चुभ सकती है, लेकिन आप उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझेंगे।

वृषभ- आज का दिन आपके लिए राहत और खुशियों की सौगात लेकर आया है। खर्चों पर कंट्रोल रखेंगे तो मन भी हल्का रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को पहचान और सम्मान मिल सकता है। आपकी मेहनत और काम करने का तरीका बॉस को प्रभावित करेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। नए लोगों से मुलाकात आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है। जीवनसाथी के साथ चल रही खटास भी आज प्यार में बदलती नजर आएगी।

मिथुन- आज किस्मत आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सामाजिक कार्यों में आपकी पहचान बढ़ेगी और बड़े लोगों से मिलने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, आपके आसपास कुछ लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। घर के अधूरे कामों को नजरअंदाज करना आगे परेशानी खड़ी कर सकता है। परिवार में किसी सदस्य के बाहर जाने की खबर भावुक कर सकती है।

कर्क- आज आप ऊर्जा से भरपूर नजर आएंगे और आपकी समझदारी हर काम को आसान बना देगी। भगवान की भक्ति में मन लगेगा और दिल को सुकून मिलेगा। बिजनेस में आपकी सोच आपको आगे बढ़ाएगी और नया काम शुरू करने का साहस भी आएगा। विद्यार्थियों के लिए मेहनत ही सफलता की कुंजी बनेगी। संतान की ओर से मिलने वाली खुशखबरी आपका दिन बना देगी।

सिंह- आज आपका आत्मविश्वास आसमान छूता नजर आएगा, खासकर बिजनेस में आपकी योजनाएं आपको शानदार लाभ दिला सकती हैं। घर में किसी मेहमान के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन आपकी व्यस्तता भी बढ़ेगी। अपनी दिनचर्या को सुधारने की जरूरत महसूस होगी। काम को टालने की आदत आपको थोड़ा पीछे खींच सकती है, इसलिए सावधान रहें। घूमने-फिरने की योजना दिल को ताजगी दे सकती है।

कन्या- आज निवेश से जुड़े फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो आगे चलकर लाभ देगी। सेहत को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। भाई-बहनों के साथ समय बिताना खुशी देगा और किसी दूर के रिश्तेदार से मुलाकात दिल को सुकून देगी। माता-पिता की सेवा करने का अवसर मिलेगा और कोई रुकी हुई डील आखिरकार पूरी हो सकती है।

तुला- आज आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी और व्यापार में नई साझेदारी का रास्ता खुल सकता है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के नए दरवाजे खुलेंगे। नई मुलाकातें आपके जीवन में ताजगी लाएंगी। दूर से मिलने वाली कोई खुशखबरी दिल को खुश कर देगी। दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है और नौकरी में प्रमोशन की खबर भी आपको उत्साहित कर सकती है।

वृश्चिक- आज आपका दिन सफलता और संतोष से भरा रहेगा। उन्नति की राह पर आप तेजी से आगे बढ़ेंगे और धन-समृद्धि में वृद्धि होगी। आपने जो वादे किए हैं, उन्हें निभाने का समय आ गया है। आपका भला सोचने वाला दिल हर किसी के लिए अच्छा करेगा, भले ही लोग उसे समझ न पाएं। सेहत भी आपका साथ देगी और किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन को सच्ची खुशी मिलेगी।

धनु- आज काम के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा और बॉस के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। बिजनेस में आपकी मेहनत रंग लाएगी और जीवनसाथी को दी गई सलाह उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आपकी लगन आपको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर मिल सकती है। परिवार में रिश्तों की मिठास बढ़ेगी, हालांकि किसी की बात दिल को लग सकती है।

मकर- आज आपको हर कदम सोच-समझकर उठाने की जरूरत है, क्योंकि जल्दबाजी आपको परेशानी में डाल सकती है। बिजनेस में बदलाव करने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। मदद मांगने पर आपको सहयोग जरूर मिलेगा, लेकिन कोई काम बनते-बनते बिगड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें।

कुंभ- आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने भावनाओं पर काबू रखना होगा। किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन आलस्य आपको पीछे खींच सकता है। सिंगल लोगों के जीवन में प्यार की दस्तक हो सकती है। आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।

मीन- आज सेहत आपका पूरा साथ देगी और पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। हालांकि कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप संभाल लेंगे। कुछ नया करने की चाह आपके अंदर जोश भर देगी। संतान के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। लिया हुआ कर्ज वापस मांगने की स्थिति बन सकती है, इसलिए तैयार रहें।

शब्दजाल - 8330

शब्दजाल में दस 'वृक्षों' के नाम ढूंढिए. दिए गए नाम उपर से नीचे व तिरछे हो सकते हैं.

आ	हु	मे	रि	द	इ	शी	श	म	ट	र्जी
का	म	क	ची	ड	जी	ने	शि	दे	ड	अ
ब	पी	जा	ह	र	ग	बा	द	व	प	शो
ला	ग	ए	ई	जा	भ	ब	ल	दा	लि	क
सा	ग	वा	न	जी	ह	ला	कि	र	प	म
पी	इ	वि	मो	ग	ब	र	ग	द	गी	स
न	प	ल	र	व	मा	जो	न	व	प	त
क	रि	ल	र	य	र	प	नी	म	वि	रे
र	या	बा	व	ह	न	ज	जी	शा	जू	ड़ी
र	ग	ल	नो	ला	व	गु	ल	मो	ह	र
बां	स	सा	ए	न	स	मे	व	क	ल	

बरगद,पीपल,नीम,अशोक,गुलमोहर, आम,शीशम,देवदार,चीड़,सागवान

शब्दजाल - 8329 का हल

[illegible]										
क	व	चि	ना	ब	प	दा	ज	ती	व	मु
श	एं	वा	ई	द	ब	व	डू	ए	श	ना
मी	ड	ल	फू	ल	औ	री	आ	ग	शी	आ
र	गॉ	ल	प	लि	जी	शी	व्या	स	री	द
वि	ज	अ	ब्र	म्ह	पु	त्र	त	ब	प	म

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

25 जुलाई 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ समय	
सूर्य	कर्क में	सिंह	07.11 बजे से
चंद्र	वृश्चिक में	कन्या	09.23 बजे से
मंगल	वृष में	तुला	11.34 बजे से
बुध	मिथुन में	वृश्चिक	13.49 ब.से
गुरु	कर्क में	धनु	16.05 बजे से
शुक्र	सिंह में	मकर	18.10 बजे से
शनि	मीन में	कुंभ	19.56 बजे से
राहु	कुंभ में	मीन	21.29 बजे से
केतु	सिंह में	मेष	23.00 बजे से
		वृष	00.40 बजे से
राहुकाल 9.00 से 10.30 बजे तक		मिथुन	02.38 बजे से
		कर्क	04.51 बजे से

शनिवार 2026 वर्ष का 206 वा दिन
दिशाशूल पूर्व **ऋतु** वर्षा।
विक्रम संवत् 2083 **शक संवत्** 1948
मास आषाढ़ **पक्ष** शुक्ल
तिथि एकादशी 11.35 बजे को समाप्त।
नक्षत्र ज्येष्ठा अहोरात्र।
योग ब्रह्म 21.09 बजे को समाप्त।
करण विष्टि 11.35 बजे तदनन्तर बव 00.47 बजे रात्र को समाप्त।
चन्द्रायु 10.6 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 19° 41'
सूर्य दक्षिणायन
कलि अहर्गण 1872781
जूलियन दिन 2461246.5
कलियुग संवत् 5128
कल्पारंभ संवत् 1972949128
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885128
वीरनिर्वाण संवत् 2552
हिजरी सन् 1448
महीना सफर
तारीख 10
विशेष गौरी व्रत, देवशयनी एकादशी।

दिन का चौघड़िया		रात का चौघड़िया	
काल	05.55 से 07.23 बजे तक	लाभ	05.37 से 07.10 बजे तक
शुभ	07.23 से 08.51 बजे तक	उद्वेग	07.10 से 08.42 बजे तक
रोग	08.51 से 10.19 बजे तक	शुभ	08.42 से 10.14 बजे तक
उद्वेग	10.19 से 11.46 बजे तक	अमृत	10.14 से 11.47 बजे तक
चर	11.46 से 01.14 बजे तक	चर	11.47 से 01.19 बजे तक
लाभ	01.14 से 02.42 बजे तक	रोग	01.19 से 02.51 बजे तक
अमृत	02.42 से 04.10 बजे तक	काल	02.51 से 04.23 बजे तक
काल	04.10 से 05.37 बजे तक	लाभ	04.23 से 05.56 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली- 7274

बायें से दायें:-

१. फरदीन, करीना की अमिताभ बच्चन की शीर्षक भूमिका वाली फिल्म-२
२. 'चल दरिया में डूब' गीत वाली राजेश खन्ना, हेमा, मुमताज की फिल्म-२,३
६. करणनाथ, मनीषा, नतान्या की 'दिल तो उड़ने लगा' गीत वाली फिल्म-२
७. 'बाहर है प्रॉबलम' गीत वाली अमृता सिंह, अमिताभ, मीनाक्षी की फिल्म-३
८. अनिलकपूर, अक्षय, ऐश्वर्या की 'इस टूटे दिल की पीर' गीत वाली फिल्म-२
१०. 'सुनता है मेरा खुदा' गीत वाली अनिलकपूर, माधुरी की फिल्म-३
११. जीतेंद्र, श्रीदेवी की 'गोरी तेरे अंग अंग में' गीत वाली फिल्म-३
१४. 'बोल बेबी बोल' गीत वाली अनिलकपूर, मीनाक्षी की फिल्म-२,२
१६. बॉबी देओल, मनीषा, काजोल की 'दुनिया हसीनों का मेला' गीत वाली फिल्म-२
१७. 'कोई माने या ना माने' गीत वाली फिरोजखान, रेखा की फिल्म-३
१९. देवआनंद, वहीदा की 'है अपना दिल तो आवारा' गीत वाली फिल्म-३,२
२३. 'गिर गया झुमका' गीत वाली धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी की फिल्म-३
२४. फिल्म 'तीसरी कसम' में राजकपूर के साथ नायिका कौन थी?-३
२५. प्राण, नवीन निश्चल, रेखा की 'ना सतरा से ऊपर' गीत वाली फिल्म-२
२६. 'तुझे प्यार करते करते' गीत वाली अजय देवगन, जूही की फिल्म-४
२७. अजय देवगन, रानी मुखर्जी की 'ना ना मेहंदी ना मुझको लगाना' गीत वाली फिल्म-२,२

ऊपर से नीचे:-

१. संजीवकुमार, शबाना आजमी की फिल्म-३
२. देवआनंद, वहीदा रहमान की 'रंगीला रे तेरे रंग में' गीत वाली फिल्म-२,३
३. 'कितना बेचैन होके' गीत वाली आफ ताब, लिसा रे की फिल्म-३
४. फिल्म 'रफूचक्कर' में ऋषिकपूर के साथ नायिका कौन थी?-२,२
५. फिल्म 'छैला बाबू' में राजेश खन्ना के साथ नायिका कौन थी?-३
९. अमिताभ, रितिक, प्रीती जिंटा की 'अगर मैं कहूँ' गीत वाली फिल्म-२
१२. 'तुम रूठ के मत जाना' गीत वाली भारतभूषण, मधुबाला की फिल्म-३
१३. किशोर कुमार, चॉद उस्मानी की 'छोटा सा घर होगा' गीत वाली फिल्म-३
१४. 'दिल मेरा अकेला' गीत वाली आमिर, फैजल, टिवंकल की फिल्म-२
१५. फरदीनखान, उर्मिला की 'दो प्यार करने वाले' गीत वाली फिल्म-३
१८. 'तेरे प्यार का छाया नशा' गीत वाली आफताब, युक्ता मुखी की फिल्म-२
१९. फिल्म 'काश आप हमारे होते' का नायक कौन है?-२
२०. मिथुन चक्रवर्ती, टीना मुनीम की 'तुम सा नहीं देखा' गीत वाली फिल्म-३
२१. 'ये लड़की जरा सी' गीत वाली कुमार गौरव, विजेयता पंडित की फिल्म-२,२
२२. मिथुन चक्रवर्ती, ऋतुपर्णा की 'गोरे रंग का जमाना' गीत वाली फिल्म-४
२३. 'मिर्ची ये मिर्ची' गीत वाली फिल्म-३

फिल्म वर्ग पहेली- 7273

आ	ई	मि	ल	न	की	बे	ला	■	शा
गा	■	ल	■	गिं	■	ना	■	मि	ली
ज	मी	न	■	स	न	म	■	■	मा
[illegible]									

Jagrutidaur.com, Bangalore

प्रसंगतः गायिका की दरियादिली

एक बार फ्रांसीसी गायिका मेलिथान के पास एक गरीब-फटेहाल लड़का आया। बालक गायिका के पास आकर खड़ा हो गया। उसे पास देखकर मेलिथान बोली, 'बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरे पास क्यों आए हो?' बालक बोला, 'मैडम, मेरा नाम पियरे है। मैं आपके पास बहुत आशा से आया हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगी?' मेलिथान बोली, 'हां बेटे, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश अवश्य करूंगी। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है?' इस पर बालक बोला, 'मेरी मां बहुत बीमार है मगर मेरे पास उनका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं।' यह सुनकर मेलिथान बोली, 'अच्छा तो तुम्हें मुझसे आर्थिक मदद चाहिए। बोलो मैं तुम्हारी मदद के लिए कितने पैसे दूं?' मेलिथान अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि बालक बीच में ही बोला, 'क्षमा कीजिएगा मैडम, मैं आपसे मुफ्त में मदद नहीं लेना चाहता। मैं तो आपसे अलग तरह की सहायता चाहता हूं।' नन्हे से बालक की यह बात सुनकर मेलिथान हैरान हो गई और बोली, 'कैसी सहायता चाहते हो?' पियरे बोला, 'मैडम मैं आपसे यह निवेदन करने आया था कि मैंने एक कविता लिखी है। आप मुझे उसे अपने साथ संगीत सभा में गाने का अवसर प्रदान करें और आप जो उचित समझें वह पारिश्रमिक मुझे दे दें।' नन्हे से बालक की इस बात से मेलिथान बेहद प्रभावित हुई और उसने पियरे को अपने ही कार्यक्रम में अकेले गाने का अवसर दिया। बालक पियरे की करुण स्वर में गाई गई कविता वहां उपस्थित जनसमूह को छू गई। सभी दर्शकों की आंखें भीग गईं। वह कार्यक्रम बेहद सफल हुआ और उस कार्यक्रम में गायिका पर पैसे की बरसात हो गई। लेकिन मेलिथान ने दरियादिली दिखाते हुए वे सारे पैसे पियरे की मां को सौंप दिए और बोली, 'आपका बेटा बेहद काबिल है और वही इन पैसों का असली हकदार है। अब न सिर्फ आपकी बीमारी भाग जाएगी बल्कि आपका जीवन भी संवर जाएगा।' पियरे की मां ने मेलिथान के प्रति आभार प्रकट किया।

सूडोकु नवताल- 7583

★★★★★ कठिनतम

			2					4
			6					1
	5		8			2		3
		7					6	
	3					8		
1		6			3		7	
2					5			
8					4			

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भर जाने आवश्यक हैं.
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
■ पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7582 का हल

6	5	4	3	1	9	7	2	8
7	2	3	5	8	4	9	6	1
8	9	1	7	2	6	3	4	5
1	7	2	8	3	2	5	9	4
4	3	8	9	6	5	1	7	6
5	6	9	4	7	1	8	3	2
2	8	7	1	4	3	6	5	9
9	1	6	2	5	7	4	8	3
3	4	5	6	9	8	2	1	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द पहेली - 8798

बाएँ से दाएँ

1. कंठ,गला-3
3. पक्षियों का शौर-4
5. शारीरिक ऊँचाई-2
6. पाचन शक्ति-3
7. मां की माता-2
8. प्यार,प्रेम(अंग्रेजी-2)
10. रचना करने वाला-5
12. शोरबा,तरी-3
15. खाद्य सामग्री-3
17. दोनों हाथों को पीटना-5
20. भाग्य(अंग्रेजी-2)
22. कदली,एक फल-2
23. उपासना,शीश झुकाना-3
24. घ्राणेन्द्रिय,नासिका-2
25. तहखाना-4
26. दया-3

ऊपर से नीचे

1. मर्यादा,सीमा-2
2. कहानी लिखने वाला-5
3. अचरज भरा कार्य-3
4. वर,इच्छित वस्तु देना-4
5. जलजला-3
7. मां के पिता-2
9. चिकनाई-2
11. हशीश,एक प्रकार का मादक पदार्थ-3
13. बोलने का तरीका-3
14. तमीजवाला-5
15. परंपरा,रिवाज-4
16. राजनीतिक पार्टी-2
18. आफत,मुसीबत-2
19. नाट्य,कथा मंचन-3
21. कमी-3
24. संबोधन-2

शब्द पहेली - 8797 का हल

■	अ	च	र	ज	■	सु	रु	चि
चा	चा	■	म	ही	ना	■	■	न्त
र	न	र	■	न	व	जी	व	न
■	क	म	ला	■	च	■	■	शी
म	■	ल	त	■	ला	त	■	ल
नो	■	■	मा	■	ना	र	द	■
का	न	भ	र	ना	■	ह	र	म
म	■	■	ना	का	रा	■	क	ण
ना	ट	क	■	म	ह	क	ना	■

Jagrutidaur.com, Bangalore

लगभग 22 करोड़ रुपये लागत की नई जल आवर्धन योजना पूर्ण होने से पूर्व ही तोड़ने लगी दम

स्वीपर कॉलोनी में बनी पानी की टंकी चालू होने से पहले ही रहवासियों के लिए बनी भय का कारण

पद्मेश न्यूज। लांजी। जिस कॉलोनी के लोगों के कंधों पर पूरे नगर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी है, आज वही लोग अपनी जान बचाने की गुहार लगाने को मजबूर हैं। लांजी नगर परिषद में लगभग 22 करोड़ रुपये की लागत से नई जल आवर्धन योजना स्वीकृत होकर वर्ष 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसके अंतर्गत कुल्पा से लांजी तक पाइप लाइन, फिल्टर प्लांट, तीन पानी की टंकियों का निर्माण एवं नगर में घरों में पानी सप्लाई के लिए पाइप लाइन का कार्य किया जाना था। 8 साल बीत जाने के बाद भी यह जल आवर्धन योजना अब तक पूर्ण नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर योजना अंतर्गत वार्ड क्रमांक.4 स्वीपर कॉलोनी में स्थित पानी की ऊंची टंकी अब रहवासियों के लिए भय का कारण बन गई है। विडंबना यह है कि 8 वर्षों बाद भी यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई है, और ना ही किसी वार्ड में पानी सप्लाई प्रारंभ हो पाई है। लेकिन टेस्टिंग के दौरान ही टंकी से पानी का रिसाव शुरू हो गया है। इससे निर्माण की गुणवत्ता और पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्ष 2018 में शुरू हुआ यह निर्माण कार्य कोरोना काल के कारण कुछ समय प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज तक पूरा नहीं हो सका। अब जब टंकी की टेस्टिंग की जा रही है तो उसमें भरा गया पानी भी जगह.जगह से रिस रहा है। ऐसे में रहवासियों का सवाल है कि यदि परीक्षण में ही यह स्थिति है तो भविष्य में हजारों लीटर पानी का दबाव पडने् पर टंकी कितनी सुरक्षित रहेगी। रहवासियों ने बताया कि जिस कॉलोनी में यह टंकी खड़ी की गई है, वहां नगर परिषद के सफाईकर्मी और उनके परिवार रहते हैं। पूरे नगर की सफाई करने वाले इन परिवारों को स्वयं मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं हैं। कॉलोनी में साफ.सफाई, नालियों और अन्य व्यवस्थाओं का अभाव है। लोगों का कहना है कि हम पूरे नगर की गंदगी साफ करते हैं,

लेकिन नगर परिषद हमारे घर.आंगन की सुध लेने तक तैयार नहीं है। अब रिसती हुई टंकी ने उनकी चिंता कई गुना बढ़ा दी है।

८ साल में बना मौत का कुआं, उपयंत्री की भूमिका संदिग्ध

वर्ष 2018 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट कोरोना और प्रशासनिक लापरवाही के कारण 8 साल बाद भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो सका। करोड़ों की योजना को अपनी देखरेख में पास कराने वाले नगर परिषद के उपयंत्री अमित नगपुरे की निष्ठा और तकनीकी दक्षता पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि उपयंत्री अमित नगपुरे द्वारा कार्यस्थल का सतत निरीक्षण और मॉनिटरिंग न किए जाने के कारण ठेकेदार को मनमानी और घटिया निर्माण की खुली छूट मिली। नगर परिषद की बैठकों में लगातार निगरानी के मुद्दे उठाए जाने के बावजूद उपयंत्री और सीएमओ की आंखें बंद रहीं। नतीजतन, जनता के 22 करोड़ रुपये पानी में बह गए और बदले में सफाई कर्मचारियों को मिला तो केवल हादसे का खौफ ।

पूरे शहर को हम चमकाते हैं, पर हमारे सिर पर खड़ी कर दी मौत की टंकी

स्वीपर कॉलोनी के रहवासियों का आक्रोश चरम पर है। कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का पहले से ही भारी अभाव है। सड़कें कीचड़ और मलबे से पटी हैं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि हम पूरे शहर की गंदगी साफ करके नगर को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन हमारे खुद के घर.आंगन को साफ कराने में नगर परिषद का दम फूलता है। ऊपर से हमारे सिर पर यह कमजोर पानी टंकी खड़ी कर दी गई है जो कभी भी गिर सकती है। विरोध और शिकायत के दौरान मुख्य रूप से रवि रगड़े, संतोषी पांडे, रत्ना रगड़े, शकुनबाई रगड़े, राजेश पांडे, दीपक खांडेकर, ललिता मोगरे, दीपम मोगरे, सोनू खांडेकर, विक्की नागवंशी, राखी खांडेकर, किशन पांडे, प्रवीण पांडे सहित दर्जनों रहवासी उपस्थित रहे।

घरों तक पानी पहुंचने से पहले ही टंकी रिसने लगी-सौरभ मोनू पशीने

वार्ड क्रमांक-11 के पार्षद सौरभ मोनू पशीने ने कहा कि कुछ दिन पहले वार्डवासियों ने उन्हें टंकी से रिसाव और संभावित खतरे की जानकारी दी थी। मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने पर शिकायत पूरी तरह सही मिली।

उन्होंने कहा कि नई जल आवर्धन योजना के तहत बने निर्माण में इस प्रकार की स्थिति होना बेहद गंभीर है। यदि निर्माण कार्य के दौरान इंजीनियर द्वारा प्रभावी निगरानी की जाती तो आज यह नौबत नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति के कारण निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की कि या तो इस टंकी को पूरी तरह डिस्मेंटल कर सुरक्षित स्थान पर नई टंकी बनाई जाए अथवा इसे गुणवत्तापूर्ण तरीके से पुनर्निर्मित किया जाएए ताकि लोगों की जान जोखिम में न रहे।

एनजीटी के नियमों के खिलाफ हुआ निर्माण-संजय खोबरागड़े

पूर्व पार्षद संजय खोब्रागढ़े ने आरोप लगाया कि टंकी का निर्माण ही एनजीटी के नियमों के विपरीत किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरी तरह गुणवत्ताहीन प्रतीत होता है और टेस्टिंग के दौरान ही रिसाव शुरू हो जाना इसकी सबसे बड़ी पुष्टि है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में कोई दुर्घटना होती है और टंकी गिरती है तो बड़ी जनहानि हो सकती हैए जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद और संबंधित अधिकारियों की होगी। उन्होंने मांग की कि या तो टंकी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए अथवा पूरी तकनीकी जांच के बाद आवश्यक सुधार किए जाएं।

इंजीनियर की लापरवाही ने खड़ा किया खतरा-संदीप रामटेक्कर

नगर परिषद उपाध्यक्ष संदीप रामटेक्कर ने इस पूरे मामले में नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री अमित नगपुरे की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य के दौरान सतत निरीक्षण और मॉनिटरिंग नहीं होने का ही परिणाम है कि करोड़ों रुपये की परियोजना टेस्टिंग के दौरान ही सवालों के घेरे में आ गई। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों से निर्माण कार्य पूरा नहीं होना अपने आप में गंभीर प्रशासनिक विफलता है। नगर परिषद की बैठकों में लगातार निर्माण कार्यों की निगरानी का मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन न तो सीएमओ और न ही इंजीनियर स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जाता है। उन्होंने शासन.प्रशासन से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा के तहत एक गुरु-एक वृक्ष कार्यक्रम का किया आयोजन

पद्मेश न्यूज। लांजी। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बोलेगाँव में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा के अंतर्गत शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को 卐एक गुरु卐एक वृक्ष卐 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य बी.आर. गुरदे एवं समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं ने फलदार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संकल्प लिया। इसी दिन विद्यालय में संचालित नवाचार आधारित शैक्षणिक गतिविधियों के अवलोकन हेतु शासकीय माध्यमिक शाला डोरली के 58 छात्र-छात्राओं एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं का शैक्षणिक भ्रमण भी आयोजित किया गया। विद्यालय परिवार ने अतिथियों का तिलक लगाकर, बिस्किट पैकेट एवं पेन भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। डोरली विद्यालय के प्रभारी प्रधान पाठक सुरेश बेदरे, शिक्षिका भूमेश्वरी डिब्बे, गीतांजलि रामटेक्कर एवं माधुरी भटेरे ने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय की कक्ष सज्जा, शैक्षणिक चार्ट, नवाचार गतिविधियों और संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय की साज-सज्जा, अनुशासित वातावरण एवं रचनात्मक शिक्षण प्रणाली की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि यहां आकर एक प्रेरणादायक और ऊर्जावान विद्यालयी माहौल का अनुभव हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहां से मिली सीख को अपने विद्यालय में भी लागू करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था प्राचार्य बी.आर. गुरदे ने कहा कि भयमुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ एवं आकर्षक विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। इससे विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ती है और उसका सकारात्मक प्रभाव परीक्षा परिणामों में भी दिखाई देता है। उन्होंने सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से अपने-अपने विद्यालय को स्वच्छ, सुंदर और प्रेरणादायी बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लिया तथा गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा के इस प्रेरणादायी आयोजन का समापन किया।

ग्रामीणों की एकजुटता व सरपंच की पहल ने प्रशासन के सहयोग से लगभग 90 एकड़ शासकीय चरनोई भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

पद्मेश न्यूज। लांजी। कभी कुछ लोगों के अवैध कब्जे में सिमट चुकी देवलगांव की शासकीय चरनोई भूमि और शमशान घाट की लगभग 3 एकड़ भूमि अब फिर से गांव की सांस बनने लगी है। हजारों मवेशियों के सामने खड़े चराई संकट ने आखिरकार पूरे गांव को एक मंच पर ला खड़ा किया। ग्रामीणों की एकजुटता, सरपंच की पहल और प्रशासन के सहयोग से देवलगांव में लगभग 90 एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। गांव में यह अभियान अभी थमा नहीं है, बल्कि 25 जुलाई को सुबह 10 बजे एक बार फि र पूरा गांव सीमांकन और झंडी लगाने के लिए जुटेगा, ताकि गोचर भूमि हमेशा के लिए सुरक्षित की जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ जमीन खाली कराने की कार्रवाई नहीं, बल्कि आने वाली पीढि ?ों और गांव के करीब दो से तीन हजार मवेशियों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कब्जा करने वालों ने शासकीय भूमि पर लगे पलाश सहित कई हरे.भरे पेड़ों की भी कटाई कर दी थी। ग्रामीणों ने ऐसे मामलों की जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

चराई पर संकट बना तो गांव ने ठान लिया-अब नहीं होगा कब्जा

देवलगांव की शासकीय चरनोई भूमि पर वर्षों से धीरे-धीरे अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे थे। इसका सबसे बड़ा नुकसान गांव के मवेशियों को उठाना पड़ रहा था। बारिश के मौसम में चरवाहों ने मवेशियों को चराना तक बंद कर दिया। हालात ऐसे बने कि ग्रामीणों ने सरपंच श्रीमती पुष्पा कमलकिशोर ठाकरे को लिखित आवेदन देकर स्पष्ट कर दिया कि जब तक शासकीय भूमि मुक्त नहीं होगीए तब तक गांव चैन से नहीं बैठेगा। ग्रामीणों के आवेदन और लगातार दबाव के बाद राजस्व विभाग सक्रिय हुआ। नायब तहसीलदार लांजी ने अलग-अलग हल्कों के पटवारियों का संयुक्त दल गठित किया। राजस्व निरीक्षक, पटवारी दल तथा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में खसरा-नक्शे के आधार पर सीमांकन किया गया और चिन्हित शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। कार्यवाही के दौरान नायब तहसीलदार रमेश मरावी, मिथलेश शेण्डे पटवारी देवलगांव, कोमेन्द्र भोयर पटवारी मिरिया,गौतम उके पटवारी फोफसा, तोमेश सोनवाने पटवारी कारंजा, ऋषि कपुर डोंगरे पटवारी खर्रेगांव मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने भी प्रशासन का पूरा सहयोग किया, जिसके कारण कार्रवाई शांतिपूर्ण और प्रभावी ढंग से संपन्न हुई।

25 जुलाई को फिर जुटेगा पूरा गांव

ग्राम पंचायत द्वारा आम सूचना जारी कर सभी ग्रामवासियों से अपील की गई है कि 25 जुलाई को सुबह 10 बजे चिन्हित भूमि पर पहुंचकर सीमांकन, झंडी लगाने और गोचर भूमि सुरक्षित करने के अभियान में भाग लें। ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ भी पहुंचेंगेए ताकि जिस उद्देश्य से यह भूमि मुक्त कराई जा रही हैए वह सभी के सामने स्पष्ट हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव की पूरी शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जातीए तब तक यह अभियान लगातार चलता रहेगा। इस मामले में देवलगांव के ग्रामीणों ने यह साबित कर दिया कि जब पूरा गांव सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए एकजुट हो जाए तो वर्षों पुराने अवैध कब्जे भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते।

पेपर लीक व रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और किल्लत को लेकर कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन

पद्मेश न्यूज। लांजी। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक प्रकरण, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तथा किसानों को रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और किल्लत से राहत दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस शनिवार, 25 जुलाई को लांजी में विरोध प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम का नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव एवं मध्यप्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे करेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार शाम 4 बजे स्थानीय सुभाष चौक, लांजी में कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान एवं युवा एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कराने, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा किसानों को पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मामलों और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में किसान उर्वरकों की कमी और बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, जिससे खेती-किसानी प्रभावित हो रही है। कांग्रेस ने क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं, किसानों, युवाओं एवं आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर जनहित के इस आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

विठ्ठल - रुखमाई मंदिर में आषाढ़ी एकादशी पर आज होंगे धार्मिक कार्यक्रम

पद्मेश न्यूज। लांजी। नगर के सुन्दरटोला में स्थित भगवान विठ्ठल - रुखमाई मंदिर में आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़े ही भक्ति भाव से अभिषेक पूजन भजन के साथ उत्साह पूर्वक मनाकर प्रसादी का वितरण किया जाएगा। ज्ञात हो कि त्रिलोकराव रामटेक्कर जो कि वर्तमान में मुम्बई में रहते हैं के द्वारा अपने पैतृक निवास में वर्ष 2012 में भव्य मंदिर का निर्माण कर पढंरपुर से भगवान विठ्ठल - रुखमाई की प्रतिमाओं को लाकर स्थापित किया गया है। यह नगर व क्षेत्र का एक मात्र भगवान विठ्ठल - रुखमाई का मंदिर देवस्थान है, जो कि हमेशा सभी भक्तों के लिए खुला है। यहां प्रतिवर्ष उनके द्वारा देवशयनी एकादशी (आषाढ़ी एकादशी) पर्व पर लांजी पहुंचकर विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इसी के तहत आज 25 जुलाई को सुबह भगवान विठ्ठल - रुखमाई का विधि-विधान से अभिषेक कर पूजन अर्चन किया जाएगा। दोपहर में भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी एवं संध्या में प्रसादी का वितरण किया जाएगा। त्रिलोकराव रामटेक्कर एवं परिवार ने सभी धर्मप्रेमी भक्तजनों से उपस्थित होकर प्रसादी ग्रहण करने की अपील की है।

आज देवशयनी एकादशी से मांगलिक कार्यों में लगेगा विराम

पद्मेश न्यूज। लांजी। आषाढ़ मास के एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है , हिन्दू धर्म में मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी (आषाढ़ शुक्ल 11) से देवोत्थान एकादशी (कार्तिक शुल्क 11 तक) देवता सोते हैं । इसी आधार पर तमाम कर्मकाण्डी पंडितों द्वारा इस बीच विवाह, यज्ञोपवित आदि पारिवारिक संस्कार करने कराने को निषेध बताया गया है। इसी आधार पर आज से देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक मांगलिक कार्यक्रमों पर विराम लग जाएगा, जिसके चलते मांगलिक एवं वैवाहिक कार्यक्रम सहित शुभ कार्यों में विराम लग जाएगा। वहीं दूसरी ओर चतुर्मास प्रारंभ होते ही धार्मिक अनुष्ठान एवं पूजन कार्यक्रम, सावन लगते ही अखंड रामायण पाठ एवं अभिषेक पूजा अर्चना जैसे धार्मिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। इसी के साथ चतुर्मास प्रारंभ होते ही गुरु शिष्य परंपरा अनुसार बहुत से लोग अनुष्ठान, जप, ध्यान, नियमों का पालन करते हुये घरों में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना की जाएगी।

लांजी में ''पद्मेश''
इंटरनेट (ब्राडबेंड)
कनेक्शन के लिये संपर्क करें
Mo. 8319969927

अब पूरी तरह दतिया उपचुनाव पर सियासी फोकस

भाजपा और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत; मुख्यमंत्री मोहन यादव, उमंग सिंघार, हेमंत खंडेलवाल और जीतू पटवारी संभालेंगे मोर्चा

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होते ही प्रदेश की राजनीति का केंद्र अब दतिया विधानसभा उपचुनाव बन गया है। तीन दिन तक सदन में सरकार और विपक्ष के बीच विधेयकों, अनुपूरक बजट और विभिन्न मुद्दों पर चली बहस के बाद अब दोनों प्रमुख दल चुनावी मोड में आ गए हैं। भाजपा और कांग्रेस ने उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल मानते हुए अपने शीर्ष नेतृत्व को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है।

भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन और सरकार के वरिष्ठ मंत्री चुनावी रणनीति संभालेंगे, जबकि कांग्रेस की कमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ नेताओं के हाथ में रहेगी।

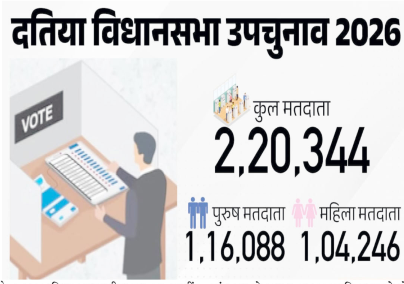

भाजपा के लिए साख बचाने की चुनौती

दतिया उपचुनाव भाजपा के लिए केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि इसे सरकार के कामकाज और संगठन की ताकत की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं चुनावी सभाओं और रणनीतिक बैठकों की कमान संभालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने में जुटे हैं। पार्टी का फोकस सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और संगठन की मजबूती को मतदाताओं तक पहुंचाने पर रहेगा।

कांग्रेस को वापसी का मौका

कांग्रेस इस उपचुनाव को सरकार के खिलाफ जनमत बनाने का अवसर मान रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार संयुक्त रूप से चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे। पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, ओबीसी आरक्षण, जल जीवन मिशन, कानून-व्यवस्था और स्थानीय मुद्दों को प्रमुख चुनावी एजेंडा बनाने की तैयारी में है।

स्थानीय समीकरण होंगे निर्णायक

दतिया उपचुनाव में जातीय और स्थानीय सामाजिक समीकरण भी अहम भूमिका निभाएंगे। राजनीतिक दलों की नजर विशेष रूप से प्रभावशाली सामाजिक समूहों, ग्रामीण मतदाताओं और शहरी वोट बैंक पर रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि उम्मीदवार चयन, स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता और बूथ प्रबंधन चुनाव परिणाम पर निर्णायक असर डाल सकते हैं।

संगठन बनाम मुद्दों की लड़ाई

भाजपा जहां अपने मजबूत संगठन, सरकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व को चुनाव का आधार बनाएगी, वहीं कांग्रेस सरकार को जनहित के मुद्दों पर घेरने की रणनीति अपनाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की लगातार सभाएं, रोड शो और जनसंपर्क अभियान देखने को मिल सकते हैं।

मानसून सत्र से चुनावी मैदान तक

विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच जिस तरह यूसीसी, अनुपूरक बजट, आरक्षण, किसानों और रोजगार जैसे मुद्दों पर तीखी बहस हुई, अब वही मुद्दे चुनावी मंचों पर भी सुनाई देंगे। दोनों दल अपने-अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। दतिया उपचुनाव भले ही एक सीट का चुनाव हो, लेकिन इसके राजनीतिक नतीजों को पूरे प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में देखा जाएगा। यही वजह है कि विधानसभा सत्र समाप्त होते ही अब प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र दतिया बन गया है।

मप्र में सस्ती होगी मेडिकल शिक्षा

- नीट मेरिट सूची में आने वाले छात्रों के लिए बड़ी सौगात

भोपाल । डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। नीट मेरिट में स्थान पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए मध्यप्रदेश में मेडिकल शिक्षा सस्ती होने जा रही है। मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स की फीस में एक-तिहाई की कमी होने के आसार हैं। दूसरी ओर, सीट बढ़ोतरी के कारण नीट परीक्षा में मेरिट स्टूडेंट्स को अधिक संख्या में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। इससे मेरिट में आए नीट एस्पिरेंट को प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी हुई सीट संख्या और कम फीस का दोहरा लाभ मिल सकेगा। वहीं मैनेजमेंट कोटे के तहत स्टूडेंट्स का एडमिशन नीट मेरिट के आधार पर राज्य सरकार की ओर से की जाने वाली काउंसलिंग के माध्यम से होगा। सरकार

मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2026 में मेडिकल कॉलेजों में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों के लिए सीटें बढ़ाई गई हैं। जहां वर्ष 2023 में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कुल उपलब्ध सीटें 4675 थीं, इनमें से सरकारी कॉलेजों में 2275 सीटें और निजी कॉलेजों में 2400 सीटें उपलब्ध थीं। इनमें से मेरिट विद्यार्थियों के लिए कुल 4315 सीटें निश्चित की गई थीं, जिसमें सरकारी कॉलेजों में 2215 और निजी कॉलेजों में 2040 सीटें रखी गई थीं। वर्ष 2026 में इनमें बढ़ोतरी करने पर मेडिकल कॉलेजों में कुल उपलब्ध सीटें 6020 हुईं, जिसमें सरकारी कॉलेजों में 3020 और निजी कॉलेजों में 3000 सीटें उपलब्ध रखी गईं। इस प्रकार वर्ष 2026 में मेरिट विद्यार्थियों के लिए कुल 4520 सीटें उपलब्ध रखी गईं, जिनमें सरकारी कॉलेजों में 3020 और निजी कॉलेजों में 1500 सीटें मेरिट विद्यार्थियों के लिए तय की गई।

साढ़े आठ लाख सीटें, लेकिन प्रवेश केवल साढ़े पांच लाख

भोपाल । मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने इस वर्ष प्रवेश का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद स्नातक और स्नातकोत्तर की लगभग 2.85 लाख सीटें अब भी खाली हैं। स्थिति यह है कि कई सरकारी और निजी कॉलेज विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों से सीधे संपर्क कर प्रवेश लेने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित संख्या में छात्र नहीं पहुंच रहे। 31 जुलाई को प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित है, जबकि दूसरे एवं अंतिम चरण की प्रक्रिया समाप्त होने में केवल कुछ दिन शेष हैं। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन को उम्मीद कम और चिंता अधिक दिखाई दे रही है। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 550 सरकारी और लगभग 800 निजी कॉलेजों में इस वर्ष करीब 8.5 लाख सीटें उपलब्ध हैं। 22 जुलाई तक इनमें से करीब 5.5 लाख सीटों पर ही प्रवेश हो पाया है। इनमें भी स्नातक प्रथम वर्ष में लगभग चार लाख विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है, जबकि शेष सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। कॉलेज लेवल काउंसिलिंग (सीएलसी) के दूसरे चरण के बाद भी विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय की खाली लगभग 3.5 लाख सीटों में से केवल 60 से 65 हजार सीटें ही भर सकी हैं।

बड़े शहरों में प्रवेश लगभग थमा

पिछले दो-तीन दिनों से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों के अनेक कॉलेजों में नए प्रवेश लगभग रुक गए हैं। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि अंतिम तिथि नजदीक आने के बावजूद नए विद्यार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। इसी कारण कई संस्थान फोन कॉल, व्यक्तिगत संपर्क और अन्य माध्यमों से विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

अगस्त-सितंबर तक बढ़ सकती है प्रवेश तिथि

हालांकि वर्तमान में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, लेकिन कॉलेज प्रबंधकों को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने के कारण उच्च शिक्षा विभाग अगस्त या सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया बढ़ाने पर विचार कर सकता है। इस बीच जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूरे हो चुके हैं, वहां नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं।

कस्बाई कॉलेजों में बेहतर रही स्थिति

शासकीय कन्या महाविद्यालय, इटारसी के प्रवेश प्रभारी प्रो. डॉ. संजय आर्य के अनुसार तहसील और कस्बाई क्षेत्रों के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही है। उनका कहना है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र सरकारी कॉलेजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। निजी कॉलेजों की अपेक्षाकृत अधिक फीस भी इसका एक कारण है। हालांकि उनके कॉलेज में भी जुलाई में तिथि बढ़ने के बाद केवल लगभग 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें ही भर सकी हैं।

विशेषज्ञों ने बताए कई कारण

उच्च शिक्षा विशेषज्ञ प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी के अनुसार सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों की मांग लगातार घट रही है। उन्होंने इसके पीछे कई प्रमुख कारण बताए। विद्यार्थी बीए और बीएससी जैसे पारंपरिक पाठ्यक्रमों की बजाय प्रोफेशनल और तकनीकी कोर्स चुन रहे हैं। कॉलेज और सीटों की उपलब्धता संबंधी सही जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। सरकारी कॉलेजों में ई-उपस्थिति (75 प्रतिशत अनिवार्यता) का कड़ाई से पालन होने के कारण कई विद्यार्थी निजी कॉलेजों को प्राथमिकता देते हैं, जहां उपस्थिति को लेकर अपेक्षाकृत लचीलापन रहता है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी 12वीं के बाद आईआईटी, नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थानों का रुख कर रहे हैं।

बड़े शहरों में सबसे अधिक सीटें खाली

तुलनात्मक रूप से देखें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के लगभग 60 प्रतिशत सरकारी कॉलेजों में सीटें अभी भी रिक्त हैं। इन शहरों के निजी कॉलेजों में भी लगभग 40 प्रतिशत सीटें खाली पड़ी हैं।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नया पेंच

- 796 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की दोबारा जांच

भोपाल। प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2025 की चयन प्रक्रिया के बीच लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड करने वाले 796 चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का दोबारा सत्यापन कराने का फैसला लिया है। विभाग ने इसके लिए विशेष समिति गठित कर 26 जुलाई तक भोपाल में दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। डीपीआई के अनुसार यह प्रक्रिया केवल उन अभ्यर्थियों के लिए होगी, जिन्होंने वर्ष 2017 से 2019 के बीच एनआईओएस से डीएलएड किया है और 18 से 21 जुलाई के दौरान आयोजित दस्तावेज सत्यापन में शामिल हुए थे। इन सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

डीएलएड प्रमाण पत्र का होगा निरीक्षण

विभाग का कहना है कि एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड करने की अनुमति केवल उन शिक्षकों को दी गई थी, जो पहले से किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत थे। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि चयनित अभ्यर्थियों ने प्रवेश के समय निर्धारित पात्रता पूरी की थी और उनके सेवा संबंधी दस्तावेज एवं डीएलएड प्रमाण पत्र नियमों के अनुरूप हैं। सत्यापन की प्रक्रिया 26 जुलाई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर शिवाजी नगर भोपाल में होगी। अभ्यर्थियों को सभी मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्वप्रमाणित प्रतियां भी लानी होंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी तय समय पर उपस्थित नहीं होता है या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज

- 10वीं, 12वीं और डीएलएड की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र।
- संबंधित विद्यालय में कार्यरत होने का नियुक्ति/कार्यादेश।
- संस्था प्रमुख द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र।
- निर्धारित प्रारूप में 100 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र।

निगम की आय में हो गया इजाफा, करोड़ों का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त

भोपाल। भोपाल नगर निगम द्वारा जनगणना के तहत कराए गए हाउस लिस्टिंग सर्वे में 1.82 लाख अघोषित संपत्तियां सामने आने से निगम की आय में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। इन संपत्तियों पर अब संपत्ति कर लगाया जाएगा, जिससे निगम को हर वर्ष करोड़ों रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। सर्वे के दौरान विशेष रूप से पुराने भोपाल के कई ऐसे मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान चिन्हित हुए, जो वर्षों से नगर निगम के रिकॉर्ड और कर दायरे से बाहर थे, जबकि वे पानी, सीवर और सड़क जैसी नागरिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। अधिकारियों के अनुसार, सबसे अधिक नई संपत्तियां पुराने भोपाल के जोन-5 में मिली हैं। मार्च 2025 तक यहां लगभग 16 हजार संपत्तियां कर दायरे में थीं, लेकिन सर्वे के बाद 17 हजार नई संपत्तियां और सामने आई हैं।

बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक संकट!

- 34 दिन में दूसरे कुलगुरु का इस्तीफा, अनुपम राजन को मिला अतिरिक्त प्रभार

भोपाल । राजधानी भोपाल की प्रसिद्ध बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। विश्वविद्यालय में महज 34 दिनों के भीतर दूसरे कुलगुरु (कुलपति) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रभारी कुलगुरु प्रो. विवेक शर्मा ने स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है, जिसे राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने स्वीकार कर लिया है।

प्रो. विवेक शर्मा के इस्तीफे के बाद नए नियमित कुलगुरु की नियुक्ति होने तक उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन को बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के कुलगुरु का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

यूनिवर्सिटी में विवादों की पूरी क्रोनोलॉजी

बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी पिछले कुछ समय से लगातार विवादों

और अनियमितताओं के आरोपों से घिरी हुई है। 11 जून को परिसर में व्याप्त कथित अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। 12 जून को बढ़ते विवाद के बीच उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने तत्कालीन कुलगुरु प्रो. एस.के. जैन को 'फोर्स लीव' (अनिवार्य अवकाश) पर भेजने का आश्वासन दिया। 18 जून को चौतरफा दबाव के बाद प्रो. एस.के. जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

कब तक नियमित कुलगुरु की नियुक्ति

19 जून को प्रशासन ने प्रो. विवेक शर्मा को विश्वविद्यालय का नया प्रभारी कुलगुरु नियुक्त किया। 23 जुलाई (34 दिन बाद)= प्रो. विवेक शर्मा ने भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा सौंप दिया। लगातार हो रहे इन इस्तीफों और प्रशासनिक अस्थिरता के कारण विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, परीक्षाओं और छात्रों से जुड़े रोजमर्रा के कामकाज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि शासन कब तक यहां नियमित कुलगुरु की नियुक्ति करता है।

अब हर घर, गांव-शहर का एक्स-रे करेगी जनगणना टीम

जनगणना में होगी हर गणना... पानी की टंकी से लेकर अस्पताल के बिस्तर, स्कूल की कक्षा से लेकर मोबाइल नेटवर्क तक हर सुविधा का बनेगा रिपोर्ट कार्ड

भोपाल। जनगणना-2027 इस बार केवल आबादी गिनने तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार गांव और शहर का ऐसा एक्स-रे कराने जा रही है, जिसमें विकास की हर छोटी-बड़ी हकीकत सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगी। जनगणना टीम अगले चरण में गांव-शहर की एक-एक सुविधा की पड़ताल करेगी। किस गांव में पीने का पानी पूरे साल आता है या नहीं, कितने हैंडपंप चालू हैं, अस्पताल में कितने डॉक्टर और कितने बिस्तर हैं, स्कूल में कौन-कौन सी कक्षाएं संचालित हैं, गांव तक पक्की सडक़ पहुंची या नहीं, मोबाइल नेटवर्क कैसा है, बैंक और एटीएम हैं या नहीं।

इस बार सरकार जनगणना नहीं, बल्कि जिले के विकास का आईना तैयार कर रही है। जिन गांवों और शहरों में वर्षों से सडक़, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य सुविधाओं की कमी है, उनकी तस्वीर अब सरकारी दस्तावेजों में दर्ज होगी। 1 अगस्त से ट्रेंड की गई टीमें घर-घर, गली-मोहल्ले जाकर 30 दिन में वास्तविक डाटा तैयार करेंगी। आने वाले वर्षों की योजनाएं, बजट और विकास कार्य इसी विस्तृत रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय किए जाएंगे। हर सवाल का जवाब 32 पेज की जिला जनगणना हस्तपुस्तिका में दर्ज होगा।

मोबाइल ऐप से होगी निगरानी

पूरा सर्वे मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। फील्ड अधिकारी मौके पर जानकारी अपलोड करेंगे, जबकि चार्ज अधिकारी वेब पोर्टल पर उसका सत्यापन करेंगे। यदि कोई जानकारी अधूरी या गलत मिली तो उसे वापस भेजकर दोबारा जांच कराई जाएगी। अंतिम रिपोर्ट तैयार होने से पहले 2011 की जनगणना के रिकॉर्ड से भी मिलान किया जाएगा।

सार्वजनिक सुविधाओं की जानकारी

टीम यह भी देखेगी कि गांव राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से जुड़ा है या नहीं, बस सेवा मिलती है या नहीं, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट उपलब्ध है या नहीं, डाकघर, जनसेवा केंद्र और परिवहन की क्या स्थिति है। रिपोर्ट में एटीएम, बैंक, सहकारी समिति, पुलिस थाना, ग्राम पंचायत भवन, राशन दुकान, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, मंडी, साप्ताहिक हाट, पुस्तकालय, खेल मैदान, सामुदायिक भवन और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की भी जानकारी दर्ज होगी।

बारीकी से होगी हर सुविधा की पड़ताल

जनगणना टीम सबसे पहले गांव और शहर की पहचान दर्ज करेगी। कितने परिवार रहते हैं, कितने टोले या बस्तियां हैं, तहसील और जिला मुख्यालय से कितनी दूरी है और निकटतम शहर कौन सा है, यह सब रिकॉर्ड में शामिल होगा। इसके बाद शिक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। आंगनवाड़ी से लेकर विश्वविद्यालय तक कितने संस्थान हैं, सरकारी हैं या निजी, यदि गांव में नहीं हैं तो सबसे नजदीकी स्कूल या कॉलेज कितनी दूरी पर है, इसका भी रिकॉर्ड तैयार होगा।

स्वास्थ्य के साथ पानी की हर बूंद और नाली का भी हिसाब

स्वास्थ्य सेवाओं की जांच में यह देखा जाएगा कि गांव में उपस्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, मातृ-शिशु केंद्र, टीबी क्लिनिक, वेलनेस सेंटर, एंबुलेंस, दवा दुकान और पशु चिकित्सालय हैं या नहीं। अस्पताल में कितने बिस्तर, कितने डॉक्टर और कितना पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है, यह भी दर्ज किया जाएगा। सर्वे में यह भी दर्ज होगा कि गांव में पानी का स्रोत क्या है—नल-जल योजना, हैंडपंप, ट्यूबवेल, कुआं, तालाब, नदी या झरना। गर्मी में पानी मिलता है या नहीं, पूरे साल जल उपलब्ध रहता है या नहीं, नालियां पक्की हैं या कच्ची, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है या नहीं और सामुदायिक शौचालय उपलब्ध हैं या नहीं, इसका भी पूरा ब्योरा लिया जाएगा।

जेपी अस्पताल में बवाल...कर्मचारियों ने दी आत्मदाह की चेतावनी

21 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने से अस्पताल की व्यवस्था चरमराई

भोपाल । राजधानी के जयप्रकाश (जेपी) अस्पताल में जिला रोगी कल्याण समिति के माध्यम से वर्षों से कार्यरत 21 कर्मचारियों की सेवाएं अचानक समाप्त किए जाने के बाद विवाद गहरा गया है। शुक्रवार को कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान 58 वर्षीय एम्बुलेंस चालक रमेश शर्मा ने न्याय नहीं मिलने पर अस्पताल के गेट नंबर-21 के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दे दी। रमेश शर्मा ने कहा, यह सेवा समाप्ति नहीं, मेरा जीवन समाप्त करना है। 58 साल की उम्र में अब मुझे कौन नौकरी देगा? अगर न्याय नहीं मिला तो यहीं आत्मदाह करूंगा।

कर्मचारियों का आरोप है कि 22 जुलाई को सुबह नियमित ड्यूटी करने के बाद करीब 11 बजे उन्हें अचानक सेवा समाप्ति का आदेश थमा दिया गया। न कोई कारण बताया गया और न ही पक्ष रखने का अवसर दिया गया। हटाए गए कर्मचारियों में वाहन चालक, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और कम्प्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। इनमें कई कर्मचारी 20 से 25 वर्षों से अस्पताल में सेवाएं देने का दावा कर रहे हैं।

हार्ट अटैक के बाद नौकरी जाने का दर्द

एम्बुलेंस चालक रमेश शर्मा ने बताया कि वह वर्ष 1999 से अस्पताल में कार्यरत हैं और कोरोना काल में भी लगातार ड्यूटी करते रहे। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था और चिकित्सकों ने दो सप्ताह के भीतर एंजियोप्लास्टी कराने की सलाह दी है। ऐसे समय में नौकरी खत्म होने से उनका परिवार आर्थिक संकट में आ गया है।

वेतन कटौती के भी लगाए आरोप

कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन पर मनमाने ढंग से वेतन काटने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि महीने में 14 से 15 हजार रुपये वेतन मिलता है, लेकिन बायोमीट्रिक या रात्रि ड्यूटी के बाद मिलने वाले अवकाश को अनुपस्थिति मानकर कई दिनों का वेतन काट लिया जाता था। कर्मचारियों का दावा है कि कई बार 8 से 10 दिन तक का वेतन काटा गया।

2019 के आदेश की गलत व्याख्या का दावा

कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें हटाने के लिए वर्ष 2019 के शासनादेश का हवाला दिया गया है, जबकि वह आदेश 2019 के बाद नई नियुक्तियां नहीं करने से संबंधित था। उनका आरोप है कि वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों पर इस आदेश को लागू कर सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

अस्पताल की व्यवस्था पर असर

21 कर्मचारियों के हटने के बाद अस्पताल की व्यवस्था भी प्रभावित होने लगी है। पंजीयन काउंटरों पर मरीजों को एक से दो घंटे तक लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का दावा है कि फार्मेसी में नियमित स्टाफ की कमी के कारण इंटर्न छात्रों के माध्यम से दवाइयां वितरित कराई जा रही हैं। कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा कि अस्पताल पहले से स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारियों को हटाना अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की सेवाएं बहाल नहीं की गईं तो अस्पताल में धरना और भूख हड़ताल की जाएगी।

एम्स में मरीजों को बड़ी राहत

- 15 अगस्त से स्मार्ट कार्ड से होगा कैशलेस भुगतान, लंबी कतारों से मिलेगी छुट्टी

भोपाल। एम्स भोपाल में इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब अस्पताल में फीस और अन्य भुगतान के लिए नकद रुपये लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। एम्स ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सहयोग से प्री-पेड स्मार्ट कार्ड सुविधा शुरू की है, जो 15 अगस्त 2026 से मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। इस कार्ड की मदद से मरीज अस्पताल की विभिन्न सेवाओं का भुगतान कैशलेस और कुछ ही मिनटों में कर सकेंगे। इससे भुगतान काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों से भी छुटकारा मिलेगा।

एम्स प्रशासन के अनुसार, बाहर से आने वाले मरीजों को अब अपने साथ अधिक नकद राशि रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट कार्ड में राशि जमा कर अस्पताल की अलग-अलग सेवाओं का भुगतान आसानी से किया जा सकेगा। इससे इलाज की पूरी प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और तेज होगी।

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बड़ा कदम

एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रो. (डॉ.) माधवानन्द कर ने कहा कि यह पहल अस्पताल को पूरी तरह डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। स्मार्ट कार्ड से भुगतान में समय बचेगा और मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

22 जुलाई को हुआ शुभारंभ

स्मार्ट कार्ड सेवा का शुभारंभ 22 जुलाई को एम्स भोपाल और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था से मरीजों का अनुभव पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और परेशानी मुक्त होगा।

जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज अपने नाम करने उतरेगी भारतीय टीम

हरारे। भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार को यहां होने वाले दूसरे टी20 क्रिकेट मुकाबले में मेजबान जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त दर्ज करने उतरेगी। भारतीय टीम ने पहले टी20 मैच को आसानी से जीता था जिससे उसके हौंसले बुलंद हैं। भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज लय में हैं जिसका लाभ टीम को मिलेगी। वहीं मेजबान टीम पहले मैच में हार के कारण दबाव में रहेगी। मेजबान जिम्बाब्वे अगर ये मैच हारी तो मुकाबला उसके हाथों से निकल जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली युवा भारतीय टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की थी। इस जीत ने टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों का मनोबल बढ़ा हुआ है। भारतीय टीम की जीत का श्रेय जबरदस्त बल्लेबाजी और अनुशासित गेंदबाजी को जाता है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पहले मैच में 19 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। उनके साथ ईशान किशन ने 35

और कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 28 रन बनाये थे। वहीं भारतीयय गेंदबाजों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव ने मैच में अच्छी गेंदबाजी कर प्रभावित किया। मयंक ने मात्र 18 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं प्रिंस यादव ने भी दो विकेट लिए। इस शानदार जीत ने भारत के उभरते सितारों पर सबका ध्यान खींचा है। हरारे एक बार फिर देश की अगली पीढ़ी के लिए अपने को साबित करने का मैदान बन गया है, जहाँ वैभव और मयंक यादव अब भारत के दबदबे को बनाए रखने और शीर्ष स्तर पर अपनी काबिलियत साबित करने की उम्मीदों को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि, जिम्बाब्वे के लिए स्थिति साफ है- या तो जीतें या सीरीज हारें। पहले मैच में पारी की पहली ही गेंद पर बेनेट का विकेट गंवाने के बाद सिकंदर रजा की टीम उबर नहीं पाई; सिर्फ वेस्ली मधेवेरे (39), तादिवानाशे मारुमनी (27) और रयान बर्ल (26) ही कुछ संघर्ष दिखा सके। मेजबान टीम को अपने शीर्ष क्रम से कहीं बेहतर प्रदर्शन की ज़रूरत होगी, जबकि तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुज़राबानी और रिचर्ड नगारवा को शुरुआती विकेट लेने होंगे ताकि भारत के आक्रामक बल्लेबाजों को एक बार फिर मैच पर हावी होने से रोका जा सके। अब देखना होगा कि मेजबान टीम वापसी कर पाती है या नहीं।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं -

जिम्बाब्वे टीम- सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), डियोन मायर्स, रयान बर्ल, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, वेस्ली मधेवेरे, इनोसेंट काइया, रिचर्ड नगारवा, तनाका चिवांगा, ब्लेसिंग मुजरबानी, बेन करन, तफादजवा त्सिगा, न्यूमैन न्यामहुरी

भारतीय टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान),अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई।

एशियाई खेलों का कार्यक्रम जारी, सेमीफाइनल में पहुंचे तो ही होगा भारत-पाक मुकाबला

आइची-नागोया। जापान के आइची-नागोया में होने वाले 2026 एशियाई खेलों के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम पुरुष और महिला दोनों वर्ग में अपना खिताब बरकरार रखने उतरेगी। इस दौरान हालांकि सभी की नजरें भारत-पाकिस्तान के संभावित महामुकाबले पर लगी होंगी पर ये तभी होगा जब दोनो ही टीमें सेमीफाइल में पहुंचेंगी। एशियाई खेलों में क्रिकेट को चौथी बार शामिल किया जा रहा है। इससे पहले यह ग्वांगझू में साल 2010, इंचियोन में साल 2014 और हांग्जो 2023 में भी खेला गया था।

पुरुष और महिला दोनों ही प्रतियोगिताओं को टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। महिलाओं का टूर्नामेंट 17 से 22 सितंबर तक चलेगा, जबकि पुरुषों के मुकबले 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। सभी मैच आइची प्रीफेक्चर के कोरोगी एथलेटिक पार्क में खेले जाएंगे।

इस बार टूर्नामेंट में कुछ शीर्ष टीमों को सीधे ही क्वार्टर-फाइनल में प्रवेश मिला है। पुरुष वर्ग में भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को शीर्ष वरीयता मिली है। इससे ये तीनो ही सीधे अंतिम-आठ में प्रवेश करेंगे। वहीं शेष चार क्वार्टर-फाइनल स्थानों के लिए मुकाबले होंगे। प्रारंभिक राउंड में छह टीमें के दो समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल को रखा गया है। वहीं हांगकांग चीन, मलेशिया और ओमान ग्रुप बी में रहेंगे। इन ग्रुप से शीर्ष दो टीमें क्वार्टर-फाइनल में आगे जाएंगी और वरीयता प्राप्त टीमों से भिड़ेंगी। पुरुष क्वार्टर फाइनल में भारत पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सभी टीमें अपने अभियान की शुरुआत में क्वालीफ़ायर टीमों से खेलेंगी।

इसी कारण भारत-पाक का सामन केवल एक बार हो सकता है। वह भी अगर दोनो सेमीफाइल में पहुंचती हैं तो। इसके अलावा फाइनल में भी इनकी टक्कर हो सकती है।

महिला टीम को भी सीधे ही क्वार्टर-फाइनल में जगह मिली है। भारतीय महिला टीम अपना शुरुआती मुकाबला मेजबान जापान से खेलेगी। वहीं इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश या चीन से खेलेगी। इनमें दूसरा क्वार्टर-फाइनल मुकाबला होगा। वहीं अन्य क्वार्टर-फाइनल मुकाबलों की बात करें तो श्रीलंका का सामना मलेशिया से होगा, जबकि पाकिस्तान थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा। टूर्नामेंट का प्रारुप इस प्रकार बनाया गया है कि शीर्ष टीमें सीधे नॉकआउट स्तर में एक दूसरे का सामना करें।

एशियाई खेलों में पुरुष वर्ग का कार्यक्रम
ग्रुप ए- अफगानिस्तान, जापान, नेपाल
ग्रुप बी- हांगकांग चीन, मलेशिया, ओमान
क्वार्टर फाइनल मैचों का शेड्यूल
भारत बनाम क्वालीफायर
पाकिस्तान बनाम क्वालीफायर
श्रीलंका बनाम क्वालीफायर
बांग्लादेश बनाम क्वालीफायर
महिला क्रिकेट क्वार्टर फाइनल का कार्यक्रम
भारत बनाम जापान
बांग्लादेश बनाम चीन
श्रीलंका बनाम मलेशिया
पाकिस्तान बनाम थाईलैंड

भारतीय पुरुष टीम- श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती और वैभव सूर्यवंशी।

महिला टीम- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और नंदनी शर्मा।

शास्त्री ने 2027 एकदिवसीय विश्वकप के लिए अपनी पसंदीदा टीम- में विराट, रोहित और भुवनेश्वर को भी शामिल किया

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने आगामी 2027 एकदिवसीय विश्वकप के लिए अपनी पसंदीदा 15 सदस्यीय अंतिम ग्यारत टीम चुनी है। शास्त्री ने अपनी टीम में अनुभवी के साथ ही युवा खिलाड़ियों को भी शामिल किया है। टीम की कप्तानी शुभमन गिल को मिली है। टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा व तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भी शामिल किया है। शास्त्री का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले इस टूर्नामेंट के दौरान टीम को कोहली और रोहित जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की भी जरुरत पड़ेगी। शास्त्री की इस टीम में अनुभव को प्राथमिकता दी गई है। शास्त्री का मानना है कि बड़े मुकाबलों में अनुभवी खिलाड़ियों की जरुरत रहती है। शास्त्री ने टीम में वर्तमान कोच गौतम गंभीर की तरह अधिक प्रयोग न करते हुए अनुभवी और स्थापित खिलाड़ियों को ही जगह दी है। उन्होंने जिस प्रकार से अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया है वह दिखाता है कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। भुवनेश्वर लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं पर इसके बाद भी शास्त्री ने उनकी स्विंग गेंदबाजी और अनुभव पर भरोसा जताया है। वहीं यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ी को शामिल करने से पता चलता है कि शास्त्री ऐसी टीम चाहते हैं जिसमें अनुभव और स्थिरता के साथ-साथ अच्छे फॉर्म में चल रहे युवा क्रिकेटर भी हों। कुल मिलाकर शास्त्री की 2027 एकदिवसीय कप टीम में अनुभवी के साथ ही उभरती हुई प्रतिभाओं को भी जगह मिली है।

शास्त्री की चयनित टीम इस प्रकार है

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव।

ईसीबी ने 2027 एशेज सीरीज का कार्यक्रम जारी किया

18 जून से ट्रेंट ब्रिज में शुरु होगी पुरुषों की टेस्ट सीरीज : महिला टीमों के मुकाबले 24 जून को हेडिंग्ले में शुरु होंगे

लंदन। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने अगले साल 2027 में होने वाली एशेज सीरीज का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जहां इंग्लैंड की पुरुष टीम अगले साल 18 जून से ट्रेंट ब्रिज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने एशेज अभियान की शुरुआत करेगी। वहीं महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत 24 जून से हेडिंग्ले में करेगी।

पुरुषों की पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 18 जून को ट्रेंट ब्रिज में शुरू होगी। इसके बाद उसे लॉर्ड्स, एजबेस्टन और यूटिलिटा बाउल (साउथेम्प्टन) में खेलना है। इस प्रतिष्ठित सीरीज का समापन 29 जुलाई का द ओवल में होगा। यह सीरीज 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगी।

वहीं इंग्लैंड की महिला टीम अपने एशेज अभियान की शुरुआत 24 जून को हेडिंग्ले में एक टेस्ट मैच के साथ करेगी। यह 2001 के बाद लीड्स में आयोजित होने वाला पहला महिला एशेज टेस्ट होगा, जिससे ये मुकाबला और भी खास बन जाएगा। टेस्ट मैच के बाद 3 से 9 जुलाई के बीच ट्रेंट ब्रिज, द किया ओवल और एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में तीन टी20 मैच खेले जाएंगे। इसके बाद, 13 से 20 जुलाई के बीच यूटिलिटा बाउल, लॉर्ड्स और एजबेस्टन में तीन एक दिवसीय मैच आयोजित किये जाएंगे।

एशेज मुकाबलों के अलावा, ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 7 से 10 जून तक एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड लायंस कीटीम के बीच चार दिवसीय वार्म-अप मैच आयोजित करने पर भी सहमति जतायी है।

कार्यक्रम इस प्रकार है -

18 ङ्क22 जून- पहला एशेज टेस्ट मैच (ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम) 30 जून से 4 जुलाई- दूसरा एशेज टेस्ट (लॉर्ड्स, लंदन) 8ङ्क12 जुलाई- तीसरा एशेज टेस्ट (एजबेस्टन, बर्मिंघम) 21ङ्क25 जुलाई- चौथा एशेज टेस्ट (यूटिलिटा बाउल, साउथेम्प्टन) 29 जुलाई से 2 अगस्त- पांचवां एशेज टेस्ट (द किया ओवल, लंदन) इंग्लैंड विमेंस वर्सेज ऑस्ट्रेलिया विमेंस ङ्क मेट्रो बैंक महिला एशेज 24ङ्क27 जून- एशेज टेस्ट मैच (हेडिंग्ले, लीड्स) 3 जुलाई- पहला वाइटैलिटी टी20 (ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम) 6 जुलाई- दूसरा वाइटैलिटी टी20 (द किया ओवल, लंदन) 9 जुलाई- तीसरा वाइटैलिटी टी20 (एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर) 13 जुलाई- पहला वनडे (यूटिलिटा बाउल, साउथेम्प्टन) 16 जुलाई- दूसरा वनडे (लॉर्ड्स, लंदन) 20 जुलाई- तीसरा वनडे (एजबेस्टन, बर्मिंघम)।

15 साल की उम्र में वैभव से पहले नेपाल के कुशल ने लगाया था अर्धशतक

हरारे। भारत के वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही टी20 क्रिकेट मैच में अर्धशतकीय पारी खेलकर छाये हुए हैं। वैभव इसी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र मे अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन ये हैं। वैभव ने 15 साल 118 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाय है। वहीं अगर बात की जाये कि सबसे पहले 15 साल की उम्र में किसने अंतरराष्टीय क्रिकेट मे अर्धशतक लगाय था तो वह नेपाल के ऑलराउंडर कुशल मल्ला थे। कुशल ने 8 फरवरी, 2020 को अमेरिका के खिलाफ एक दिवसीय अंतरराष्टीय मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की थी, तब वह भी 15 साल के थे। उनके इस प्रदर्शन ने उस समय क्रिकेट जगत में काफी सुर्खियां बटोरी थीं और उन्हें सबसे कम उम्र के अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में पहचान मिली थी। हालांकि विश्व रिकॉर्ड वैभव के नाम पर इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि कुशन ने जब अर्धशतक लगाया था तब उनकी उम्र 15 साल 340 दिन थी जबकि वैभव ने 15 साल और 118 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया है।

मुरलीधरन ने करियर के अंतिम मैच में पूरे किये थे अपने 800 टेस्ट विकेट

कोलंबो। विश्व क्रिकेट में एक से बढ़कर एक स्पिनर हुए हैं उन्हीं में से एक हैं श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन। ीधरन ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को नचाया है। उनके नाम 800 टेस्ट विकेट का ऐतिहासिक रिकार्ड है जो आज तक कायम है। दुनिया को कोई भी स्पिनर उनका ये रिकार्ड तोड़ने की बात तो दूर उनके पास भी नहीं पहुंच पाया है। मुरलीधरन ने अपने अंतिम मैच में भी एक अनोखा रिकार्ड अपने नाम किया था। उन्होंने इस मैच में 8 विकेट लेकर अपने 800 विकेट पूरे किये थे। भारत के खिलाफ हुए इस मैच में मुरलीधरन भारतीय टीम के स्टार ऑलराउडर युवराज सिंह, हरभजन सिंह सहित कई खिलाड़ियों को आउट किया था।

भारतीय मूल के आर्यन और जेसन भी शामिल

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट (सीए) अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करने और उन्हें स्पिन से निपटने के गुर सिखाने के लिए भारतीय हालातों में भी प्रशिक्षण देने की योजना बनायी है। इसी के तहत ही सीए ने अपनी एक विशेष डेवलपमेंट टीम का चयन किया है, जो अगले महीने अगस्त की शुरुआत में चेन्नई स्थित प्रतिष्ठित एमआरएफ पेस अकादमी में इन खिलाड़ियों के गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। ऑस्ट्रेलियई दल में भारतीय मूल के दो उभरते हुए खिलाड़ी, आर्यन शर्मा और जेसन सांघा, भी शामिल हैं, जिन पर सीए की नजरें विशेष रुप से लगी हैं।

यह टीम 1 से 13 अगस्त तक चेन्नई में रहेगी और इस दौरान टीम के युवा खिलाड़ियों को स्पिन-अनुकूल पिचों पर खेलने और अभ्यास करने का अच्छा अनुभव मिलेगा। सीए के लिए यह दौरा केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक रणनीतिक निवेश है, खासकर जब उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में स्पिन के खिलाफ अपनी चुनौतियों का सामना करना होता है। भारतीय मूल के आर्यन शर्मा और जेसन सांघा की टीम में मौजूदगी इस दौरे को और भी दिलचस्प बनाती है। उनकी जड़ों और भारतीय हालातों से संभावित परिचितता उन्हें टीम के लिए एक अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकती है, साथ ही यह दिखाता है कि सीए किस प्रकार से प्रतिभाओं को बढ़ावा देता है। चेन्नई दौरे के दौरान, यह युवा ऑस्ट्रेलियाई टीम दो दिवसीय प्रारूप के दो अभ्यास मैच भी खेलेगी। पहला मैच 5 से 6 अगस्त को होगा, जबकि दूसरा 10 से 11 अगस्त को खेला जाएगा। इन मैचों के लिए विशेष रूप से स्पिनरों के अनुकूल पिचें तैयार की जाएंगी, ताकि खिलाड़ियों को वास्तविक खेल स्थितियों में स्पिन गेंदबाजी का सामना करने और उसे समझने का मौका मिल सके। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट किया है कि चेन्नई का यह दौरा उनके राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य देश के सबसे होनहार खिलाड़ियों को उनके खेल कौशल में निखार लाने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल होने के लिए तैयार करना है।

इस महत्वपूर्ण दल का मार्गदर्शन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान टिम पेन और एंथनी क्लार्क को कोच नियुक्त किया गया है। पेन का अनुभव और नेतृत्व युवा खिलाड़ियों के लिए अमूल्य साबित होगा, जबकि क्लार्क भी उन्हें तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं पर मार्गदर्शन करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विकास प्रमुख सोन्या थॉम्पसन ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह दौरा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में प्रतिभा का आकलन करने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह खिलाड़ियों के निरंतर विकास को सुनिश्चित करेगा और उन्हें विदेशों की अनूठी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का अनुभव हासिल करने में मदद करेगा।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन सहित सबसे अधिक रन बनाने वाले पांच खिलाड़ी

मुम्बई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में पहले नंबर पर हैं। तेंदुलकर को संन्यास लिए एक दशक से भी अधिक समय जो गया है पर कोई भी खिलाड़ी उनके बनाये रनों के रिकार्ड के तोड़ नहीं पाया है। टेस्ट, एकदिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय तीनों प्रारूपों को मिलाकर, सचिन ने अपने 24 वर्ष के अद्वितीय करियर में कुल 34,357 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर भारत के ही अनुभवी विराट कोहली हैं, इसके बाद श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज रिकी पोंटिंग और श्रीलंका के ही माहेला जयवर्धने का नंबर आता है। इस सभी ने विश्वक्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया है पर इसके बाद भी सचिन का रिकार्ड नहीं तोड़ पाये हैं। इनमें से अब केवल विराट ही सक्रिय क्रिकेट हैं जो एकदिवसीय प्रारुप में खेल रहे हैं। ऐसे में अब केवल विराट के पास ही उनके रिकार्ड को तोड़ने का अवसर है।

गौरतलब है कि तेंदुलकर ने साल 1989 से 2013 के बीच भारत के लिए कुल 664 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। इनमें उन्होंने 782 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 74 बार नाबाद रहकर 48.52 की प्रभावशाली औसत से 34,357 रन बटोरे। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 248 रन रहा। उनके नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक और 164 अर्धशतक दर्ज हैं, जो आज भी विश्व रिकॉर्ड हैं और उनकी अद्वितीय बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाते हैं। अपने करियर में उन्होंने 50,000 से अधिक गेंदों का सामना किया और उनके चार हजार से ज्यादा चौके तथा 264 छक्के लगाये।

वहीं विराट दूसरे नंबर पर हैं। वह सचिन के

रिकॉर्ड के सबसे करीब पहुंचे है। वर्ष 2008 से अब तक अपने शानदार करियर में कोहली ने 562 मैचों की 629 पारियों में 91 बार नाबाद रहते हुए 52.71 की असाधारण औसत से 28,359 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 254 रन है। विराट के नाम 85 शतक और 148 अर्धशतक दर्ज हैं। 79.73 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले विराट को आधुनिक क्रिकेट के सबसे सफल और प्रभावशाली बल्लेबाजों में से एक माना जाता है, और उनके पास अभी भी सचिन के रिकॉर्ड को चुनौती देने का अवसर है।

तीसरे स्थान पर श्रीलंका के महान विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार संगकारा हैं, जिन्होंने 2000 से 2015 के बीच 594 मैचों की 666 पारियों में 46.77 की औसत से 28,016 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 319 रन रहा। संगकारा ने 63 शतक और 153 अर्धशतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दो बार के विश्व कप विजेता पोंटिंग इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 1995 से 2012 तक 560 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 668 पारियों में 45.95 की औसत से 27,483 रन बनाए। पोंटिंग ने अपने करियर में 71 शतक और 146 अर्धशतक लगाएहै। पांचवें स्थान पर श्रीलंका के एक और दिग्गज बल्लेबाज माहेला जयवर्धने हैं, जिन्होंने 1997 से 2015 तक 652 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 725 पारियों में 40.81 की औसत से 25,957 रन बनाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 374 रन रहा। जयवर्धने के नाम 54 शतक और 136 अर्धशतक दर्ज हैं। ये सभी पांचों बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में निरंतरता, असाधारण कौशल और लंबे समय तक उत्कृष्ट प्रदर्शन के प्रतीक हैं। हालांकि, इन सभी महान खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रनों का सचिन का रिकॉर्ड आज भी अटूट है।

इंग्लैंड में घरेलू वनडे क्रिकेट में होगा स्टोक्स और कुलदीप का मुकाबला

लंदन। इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने एक दशक से अधिक समय के बाद घरेलू वनडे क्रिकेट में धमाकेदार वापसी करते हुए डरहम की ओर से नाबाद शतक लगाकर दिखाया है कि वह अभी भी एक मैच विजेता खिलाड़ी हैं। वहीं अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें 31 जुलाई पर टिकी हैं, जब क्लिफ्टन पार्क ग्राउंड, यॉर्क में डरहम का सामना यॉर्कशायर से होगा। यह मुकाबला सिर्फ दो काउंटी टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं होगी, बल्कि इसमें स्टोक्स का सामना भारतीय चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव से होगा।

कुलदीप यादव के लिए यह टूर्नामेंट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई एकदिवसीय सीरीज में उन्हें भारतीय टीम में शामिल होने के बावजूद एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था, जिस पर कई क्रिकेट विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने सवाल उठाए थे। उनकी गैरमौजूदगी को लेकर काफी आलोचना भी हुई थी, क्योंकि वे अपनी फिरकी से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में, वन-डे कप कुलदीप के लिए अपनी लय वापस पाने, अपनी गेंदबाजी का जौहर दिखाने और चयनकर्ताओं को यह याद दिलाने का एक सुनहरा मौका होगा कि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में कितने प्रभावी हो सकते हैं। वह निश्चित रूप से यॉर्कशायर के लिए खेलते हुए अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे और आगामी अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे।

बेन स्टोक्स और कुलदीप यादव अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में अब तक पांच बार आमने-सामने आ चुके हैं। इन भिड़ंतों में स्टोक्स ने कुलदीप की 59 गेंदों पर 47 रन बनाए हैं, लेकिन एक बार वह भारतीय स्पिनर का शिकार भी बने हैं। उनकी सबसे यादगार टक्कर 2018 में ट्रेंट ब्रिज में हुई थी, जहां कुलदीप यादव ने अपने करियर का एक बेहतरीन स्पेल डाला था। उस मैच में उन्होंने अपनी जादुई फिरकी से इंग्लैंड की बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करते हुए शानदार छह विकेट झटके थे, जिसमें बेन स्टोक्स का महत्वपूर्ण विकेट भी शामिल था। उस दिन कुलदीप ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए भारत को एकतरफा जीत दिलाई थी और दिखाया था कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को भी कैसे परेशानी में डाल सकते हैं। कुलदीप यादव यॉर्कशायर के लिए अपना पहला मैच 24 जुलाई को ग्लैमॉर्गन के खिलाफ खेलेंगे, जो उन्हें आगामी बड़े मुकाबले से पहले टीम के साथ सामंजस्य बिठाने और अपनी फॉर्म को परखने का अवसर प्रदान करेगा। स्टोक्स की शानदार वापसी और कुलदीप की खुद को साबित करने की चुनौती, ये दोनों कारक आगामी वन-डे कप के मैचों को बेहद रोमांचक बना रहे हैं।

अनाहत वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश के सेमीफाइनल में पहुंची

ओंटारियो। भारत की अनाहत सिंह ने जीत के साथ ही लगातार दूसरी बार वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश के सेमीफाइनर में प्रवेश किया है। अनाहत ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। अनाहत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मिस्त्र की हबीबा रिजक को 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत का सामना मिस्त्र की ही बारब सामेह से होगा।

वहीं महिला वर्ग के अन्य मुकाबलों में भी मिस्त्र की ही खिलाड़ी हावी रहीं। बारब सामेह और मलिका एल्कराक्सी ने हांगकांग, चीन की हेलेन टैंग और बेल्जियम की सवाना मोक्सहैम को सीधे गेम में हराकर अंतिम चार में जगह बनायी। बारब ने हेलेन को 11-1, 11-9, 11-7 से और मलिका ने सवाना को 11-8, 11-8, 11-5 से हराया। इसके अलावा, मिस्त्र की रुकैया सलेम ने भी एक बेहद रोमांचक मुकाबले में मलेशिया की व्हिटनी विल्सन को पांच गेम तक चले मुकाबले के बाद अंतिम चार में अपनी जगह बनायी। रुकैया ने 4-11, 11-5, 8-11, 11-9, 11-7 के स्कोर से जीत दर्ज की।

दूसरी ओर पुरुष वर्ग में भी कई दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। इसमें भी मिस्त्र के ही खिलाड़ी हावी रहे। दूसरी वरीयता प्राप्त मिस्त्र के एडम हवल ने सऊदी अरब के मोहम्मद अलनासफान को 3-1 (11-2, 10-12, 11-3, 11-3) से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। एक अन्य कड़े मुकाबले में, मिस्त्र के मारवान असल ने फ्रांस के अमीर खालिद-जौसेलिन को पांच गेम तक चले संघर्षपूर्ण मैच में 11-7, 7-11, 7-11, 11-6, 11-7 से हराया।

वैभव टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने

हरारे। भारतीय टीम के उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ही टी20 क्रिकेट मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेलकर एक अहम उपलब्धि अपने नाम की है। इसी के साथ ही वैभव सबसे कम उम्र में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पचास रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बन गये हैं। वैभव की उम्र अभी केवल 15 साल 118 दिन है और वह अंतराष्टीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय हैं। वैभव ने केवल 19 गेंदों में तेजी सेअर्द्धशतक लगाकर अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वैभव ने अपनी इस पारी में टी20 में उम्र को लेकर बनाये सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले, टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड जिब्राल्टर के लुईस ब्रूस के नाम था, जिन्होंने 2021 में माल्टा के खिलाफ 16 साल और 56 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।

बाहीटोला का रास्ता बंद, 200 ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित

स्कूली बच्चों और मजदूरों का आवागमन ठप

पद्मेश न्यूज। बैहर। ग्राम पंचायत बिरवा के बाहीटोला में एक रास्ते को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के एक कृषक द्वारा सार्वजनिक आवागमन के रास्ते को खोदकर बंद कर दिया गया है और उस पर धान की रोपाई कर दी गई है। इससे करीब 50 परिवारों की लगभग 200 की आबादी का आवागमन गंभीर रूप से प्रभावित हो गया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, मजदूरों, किसानों और जरूरतमंद लोगों को उठानी पड़ रही है।ग्रामीणों के अनुसार 28 मार्च 2026 को धनु नागेश्वर के यहां से बारात लौटने के दिन से ही संबंधित कृषक ने रास्ता खोदकर गड्ढा कर दिया था। इसके बाद से गांव के लोगों का सामान्य आवागमन बाधित है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत कर रास्ता बहाल कराने की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने स्वयं गड्ढे को समतल कर आवागमन शुरू कराया। आरोप है कि इसके बाद संबंधित कृषक ने दोबारा रास्ता खोद दिया

और अब सड़क पर धान की रोपाई कर लोगों के आने-जाने का मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है।ग्रामीणों ने बताया कि 3 जुलाई को महिलाओं और पुरुषों ने संयुक्त रूप से बैहर तहसील कार्यालय में लिखित आवेदन देकर रास्ता खुलवाने और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी। शिकायतकर्ताओं में दुर्गेश दायरे, खेमचंद दीवान, श्यामलाल पांजरे, पार्वतीबाई पंचतिलक, प्रीति बाई खरे, स्नेहा दीवान और रेशमा दीवान सहित कई ग्रामीण शामिल हैं।ग्रामीणों का कहना है कि बाहीटोला के लोगों को बैहर आने-जाने के लिए अब मजबूरी में कमर तक पानी वाली नदी पार करनी पड़ रही हैमजिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई, मजदूरों का रोजगार, किसानों के कृषि कार्य तथा अन्य शासकीय कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सरपंच की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि समस्या के समाधान में अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। उनका कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जिससे लोगों में भारी नाराजगी है।ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर रास्ता बहाल कराने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।ताकि बाहीटोला के लोगों को राहत मिल सके।

सालेटेकरी में माध्यमिक शाला के नवीन भवन के लिए 51 लाख रुपये स्वीकृत

नया भवन बनने तक प्राथमिक शाला में दो पाली में लगेंगी कक्षा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। समाचार पत्रों में बिरसा विकासखंड के ग्राम सालेटेकरी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला के जर्जर भवन संबंधी प्रकाशित समाचार के बाद सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक श्री जी.पी. बर्मन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ग्राम सालेटेकरी की शासकीय माध्यमिक शाला का पुराना भवन जर्जर हो चुका है, जबकि शासकीय प्राथमिक शाला का भवन पूरी तरह सुरक्षित एवं अच्छी स्थिति में है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा माध्यमिक शाला के नए भवन के निर्माण के लिए 51 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। श्री बर्मन ने बताया कि नए भवन के निर्माण तक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय का संचालन प्राथमिक शाला भवन में ही किया जाएगा। इसके लिए दो पालियों में कक्षाएं संचालित करने की व्यवस्था की गई है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं प्रातःकालीन पाली में संचालित की जा रही हैं, जबकि कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं दोपहर की पाली में लगाई जा रही हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित रहेगी।

जिला परियोजना समन्वयक ने कहा कि नए भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद माध्यमिक विद्यालय को आधुनिक एवं सुरक्षित भवन उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक विद्यार्थियों की शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू रहेगी।

कनिष्का भीमटे नवोदय विद्यालय हेतु चयनित

पद्मेश न्यूज। किरनापुर। तहसील मुख्यालय ग्राम पंचायत किरनापुर निवासी सरोज भीमटे एवं प्रियंका भीमटे की सुपुत्री कुमारी कनिष्का भीमटे पी एम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मुरझड़ मे कक्षा छठवीं के लिए चयन हुआ है। बताए कि ब्राइट कैरियर इंग्लिश स्कूल किरनापुर मे अध्ययनरत प्रतिभावान छात्रा कुमारी कनिष्का भीमटे ने कक्षा पांचवीं मे भी 89.75 प्रतिशत अंक हासिल कर अपने माता पिता का नाम गौरान्वित किया था। बहरहाल कनिष्का भीमटे के पी एम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय मुरझड़ मे कक्षा छठवीं के लिए चयनित होने पर छात्रा के परिजनों, विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं, नाते रिश्तेदारो एवं समस्त सामाजिक बन्धुओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए मेधावी छात्रा कुमारी कनिष्का भीमटे को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे बालाघाट के सिद्धार्थ गेडाम, VVVP-2026 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चयन

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। ग्राम मंझारा (भरवेली) निवासी नेशनल वॉलिंटियर सिद्धार्थ गेडाम का चयन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित My Bharat Viksit Vibrant Village Programme (VVVP)-2026 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। कार्यक्रम के अंतर्गत 26 जुलाई 2026 को देशभर से चयनित युवा प्रतिभागियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशेष संवाद करेंगे, जिसमें सिद्धार्थ गेडाम मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

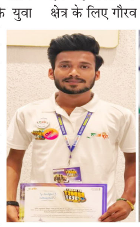

सिद्धार्थ गेडाम इस क्षेत्र के बालाघाट, सिवनी, मंडला, नैनपुर एवं छिंदवाड़ा सहित पाँच जिलों में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने वाले एकमात्र युवा प्रतिभागी हैं। यह उपलब्धि जिले और पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। इससे पहले भी सिद्धार्थ विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में बालाघाट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं Budget Quest-2026 में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर उन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रत्यक्ष संवाद का अवसर भी प्राप्त हुआ था। वे MY Bharat के विभिन्न राष्ट्रीय युवा अभियानों और जनभागीदारी कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

सिद्धार्थ ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुओं एवं भारत सरकार द्वारा युवाओं को दिए जा रहे अवसरों को दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ पुनः संवाद का अवसर उनके लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उनकी यह सफलता ग्रामीण अंचलों के युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है और यह साबित करती है कि प्रतिभा और मेहनत के बल पर देश के सर्वोच्च मंच तक पहुंचा जा सकता है।

पेट्रोल में 20 फीसदी से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि फिलहाल पेट्रोल में 20 फीसदी से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार ने साफ किया कि भविष्य में यदि एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने पर विचार किया जाता है, तो उससे पहले विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन किए जाएंगे तथा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिसर्च संस्थानों सहित सभी संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा की जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया कि ई85 फ्यूल केवल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए शुरू किया गया है, जिन्हें विशेष रूप से इस फ्यूल के लिए डिजाइन और सर्टिफाई किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि इसका मतलब देश भर में पेट्रोल की सामान्य एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20 फीसदी से आगे बढ़ाना नहीं है। मंत्री ने बताया कि एथेनॉल का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में पिछले सौ सालों से किया जा रहा है और ब्राजील जैसे देशों में लंबे समय से अधिक एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में एथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को चरणबद्ध, वैज्ञानिक और व्यापक परामर्श प्रक्रिया के तहत लागू किया गया है। सरकार के मुताबिक वैज्ञानिक अध्ययन, फील्ड वैलिडेशन और वास्तविक उपयोग के अनुभवों से यह साबित हुआ है कि तय मानकों और वाहन निर्माता की सिफारिशों के मुताबिक इस्तेमाल किए जाने पर ई20 पेट्रोल सुरक्षित, स्वच्छ और तकनीकी रूप से बेहतर फ्यूल है। सरकार का कहना है कि यह निष्कर्ष केवल लैब रिसर्च पर नहीं, बल्कि देश भर में इसके व्यापक उपयोग के अनुभव पर आधारित है। सुरेश गोपी ने बताया कि ई15+ ब्लेंडेड पेट्रोल का देश में साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से और ई19-ई20 फ्यूल का ढाई साल से अधिक समय से उपयोग हो रहा है।

जेन-जी बातचीत पर केस खारिज- हाईकोर्ट ने कहा सुंदर कहना अपराध नहीं

बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर हुई मामूली बातचीत को लेकर दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बेंगलुरु के 20 वर्षीय कॉलेज छात्र को अपनी क्लासमेट की इंस्टाग्राम फोटो पर प्रिटी और ब्यूटीफुल कमेंट करना भारी पड़ गया था, जब लड़की के पुलिस अधिकारी पिता ने उस पर केस कर दिया था।

मामला तब शुरू हुआ जब छात्र थॉमस ने अपनी मित्र और क्लासमेट की इंस्टाग्राम पोस्ट पर उक्त कमेंट किए, जिसका जवाब लड़की ने थैंक्स कहकर दिया। यह बात यहीं खत्म हो गई होती, अगर लड़की के पिता ने इस कमेंट को न देखा होता। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते, उन्होंने छात्र के खिलाफ पुलिस स्टेशन में महिला का पीछा करने, उसकी प्राइवेसी भंग करने और आईटी एक्ट की धारा 66ई (प्राइवेसी उल्लंघन) के तहत केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने थॉमस का मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया।

इस कार्रवाई से परेशान होकर छात्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच ने छात्र की याचिका स्वीकार कर पूरे क्रिमिनल केस को तत्काल खारिज कर दिया और पुलिस को छात्र का फोन व लैपटॉप तुरंत वापस करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जेन जी (जेन-जी) की बातचीत को अपराध नहीं माना जा सकता। युवाओं के बीच निजी चैट और कॉम्प्लिमेंट को सिर्फ इसलिए आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वे आधुनिक और अनौपचारिक तरीके से बात करते हैं। कोर्ट ने लड़की के पिता को चेतावनी भी दी कि इसतरह के मामलों में केस जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जो बिना वजह छात्र के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले से सोशल मीडिया पर छोटी-मोटी ऑनलाइन बातचीत को लेकर पुलिस केस का सामना करने वाले कई युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह फैसला निजी बातचीत के संदर्भ को समझने और आपराधिक दायरे से बाहर रखने की जरूरत को रेखांकित करता है।

उत्तराखंड में इंजीनियरिंग का पेपर हुआ लीक, 377 छात्रों की परीक्षा रद्द

देहरादून। देशभर में पेपर लीक को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) में इंजीनियरिंग के दो प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया है। मामला सामने आते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इस मामले में शिवालिक कॉलेज के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रोफेसर पर आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से मिलते-जुलते सवाल एक कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किए थे। विश्वविद्यालय अधिकारियों के अनुसार, यह मामला इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों से जुड़ा है। इस महीने की शुरुआत में विश्वविद्यालय को एक ईमेल मिला था, जिसमें तीसरे वर्ष के 'मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स'विषय का पेपर लीक होने का दावा किया गया था। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आरोपी प्रोफेसर द्वारा साझा किए गए सवाल अंतिम परीक्षा के प्रश्नपत्र से 90 से 95 प्रतिशत तक हूबहू मेल खाते थे।

एनटीए में आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रहा काम, स्थाई कर्मचारी सिर्फ 24

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाएं कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह परीक्षा विवाद नहीं, बल्कि एजेंसी का स्टाफ है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि एनटीए में फिलहाल सिर्फ 24 स्थायी कर्मचारी हैं जबकि बड़ी संख्या में काम संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। यही एजेंसी नीट-यूजी, जेईई और यूजीसी-नेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाएं आयोजित करती है। केंद्र सरकार के मुताबिक एनटीए की स्थापना 2018 में हुई थी। तब से लेकर अब तक एजेंसी ने 270 से ज्यादा राष्ट्रीय परीक्षाएं आयोजित की हैं। इन परीक्षाओं के लिए 6.6 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें नीट-यूजी, जेईई मेन, यूजीसी-नेट समेत कई अहम परीक्षाएं शामिल हैं। इतने बड़े स्तर पर परीक्षाएं कराने वाली एजेंसी में स्थायी कर्मचारियों की संख्या बेहद कम होने का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि एनटीए में 39 स्थायी पद हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति के जरिए भरा जाता है हालांकि मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए पदवार आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 24 स्थायी अधिकारी ही कार्यरत हैं। इनमें स्थायी कर्मचारियों के अलावा एनटीए में बड़ी संख्या में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक एनटीए में 73 कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं। इनमें 44 कंसल्टेंट, 17 यंग प्रोफेशनल, 5 सीनियर कंसल्टेंट, 3 सलाहकार और एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर शामिल हैं।

पेपर लीक पर मोदी सरकार का बड़ा प्रहार- 1 करोड़ जुर्माना, 10 साल तक जेल

नई दिल्ली । नीट पेपर लीक विवाद के बीच, केंद्र की मोदी सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोषियों को न बख्शने के ऐलान के बाद, शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट 2024' में संशोधन के मसौदे पर विचार होगा। यह संशोधित कानून मौजूदा प्रावधानों से कहीं अधिक कठोर होगा, जिसका लक्ष्य संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर शिकंजा कसना है।

मोदी सरकार का मानना है कि जून 2024 में लागू हुआ वर्तमान कानून, जिसमें पेपर लीक, संगठित नकल, और कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ जैसे कृत्यों को अपराध माना गया है, अलग-अलग राज्यों में सक्रिय संगठित सिंडिकेट्स के खिलाफ पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। इसलिए, एक व्यापक कानूनी ढाँचे की आवश्यकता महसूस की गई है, ताकि अंतर-राज्यीय लिंक वाले पेपर लीक नेटवर्कों को जड़ से खत्म हो सके। इस पर शुक्रवार कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है और कठोर पेपर लीक कानून पर मुहर लग सकती है।

प्रस्तावित संशोधनों में दोषी साबित होने पर व्यक्तियों के लिए लंबी जेल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान शामिल है। सूत्रों के अनुसार, पेपर लीक में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने वालों को तीन से पांच साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, संगठित पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों को पांच से दस साल की जेल की सजा और करीब 1 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए ट्रायल पूरा करने के लिए अनिवार्य समय-सीमा (संभवतः एक साल या उससे कम) भी तय की जाएगी ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके।

यह सख्त कदम तब उठाया जा रहा है जब नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में छात्रों और विपक्षी दलों (जैसे सीजेपी) द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। यह प्रस्तावित बदलाव सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा शिक्षा सुधारों और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी कई मांगों पर सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपनी 26 दिवसीय भूख हड़ताल समाप्त करने के एक दिन बाद सामने आए हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इस संशोधित बिल को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है, जिससे परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित की जा सके और लाखों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।

देहरादून-नैनीताल समेत 6 जिलों में होगी झमाझम, विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

देहरादून। उत्तराखंड में मानसून फिर अपनी रफ्तार पकड़ने लगा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज विशेष रूप से देहरादून और नैनीताल जैसे संवेदनशील पर्वतीय एवं मैदानी इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी मौसम का मिजाज काफी बिगड़ सकता है। राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर पर्वतीय जिलों तक बारिश का दौर शुरू होने से तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी।

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। विभाग का स्पष्ट कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में मानसून का दौर काफी तेज रहेगा। केवल देहरादून या नैनीताल ही नहीं, बल्कि राज्य के सभी जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के बेहद तीव्र दौर आने की आशंका जताई गई है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में मानसून की गतिविधियां थोड़ी कमजोर जरूर रही थीं, फिर भी मसूरी, मुक्तेश्वर और रुड़की जैसे इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई।

शुक्रवार को उत्तराखंड के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक राज्य के देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है1 पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों के तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश के 'अति तीव्र' दौर होने का अनुमान जताया गया है।

यह केवल एक रिप्रेजेंटेशन था और लोगों ने बिना सोचे इसकी रिपोर्टिंग शुरू कर दी

-मेरा समय बर्बाद मत करो के बयान की अब सीजेआई सूर्यकांत ने बताई सच्चाई

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। बीते दिनों सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग की गई। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी काफी चर्चा में रही। सीजेआई सूर्यकांत ने तब कहा था कि उनके पास वीडियो देखने का वक्त नहीं है उनका समय बर्बाद न करें। यह बयान जब वायरल हुआ तो खुद सीजेआई सूर्यकांत ने उस टिप्पणी की सच्चाई बताई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने शुक्रवार को मीडिया से नाराजगी जताई। उनका मानना है कि उनके बयान को लेकर इस मामले में मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की।

मीडिया रिपोर्ट में बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक मीडिया की रिपोर्टिंग को गलते बताते हुए सीजेआई ने कहा कि सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े मामले में उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर ही नहीं हुई थी। सिर्फ एक प्रतिनिधित्व दिया गया था। बता दें मीडिया में यह खबर आई थी कि सीजेआई सूर्यकांत ने 22 जुलाई को एक याचिका को लिस्ट करने से इनकार कर दिया था। सीजेआई ने कहा कि मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया कि मैंने मामले को लिस्ट करने से इनकार कर दिया। यह केवल एक रिप्रेजेंटेशन था और लोगों ने बिना सोचे-समझे इसकी रिपोर्टिंग शुरू कर दी। मैंने रजिस्ट्री से पता किया और कोई भी सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ा कागज दायर नहीं किया गया था।

बता दें 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने एक मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती की थी। उन्होंने मामले को लिस्ट करने की मांग की और कहा कि पुलिस की बर्बरता के वीडियो सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा था, 'जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस बर्बर कार्रवाई कर रही हैज्' इस पर उस दिन सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था, 'हमारे पास समय नहीं है। हमारा समय बर्बाद न करें और अपना भी नहीं। इसके बाद वकील ने कहा था कि वह कुछ अहम मांगें कर रहे हैं, जिनमें सरकार की ओर से नीट का निष्पक्ष आयोजन और बार-बार पेपर लीक होने के कारण एनटीए को भंग करना शामिल है।

जब सुप्रीम कोर्ट ने अगला मामला पुकारा तो वकील ने जोर देकर कहा कि वह प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती दिखाने वाले वीडियो पेश कर सकते हैं। हालांकि, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि 'हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास देखने का टाइम नहीं है। सीजेआई की इस टिप्पणी पर खूब चर्चा हुई इसकी आलोचना भी हुई।

लाखों फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का खुलासा, सुवेंदु सरकार ने दिए जांच के आदेश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले लाखों की संख्या में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी होने का बड़ा मामला सामने आया है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने इस गंभीर धोखाधड़ी की गहन जांच के आदेश दिए हैं। ये चौंकाने वाले खुलासे तब हुए हैं जब राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों की अहम भूमिका होती है।

राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने पूरी प्रक्रिया को शुद्धिकरण अभियान करार दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों से जुड़े सभी रजिस्टर पंचायतों और नगर पालिकाओं से तत्काल जब्त करें। इन रजिस्टरों का डेटा जुटाकर अगले तीन से चार महीनों तक असली और फर्जी प्रमाणपत्रों की पहचान करने के लिए गहराई से जांच करे। एक अधिकारी ने बताया कि डेटा संकलन के बाद रजिस्टर स्थानीय निकायों को लौटा दिए जाएंगे।

मुख्य सचिव अग्रवाल के अनुसार, एक शुरुआती टेस्ट चेक में ही बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई है। जांचे गए करीब 47 हजार डिलेड बर्थ सर्टिफिकेट (देरी से बनवाए गए प्रमाणपत्र) में से 11 हजार से अधिक फर्जी मिले है। वहीं, करीब 11 लाख डिजिटाइज्ड सर्टिफिकेट्स की जांच में करीब 1 लाख 80 हजार प्रमाणपत्रों को फर्जी करार दिया है। सिर्फ दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप और दार्जिलिंग के माटीगाड़ा जैसी दो जगहों पर ही 4,000 से 6,000 इसतरह के संदिग्ध प्रमाणपत्र जारी हुए थे।

सरकारी आंकड़े खुद अप्रत्याशित उछाल की गवाही दे रहे हैं। साल 2023 में राज्य में कुल 1,21,453 जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, जो 2024 में बढ़कर 3,81,591 पर पहुंच गया। लेकिन 2025 में, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार सत्ता में थी, यह आंकड़ा अचानक बढ़कर 10,50,441 हो गया। इस बड़े फर्जीवाड़े की आशंका के मद्देनजर, सुवेंदु सरकार ने अब कड़ा कदम उठाया है और केवल अधिकृत सरकारी अधिकारियों को ही जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया है, ताकि भविष्य में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सर्वाधिक फर्जी प्रमाणपत्र मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर जैसे तीन मुस्लिम बहुल जिलों में जारी हुए हैं।

न्यूज गैलरी

तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने साइकिल सवार मजदूर को मारी टक्कर

सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के पास देर रात हुआ हादसा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरेखा स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास बीती रात तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से एक साइकिल सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर रात्रि गश्त कर रहे पुलिस कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई तथा परिजनों को सूचना देकर 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया गया।घायल व्यक्ति राजू पिता गणेश लिल्हारे 42 वर्ष वार्ड क्रमांक 7 ग्राम कोसमी थाना ग्रामीण निवासी बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कोसमी निवासी राजू मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 23 एवं 24 जुलाई की दरमियानी रात 2:30 बजे राजू आंवलाझरी से मजदूरी कर साइकिल से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के नीचे तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में राजू साइकिल सहित सड़क पर गिर गया और बेहोश हो गया।संयोगवश उसी समय क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रहे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने तत्काल घायल को संभाला। होश में आने पर राजू ने अपना नाम और पता बताया।जिसके बाद पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद 108 एंबुलेंस के माध्यम से उसे जिला अस्पताल बालाघाट भेजा गया। जहां उसका उपचार किया।जिला अस्पताल पुलिस ने घायल राजू का बयान दर्ज कर मामले को अग्रिम कार्रवाई के लिए कोतवाली भिजवा दिया है। बताया गया है कि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार थे। पुलिस मामले की जांच कर अज्ञात मोटरसाइकिल चालक और उसके साथियों की तलाश में जुटी है।

डबल मनी घोटाले में एसआईटी को बड़ी सफलता, 122 जमीनों की रजिस्ट्री और करोड़ों के दस्तावेज जब्त

रिमांड के दौरान आरोपियों के घरों से 18.61 करोड़ की संपत्तियों के दस्तावेज, 14.82 करोड़ के चेक और निवेशकों का रिकॉर्ड बरामद, अब पुलिस बनाएगी निवेशकों की एक्सेल शीट, शिकायतों के लिए अलग कंट्रोल रूम होगा तैयार

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

जिले के बहुचर्चित डबल मनी घोटाले की जांच में विशेष जांच दल (एसआईटी) को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। चार वर्षों तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार किए गए गिरोह के मास्टरमाइंड सोमेंद्र कांकरायने और उसके साथियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को करोड़ों रुपये की संपत्तियों और निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं।रिमांड के दौरान हुई कार्रवाई में आरोपियों के घरों से 122 जमीनों की रजिस्ट्री, करोड़ों रुपये के चेक, हजारों बैंकिंग दस्तावेज और निवेशकों का विस्तृत रिकॉर्ड बरामद हुआ है। इन दस्तावेजों के आधार पर अब पुलिस न केवल घोटाले की पूरी आर्थिक परतें खोलने की तैयारी में है, बल्कि निवेशकों को उनकी राशि वापस दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी में है।

शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेसवार्ता में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा और एसआईटी प्रमुख नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी ने जांच में हुई अब तक की प्रगति की जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि डबल मनी मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है, जो हर दस्तावेज और आर्थिक लेन-देन की बारीकी से जांच कर रही है। एसआईटी प्रमुख मयंक तिवारी ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी प्रद्युम्न कांकरायने, रामप्रसाद मंसुरे और दिनेश कांकरायने के घरों की तलाशी ली गई। इस दौरान प्रद्युम्न कांकरायने के कब्जे से 54 जमीनों की रजिस्ट्री बरामद हुई, जिनकी अनुमानित कीमत

लगभग 9 करोड़ 51 लाख रुपये है। वहीं रामप्रसाद मंसुरे के यहां से 68 जमीनों की रजिस्ट्री मिली, जिनकी कीमत लगभग 9 करोड़ 7 लाख रुपये आंकी गई है। इस प्रकार कुल 122 संपत्तियों की रजिस्ट्री, जिनका बाजार मूल्य लगभग 18.61 करोड़ रुपये है, पुलिस ने जब्त कर ली है। तलाशी के दौरान पुलिस को केवल जमीनों के दस्तावेज ही नहीं मिले, बल्कि डबल मनी योजना से जुड़े 617 चेक, जिनकी कुल राशि लगभग 14.82 करोड़ रुपये है, भी बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि निवेशकों को भुगतान के नाम पर चेक दिए जाते थे और उनकी फोटो कॉपी और रिकॉर्ड आरोपी अपने पास सुरक्षित रखते थे। इसके अलावा 20 रजिस्टर, 16 ऋण पुस्तिकाएं, पावर ऑफ अटॉर्नी, लगभग 1500 कोरे चेक, 59 बैंक इंस्टा किट, टैक्स एवं जीएसटी रिटर्न से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख भी जब्त किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि ये दस्तावेज डबल मनी नेटवर्क की पूरी आर्थिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बरामद रजिस्टरों में निवेश करने वाले लोगों के नाम, जमा राशि और भुगतान संबंधी विस्तृत जानकारी दर्ज है। अब एसआईटी इन सभी रिकॉर्ड का डिजिटल विश्लेषण कर रही है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि बरामद दस्तावेजों के आधार पर सभी निवेशकों की सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए एक विस्तृत एक्सेल शीट बनाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक निवेशक का नाम, निवेश की राशि और संबंधित दस्तावेजों का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके बाद निवेशकों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ताकि उनकी वास्तविक राशि का सत्यापन कर आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत पैसा वापस दिलाने की कार्रवाई शुरू की जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसके लिए अलग से सहायता कक्ष स्थापित किया जाएगा। शिकायत दर्ज कराने वाले निवेशकों को भीड़ से बचाने और प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए उन्हें स्लॉट के आधार पर बुलाया जाएगा। इसके लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर और पंजीयन व्यवस्था भी शुरू करेगी, जिससे प्रतिदिन लगभग 50 से 100 निवेशकों की शिकायतें सुनकर उनका सत्यापन किया जा सके। एसपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल आरोपियों को गिरफ्तार करना नहीं है, बल्कि जिन लोगों की जीवनभर की कमाई इस घोटाले में फंसी है, उन्हें न्याय दिलाना भी है। उन्होंने कहा कि जब्त की गई रजिस्ट्रियों और अन्य संपत्ति संबंधी दस्तावेजों का भी सार्वजनिक सत्यापन कराया जाएगा, ताकि यदि किसी निवेशक की राशि से खरीदी गई संपत्ति का संबंध सामने आता है तो उसे भी जांच में शामिल किया जा सके।

28 वर्षीय युवक ने किया यूरिया खाद का सेवन

जिला अस्पताल में भर्ती

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम खोड़सिवनी में एक 28 वर्षीय युवक परदेशी सिंघनधुपे के द्वारा यूरिया खाद का सेवन किए जाने का मामला सामने आया है। युवक की हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया। जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खोड़सिवनी निवासी परदेसी सिंघनधुपे अपने परिवार के साथ खेती किसानी का कार्य करता है। 24 जुलाई की सुबह परदेशीअपने चाचा दिनेश सिंघनधुपे के साथ खेत में कृषि कार्य करने गया था। दोपहर करीब 1 बजे परदेसी खाना खाने के लिए घर जाने की बात कहकर खेत से निकला।लेकिन काफी देर तक वह घर से खेत वापस नहीं लौटा।इस पर उसके चाचा दिनेश घर पहुंचे तो देखा कि परदेसी बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रही थी तथा पास में यूरिया खाद की खुली बोरी रखी थी।परदेशी के मुंह से यूरिया खाद की दुर्गंध भी महसूस हुई। इसके बाद उसे तत्काल निजी वाहन से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया गया।फिलहाल युवक द्वारा यूरिया खाद का सेवन किन कारणों से किया गया। इसका पता नहीं चल सका है। जिला अस्पताल पुलिस ने युवक के चाचा दिनेश सिंघनधुपे के बयान दर्ज कर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित हट्टा थाना भेज दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आवश्यकता है

कम्प्यूटर आपरेटर की आवश्यकता है

शैक्षणिक योग्यता-हिंदी व अंग्रेजी टायपिंग का ज्ञान अनिवार्य
वेतनमान - 6000 रूपये से योग्यतानुसार

-मिलने का पता-
अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल
वार्ड नं. 14 गंगोत्री कालोनी वारासिवनी
सम्पर्क सूत्र-9584968038

आवश्यकता है

क्वार्क में पेज सेटिंग हेतु कम्प्युटर ऑपरेटर की आवश्यकता है

संपर्क करें-बालाघाट एक्सप्रेस
पद्मेश सिटी केबल, काली पुतली चौक, बालाघाट

पट्टे की शर्तों के उल्लंघन पर कलेक्टर की बड़ी कार्वाई, मिनिस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसायटी का पट्टा निरस्त

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बालाघाट बस स्टैंड क्षेत्र स्थित नजूल भूमि पर पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के मामले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मृणाल मीना ने सख्त कार्रवाई करते हुए दी मिनिस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसायटी मर्यादित, बालाघाट को आवंटित पट्टा निरस्त कर दिया है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा 20 जुलाई 2026 को पारित आदेश के अनुसार संबंधित भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने तथा भूमि पर शासन का आधिपत्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बस स्टैंड बालाघाट क्षेत्र स्थित नजूल शीट क्रमांक-306, प्लॉट क्रमांक-277/3 की 122.075 वर्गमीटर (1314 वर्गफुट) भूमि सोसायटी को केवल कैंटीन संचालन के उद्देश्य से पट्टे पर आवंटित की गई थी। लेकिन जांच में पाया गया कि सोसायटी द्वारा स्वीकृत प्रयोजन के विपरीत इस भूमि पर व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा था, जो पट्टे की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। नजूल अधिकारी के प्रतिवेदन एवं राजस्व निरीक्षक के स्थल निरीक्षण में यह भी सामने आया कि सोसायटी ने भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की। साथ ही निर्माण शुरू करने से पहले नजूल विभाग से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) नहीं लिया गया। नगरपालिका से भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करते समय भी पट्टे की शर्तों के उल्लंघन संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए। जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित भूमि पर कैंटीन का संचालन नहीं किया जा रहा था और न ही सोसायटी अपने पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कोई गतिविधि संचालित कर रही थी। प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए सोसायटी को कारण बताओ सूचना जारी कर स्पष्टीकरण एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सोसायटी के अध्यक्ष ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष भी रखा, लेकिन समस्त अभिलेखों एवं तथ्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने पाया कि पट्टे की शर्तों का गंभीर एवं लगातार उल्लंघन हुआ है। इसके आधार पर पट्टा निरस्त करने की कार्रवाई को न्यायोचित माना गया। कलेक्टर न्यायालय ने आदेश में संबंधित भूमि पर चल रहे समस्त निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा भूमि पर शासन का कब्जा नियमानुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति पालनार्थ नजूल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालाघाट, तहसीलदार बालाघाट एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी बालाघाट को भेज दी गई है।

इलाज कराने निकली 20 वर्षीय युवती रहस्यमय ढंग से लापता

किरनापुर पुलिस ने शुरू की तलाश

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। किरनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसाटोला की 20 वर्षीय युवती मीनाक्षी देवे रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है। युवती इलाज कराने के लिए किरनापुर अस्पताल जाने घर से निकली थी।लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर किरनापुर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीनाक्षी देवे ने कक्षा 12वीं तक शिक्षा प्राप्त की है। उसका परिवार खेती-किसानी से जुड़ा है तथा उसका एक छोटा भाई भी है। 21 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे मीनाक्षी घर से यह कहकर घर से निकली थी कि वह इलाज कराने किरनापुर अस्पताल जा रही है। इसके बाद वह वापस घर नहीं पहुंची।परिजनों ने पहले गांव, आसपास के क्षेत्रों और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश किये। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मामले की सूचना किरनापुर थाना में दी गई। पुलिस ने गुम इंसान क्रमांक 63/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।लापता युवती का रंग सांवला, कद लगभग 5 फीट, चेहरा गोल है। घर से निकलते समय उसने जामुनी रंग का सलवार सूट पहन रखा था।किरनापुर पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि यदि किसी को मीनाक्षी देवे के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा किरनापुर थाना को सूचित करें, ताकि उसे सकुशल परिजनों तक पहुंचाया जा सके।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :**9425138710**, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट